हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 2021 (प्रथम बैठक)

खण्ड–1, अंक–8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 16 मार्च, 2021

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्थगन

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

प्रदर्शनकारियों के सम्बन्ध में मामला उठाना

वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

हरियाणा विधान सभा
मंगलवार, 16 मार्च, 2021 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Depleting Level of Ground Water

***893. Smt. Nirmal Rani:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the level of ground water is depleting due to misuse of water from submersibles installed in villages of District Sonipat; if so, the steps taken or likely to be taken by the Government to check the abovesaid problem?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां श्रीमान जी, यह एक तथ्य है कि ट्यूबवैल (Submersible) के माध्यम से भूमिगत जल के अत्याधिक दोहन के कारण सोनीपत जिले में भूमिगत जल घट रहा है।

श्रीमती निर्मल रानीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि फिर से भूमिगत जल न घटे, इसके लिये हम कौन–कौन से कदम उठायें? किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कृपया करके माननीय मंत्री जी यह बात भी सदन को बतायें।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जल के मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई हुई है। हमारी सरकार ने वॉटर रिचार्जिंग की बहुत स्कीम्ज बनाई हैं। हरियाणा राज्य अधोभूमि जल संरक्षण अधिनियम, 2009 लागू किया है। अत्याधिक जल की आवश्यकता न हो इसके लिये प्रदेश में धान की फसल की बुआई को कम करने की कोशिश भी जारी है ताकि ड्रिप इरिगेशन पर पानी रहे। धान की फसल की बुआई न करने वाले किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। प्रदेश में स्प्रिंकलर्स सिंचाई की योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसी तरह फसलों की विविधिकरण के लिये पूरी स्कीम्ज बनाई हैं। जिसमें धान की फसल की बुआई न करने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने इस संबंध में अपनी एक अथॉरिटी बनाई हुई है जो कहां पर डार्क जोन घोषित हो, कहां पर भूमिगत जल के अत्याधिक दोहन करने दे, कहां पर न करने दे आदि की मैपिंग करेगी। सरकार पूरी एग्रेसिव होकर इस मामले में काम कर रही है। यह बात सही है कि हरियाणा

@ Reply given by the Agriculture & Farmers Welfare Minister

में पानी की समस्या है लेकिन हमारी सरकार हमारे जल के जो संसाधन हैं उनका सही बंटवारा हो ऐसी स्कीम्ज को लेकर काम कर रही है।

श्रीमती निर्मल रानीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ।

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पिपली और बबैन दोनों ब्लॉक में पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार की तरफ से धान की फसल की बुआई पर बैन लगाने से लगभग 3000 हजार एकड़ पंचायत की जमीन खाली भी पड़ी हुई है। सरकार ने बोरवेल की स्कीम शुरू कर रखी है और उसकी गहराई 150–160 फीट तक की है, इसकी गहराई 300–350 फीट की जाये ताकि सरकार की बोरवेल की स्कीम कामयाब हो जाये क्योंकि यह स्कीम ज्यादा समय तक नहीं चल पायेगी।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बहुत सारे बोरवेल लगवायें हैं। जिस क्षेत्र में बोरवेल लगाते हैं, उस क्षेत्र में पानी का लेवल देखा जाता है क्योंकि किसी क्षेत्र में 50–60 फीट की गहराई पर पानी उपलब्ध है और किसी क्षेत्र में 300–400 फीट की गहराई पर पानी उपलब्ध होता है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी हम माननीय सदस्य के सुझाव पर जरूर विचार करेंगे।

.....

To Develop HSVP Sectors

***762. Shri Mamman Khan**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the districts of State in which sectors have been developed by HSVP; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop HSVP sectors at head quarter Nuh, Ferozepur-Jhirka and Punhana in District Nuh; if so, the time by which the said HSVP sectors are likely to be developed?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) हां, श्रीमान् जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में सैक्टर विकसित किये गये है (विवरण अनुलंग्नक 'ए' पर संलग्न है)।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी। ऐसी कोई प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

@ Reply given by the Agriculture & Farmers Welfare Minister

विवरण

अनुलंग्नक–ए

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जिले का नाम	शहरी सम्पदा का नाम
1.	फरीदाबाद	फरीदाबाद	फरीदाबाद
		पलवल	हथीन
			पलवल
		नूंह	तावडू
			रोजका मिओ
2.	गुरूग्राम	गुरूग्राम	गुरूग्राम
			पटौदी
		रेवाड़ी	रेवाड़ी
			धारूहेडा
			कोसली
		महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
			नारनौल
3.	हिसार	हिसार	हिसार
			हांसी
			आदमपुर मंडी टाउनशिप
		चरखी दादरी	चरखी दादरी
		फतेहाबाद	फतेहाबाद
			भट्टु मंडी टाउनशिप
		भिवानी	भिवानी
		जींद	जींद
			सफीदों
		सिरसा	सिरसा
			डबवाली
4.	पंचकुला	पंचकुला	पंचकुला –एमडीसी
			पिंजौर–कालका
		अम्बाला	अम्बाला
			नरायणगढ़
		यमुनानगर–जगाधरी	यमुनानगर–जगाधरी
		कैथल	कैथल
		करनाल	करनाल
			घरौंडा
			तरावडी
		कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र
			पेहवा
			शाहबाद
5.	रोहतक	रोहतक	रोहतक
			सांपला
		झज्जर	झज्जर
			बहादुरगढ़
		पानीपत	पानीपत
		सोनीपत	सोनीपत
			गोहाना
			गन्नौर

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 22 जिले हैं और 21 जिलों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों को विकसित किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि नूंह जिले को कंट्रोल्ड एरिया कब घोषित किया गया था कब इसकी अधिसूचना जारी हुई थी? और अधिसूचना जारी होने के बाद क्यों सेक्टर विकसित नहीं किये गये? इन सभी बातों का माननीय मंत्री जी सदन में जवाब दे।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हर जिले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा डिवैल्प किए गये सेक्टर्ज हैं। माननीय सदस्य ने जिन सवालों के जवाब मांगे हैं, मैं उनका लिखित में जवाब माननीय सदस्य को बाद में भिजवा दूंगा। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि नूंह जिले के तावडू में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा सेक्टर डिवैल्प किया जा रहा है।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तावडू का जिक्र किया है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नूंह शहर के इर्द–गिर्द के गांव को मिलाकर कंट्रोल्ड एरिया पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बधन अधिनियम 1963 (एक्ट–नंबर 41) की धारा–4 के तहत अधिसूचना दिनांक 2.09.1981 तथा अतिरिक्त कंट्रोल्ड एरिया दिनांक 28.03.2019 को जारी की गई थी । इसके बाद लगभग 25 वर्ष उपरांत नूंह का प्रारूप विकास प्लान 2021 ए.डी. दिनांक 18.09. 2006 को प्रकाशित हुआ जिसमें 13 सैक्ट्र्स को विकसित करने का प्रावधान किया गया था । रिवाइज्ड प्रारूप विकास प्लान नूंह 2021 ए.डी. दिनांक 11.01.2009 को प्रकाशित हुआ था । इसका अंतिम विकास प्लान दिनांक 2.07.2019 को प्रकाशित हुआ परन्तु 40 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी वहां आज तक एक भी सैक्टर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नहीं किया गया है । इसी तरह से फिरोजपुर–झिरका का मामला है । इसी प्रकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा फिरोजपुर–झिरका शहर के इर्द–गिर्द के गांव को मिलाकर कंट्रोल्ड एरिया पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बधन अधिनियम 1963 (एक्ट–नंबर 41) की धारा–4 के तहत अधिसूचना दिनांक 29.01.1982 को जारी की गई थी । लगभग 40 वर्ष उपरांत फिरोजपुर–झिरका का प्रारूप विकास प्लान 2021 ए.डी. दिनांक 24.03.2009 को प्रकाशित हुआ जिसमें 8 सैक्ट्र्स को विकसित करने का प्रावधान किया गया था । इसका रिवाइज्ड प्रारूप विकास प्लान नूंह 2021 ए.डी. दिनांक 28.03.2018 को प्रकाशित हुआ और अंतिम विकास प्लान दिनांक 11.01.2019 को प्रकाशित हुआ । कंट्रोल्ड एरिया घोषित हुए 40 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी आज तक वहां भी एक भी सैक्टर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नहीं किया गया है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मामन जी, आप माननीय मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा तावडू में सैक्टर काटने के विषय में एक बात कहना चाहता हूं । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर 7, 8 व 11 को विकसित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2012–13 में किया गया था । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक इन सैक्ट्र्स को विकसित क्यों नहीं किया गया ?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नूँह की आबादी 25000 थी । उसके अनुसार नूँह में सैक्ट्र्स काटने का प्रावधान किया गया था । सैक्ट्र्स के लिए हमने जमीन भी अधिग्रहित कर ली थी लेकिन सैक्ट्र्स काटने वहीं पर वायबल होते हैं जहां पर ग्राहक लेने के लिए तैयार हों । वहां पर सैक्ट्र्स के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया था उस जमीन पर प्लॉट्स काटने के लिए विभाग ने रेट तय किया था । उस रेट पर प्लॉट बेचने के लिए विभाग ने एक सर्वे करवाया था । सर्वे में वह रेट वायबल नहीं पाया गया क्योंकि लोग उस रेट पर प्लॉट लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वहां पर सैक्ट्र्स काटने का मामला आज तक पैंडिंग है ।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा पुन्हाना शहर के इर्द–गिर्द के गांव को मिलाकर कंट्रोल्ड एरिया पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बधन अधिनियम 1963 (एक्ट–नंबर 41) की धारा–4 के तहत अधिसूचना दिनांक 27.07.2010 को जारी की गई थी परन्तु आज तक कोई भी मास्टर प्लान प्रकाशित नहीं किया गया है । ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि मेवात जिले में सैक्ट्र्स क्यों नहीं काटे जा रहे हैं ? मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि वहां पर एक बार सैक्ट्र्स काटकर तो देखें । वहां पर ग्राहक भी जरूर आयेंगे । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं । मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि हमारे जिले को इतना मत पिछाड़िये । वहां पर सैक्ट्र्स अवश्य कटवाइये । हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने जिले में सैक्ट्र्स कटवाने के लिए डिमांड कर रहे हैं और इसी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद भी हाथ उठा रहे हैं । सरकार ने नूँह जिले में आने वाले लगभग सभी विधान सभा क्षेत्रों में सैक्ट्र्स के लिए लैण्ड एक्वायर की हुई है लेकिन वहां पर वायबिलिटी के विषय की वजह से सैक्ट्र्स नहीं काटे गये ।

इसमें हम एक काम कर सकते हैं । हम सैक्ट्र्स काटे बगैर वहां की वायबिलिटी के हिसाब से रेट निकालकर 'एक्सप्रैशन ऑफ इंट्रस्ट' मांग लेते हैं कि इस रेट पर कौन–कौन प्लॉट खरीदने का इच्छुक है । यदि सैक्ट्र्स में प्लॉट्स की कुल संख्या के 50 परसैंट लोगों ने भी प्लॉट खरीदने की इच्छा जताई तो हम वहां पर प्लॉट काट देंगे ।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस प्रस्ताव से सहमत हैं ।

चौधरी आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसी विषय पर एक सप्लीमैंट्री पूछने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आफताब जी, इस प्रश्न पर पहले ही तीन सप्लीमैंट्री पूछे जा चुके हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप माननीय मंत्री जी के पास लिखित में भेज सकते हैं।

————————

To Reconstruct /Upgrade Hospital

***1071. Shri Sudhir Singla:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the old General Hospital in Gurugram is in dilapidated condition; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the said Hospital by upgrading it up to 500 beds; and

(b) if so, the time by which the reconstruction / upgradation work of said hospital is likely to be completed?

@स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) हां श्रीमान जी, पुराना नागरिक अस्पताल गुरूग्राम जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। उपरोक्त अस्पताल को 500 बिस्तरीय में अपग्रेड करते हुये पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) निर्माण कार्य सभी आवश्यक तौर–तरीकों के पूरा होने और सभी आवश्यक अनुमोदनाएं प्राप्त करने के उपरान्त शुरू होगा।

@ Reply given by the Co-operative Minister

श्री सुधीर सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में पिछले सैशन के दौरान भी क्वैश्चन पूछा था और उसके रिप्लाई में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस कार्य को मार्च तक शुरू करवा देंगे, लेकिन वह कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ? अगर कोई बिल्डिंग टूट जाए तो नयी बनानी पड़ती है। चूंकि वह बिल्डिंग टूटी नहीं है।

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि संबंधित रिक्वायरमैंट्स की एप्रूवल आने के बाद जल्दी ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री सुधीर सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कौन सी एप्रूवल बाकी रह गयी हैं ? इसमें तो संभवतः सभी एप्रूवल्ज आ चुकी हैं ?

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी डिपार्टमैंट्स की तरफ से सभी एप्रूवल्ज नहीं आयी हैं। जब सभी एप्रूवल आ जाएंगी तो संबंधित कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री सुधीर सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय मंत्री जी टैंटेटिवली टाईम बता दें कि संबंधित कार्य कब तक शुरू हो जाएंगे और कौन– कौन सी एप्रूवल्ज आ गयी हैं ?

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जल्दी ही संबंधित कार्य शुरू करवा देंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य ने जो बातें पूछी हैं, उनका पूरा रिप्लाई भिजवा दें। माननीय सदस्य गुरूग्राम के हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहे हैं कि वहां पर कितने वर्क्स की सैंक्शन आ चुकी हैं और कितनी आनी बाकी हैं ? आप कह रहे हैं कि ये कार्य मार्च में शुरू हो जाएंगे।

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग की तरफ से उनके पास सभी जानकरियों का रिप्लाई बाद में भिजवा दिया जाएगा।

———————

To provide Grant of Rupees 5 Crore

***883. Smt. Shailly:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister in the year 2020 to provide grant of rupees 5 crore to each legislature for the development works in their Constituency but a small amount has been released by the Government under abovesaid announcement so far; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to release full amount under above- said announcement?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): An announcement was made by CM on 20.12.2019 (CM CODE 25284) that each member of constituency can recommend Development works in his/her assembly constituency to the extent of Rs. 5 crore. Accordingly, till date development works have been sanctioned amounting to Rs. 239.03 crore. Government is committed to the fulfillment of the announcement over time. The onset of covid-19 pandemic and the general understanding on development expenditure during the early part of financial year 2020-21 has staggered the release of funds for the fulfillment of the announcement.

श्रीमती शैली: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि अभी तक 2.39 करोड़ रुपये के वर्क्स सैंक्शन हुए हैं और आज उन बातों को सवा साल का समय व्यतीत हो चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि यह पैसा कब तक मिलेगा, कब तक वर्क्स शुरू हो जाएंगे और बाकी पैसे कब तक मिल जाएंगे?

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पिछली बार हमारी सरकार ने बजट सैशन के दौरान सभी माननीय सदस्यों को अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों के लिए विधायक निधि के तहत 5–5 करोड़ रुपये की ग्रान्ट यूटिलाईज करने की घोषणा की थी। हमारे पास माननीय सदस्या की तरफ से डिवलैपमैंट वर्क्स के ऐस्टिमेट बनकर आये थे और उनमें से 2,39,03000

रुपये के वर्क्स फिजिबल थे। जिनको सैंक्शन कर दिया है। जैसे ही बैलैंस वर्क्स फाईल पर पुट अप हो जाएंगे तो हम उनको भी सैंक्शन कर देंगे।

श्रीमती शैली: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें संबंधित वर्क्स के लिए जल्दी से जल्दी बजट दिया जाए। बजट तो सैंक्शन हो जाते हैं, परन्तु पैसे आने में समय लगता है। अभी तक संबंधित वर्क्स का पैसा नहीं आया है। मैं बाकी वर्क्स के ऐस्टिमेट भी जल्दी भिजवा दूंगी। मैं सरकार से उम्मीद करती हूं कि संबंधित वर्क्स का पैसा जल्दी मिल जाएगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इनके जिले की ट्रेजरी में आलरेडी अमाउंट पड़ी हुई है और उसके लिए माननीय सदस्या अपने डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिशनर से कॉआर्डिनेट कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता दें और मैं उसके लिए एक कमेटी कांस्टीच्यूट करके संबंधित कार्य को एक्सपीडियसली करवा दूंगा। इसके अतिरिक्त 7 माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 5 करोड़ रुपये की ग्रान्ट में से एक पैसे का भी अस्टिमेट बनवाकर नहीं भेजा है। इसमें मुख्यतः दादरी, बेरी, इसराना, नारनौंद, पंचकुला, रेवाड़ी और रोहतक शामिल हैं। इसमें पंचकुला तो वैकेट है। मैं इन सभी 6 हल्कों के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी अपनी डिमांड के ऐस्टिमेट बनवाकर पुट अप करें ताकि हम वे फंड्ज रिलीज कर सकें।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन 6 हल्कों में मेरा इसराना हल्का भी शामिल है ?

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इन 6 हल्कों में इसराना भी शामिल है। अभी तक माननीय सदस्य की तरफ से कोई भी ऐस्टिमेट बनवाकर नहीं भेजा गया है।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैं 3 बार वर्क्स के ऐस्टिमेट बनवाकर भेज चुका हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वे इसके लिए संबंधित जिले के डिप्टी कमिशनर से कन्टैक्ट करें।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए पहले सभी माननीय सदस्य अपने–अपने जिलों के डिप्टी कमिशनर्ज से कन्टैक्ट कर लें।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं उनके पास संबंधित वर्क्स के ऐस्टिमेट की फाईल्ज दोबारा भिजवा दूंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ठीक है। माननीय सदस्य संबंधित वर्क्स के ऐस्टिमेट की फाईल्ज भिजवा दें।

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने डिवलैपमैंट वर्क्स पर रोक लगायी हुई है और इसके बारे में सरकार द्वारा लैटर भी जारी किया हुआ है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो लैटर जारी किया गया था वह पंचायत के वर्क्स रोकने के बारे में था। यानी वह लैटर विधायकों के वर्कस रोकने के बारे में नहीं था।

———————

To Shift the Electricity Line

***770. Shri Balbir Singh**: Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the 33 KV Panipat-Safidon electricity line is passing over the Shiv Gaushala constructed in Matloda-Nara of Israna Assembly Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the said electricity line towards railway track togetherwith the time by which it is likely to be shifted?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): (क) 33 किलोवाट मतलौडा–नारा लाइन इसराना विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के मतलौडा–नारा में निर्मित शिव गऊशाला के ऊपर से गुजर रही है।

(ख) उक्त बिजली लाइन को शिफ्ट करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। शिव गऊशाला ने राईट ऑफ वे की उपलब्धता एवं अनुमानित राशि जमा करवाने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की है। अनुमानित राशि जमा करवाने के बाद इस लाइन की शिफ्टिंग दो महीनों के अन्दर पूरी की जाएगी।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री और सरकार को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के इसराना के गांव नारा और मतलौडा में एक शिव गऊशाला है, उसमें लगभग 1800 गायें हैं। इस गऊशाला के ऊपर से 33 किलोवाट की बिजली की लाइन गुजरती है। वहां लोहे के पोल लगे हुए हैं और बिजली की तारें भी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, जिसके कारण कई बार हादसे होने की बातें भी सामने आई हैं लेकिन कोई जान–माल का नुक्सान नहीं हुआ है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस गऊशाला के दूसरी साइड में रेलवे लाइन है वहां पर पंचायत की जमीन है इसलिए इस गऊशाला को पंचायत की जमीन पर बनाने की कृपा की जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि जैसे कई जगहों पर जैसे भवनों में, चौपालों में, गऊशालाओं में, आश्रमों में और अन्य जगहों में बिजली की तारें पुरानी हो चुकी हैं, उनको बदलने की बहुत जरूरत है। इन तारों पर होने वाला खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां के लोग इन तारों को नहीं बदलवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि पूरे प्रदेश में जिन मकानों के ऊपर से, भवनों के ऊपर से और चौपालों के ऊपर से बिजली की हाइटेंशन तारें गुजरती हैं, उनको सरकार अपने खर्चे से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करवाया जाये। हमारे प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या ज्यादा है। आपको भी पता है कि बी.पी.एल. परिवार के लोग अपने मकान किन हालातों में बनाते हैं, यह बात पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। जिसके कारण उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इन बिजली की तारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि कम से कम जो बी.पी.एल. परिवार हैं या दूसरी धार्मिक संस्थाएं हैं। इन मकानों के ऊपर से जो बिजली की हाइटेंशन तारें गुजरती है उन बिजली की तारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सरकार इस खर्चे को स्वयं वहन करें।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने एक सवाल नहीं 10 सवाल पूछे हैं। इन्होंने मतलौडा और नारा में निर्मित शिव गऊशाला के बारे में सवाल पूछा है तो मैं इस सवाल के जवाब में यही बताना चाहूंगा कि शिव गऊशाला की कमेटी ने इसके लिए पैसा जमा करवाने के लिए हां भर दी है। उन्होंने इस पर अपनी सहमति दी है और जैसे ही हमारे पास इसका पैसा आ जायेगा हम उन बिजली की तारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम शुरू कर देंगे। अब मैं माननीय सदस्य को दूसरे सवाल के बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ लोग पैसा भरने की स्थिति में नहीं है तो उनके लिए सरकार ने अब तक अमूमन 109 करोड़ 48 लाख रुपये खर्च किये हैं। जिन लोगों के मकान लाल डोर में आते हैं उनमें बिजली की तारें बदलने का काम ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां बिजली की तारों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि काफी बड़े पावर की लाइनें हैं। हमें एक दो जगह पर इस प्रकार की

समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर पहले बिजली की बड़े पावर की लाइनें निकली हुई थी वहां पर लोगों के प्लॉट थे। इसके बावजूद भी लोगों ने इन तारों के नीचे अपने मकान बना लिये। हमें इस तरह की जगहों पर थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है परन्तु विभाग की टीम द्वारा लगातार सर्वे भी किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां पर पुरानी तारें होंगी वहां तो बिजली की तारें बदल दी जायेंगी और पूरे हरियाणा प्रदेश में पुरानी तारों को बदलने का काम चल रहा है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई और विषय है तो वह भी मेरे संज्ञान में लाया जाये ताकि उस पर भी काम करवाया जा सके।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कोविड–19 आने के कारण गऊशालाओं में दान बहुत कम आया है। जिसके कारण गऊशाला की कमेटी के पास इतने पैसे नहीं है इसलिए सरकार के खर्चे पर यह काम करवा दिया जाये तो सरकार की बहुत मेहरबानी होगी। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद भी करता हूं।

———————

To Reduce the Pollution

***744. Shri Neeraj Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the 60 Feet Air Force road was identified as a hotspot by Central Pollution Control Board, if so, the steps taken by the Government to prevent the pollution and to remove the said area from the said hotspot; and

(b) Whether the level of pollution has been reduced due to the steps taken by the Government so far, if so, the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) हाँ, श्रीमान जी, प्रदूषण को कम करने के लिए और क्षेत्र में अति क्षेत्र (हॉटस्पाट) को साफ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा ब्यान में दिया गया है।

(ख) हाँ, श्रीमान जी, नगर निगम फरीदाबाद ने क्षेत्र से ठोस अपशिष्ट को हटा दिया

@ Reply given by the Education Minister

है और नगर निगम प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र की सफाई कर रहा है और ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा कर रहा है।

ब्यौरा

सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण में अति क्षेत्र के रूप में चिह्नित वायु सेना मार्ग फरीदाबाद में प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के लिए, फरीदाबाद के जिला प्रशासन, नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0 एस0 पी0 सी0 बी0), और अन्य एजेंसियों व विभागों के माध्यम से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: –

(i) जिला प्रशासन और सभी संबंधित हित धारकों के परामर्श से फरीदाबाद शहर में वाहन उत्सर्जन सहित वायु प्रदूषण के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। नगर निगम फरीदाबाद के द्वारा नियमित रूप से कूड़ा करकट /ठोस अपशिष्ट की सफाई की जा रही है।

(ii) राज्य सरकार चिन्हित किए गए मुख्य स्थानों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण/ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना (जी0 आर0 ए0 पी0) के तहत जारी किए गए निर्देशों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू कर रही है।

(iii) फरीदाबाद जिले में विभिन्न उच्च प्रदूषण वाले उद्योगों, संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयत्र (सी0 ई0 टी0 पी0), संयुक्त खतरनाक अपशिष्ट व जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं को अनुपालन की स्व निगरानी के बारे में वायु उत्सर्जन और औद्योगिक बहिस्राव पर ऑनलाइन निगरानी संयत्र लगाने के लिए निर्देशित किया गया हैं और फरीदाबाद जिले में 101 इकाइयों ने इसे लगा लिया है और जिसका ऑनलाइन डेटा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है और आंकड़े वास्तविक समय में प्रदर्शित हो रहे है।

(iv) फरीदाबाद जिले में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित 05 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0) के माध्यम से की जाती है, जिसके माध्यम से परिवेशी वायु

गुणवत्ता की वास्तविक समय के आधार पर निरंतर निगरानी की जा रही है और यह ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच के लिए उपलब्ध है। अद्ध हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से वायु और जल प्रदूषण इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और संचालन और पर्यावरणीय प्रदूषण के निर्वहन के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण कर रहा है। नियमित रूप से अनिवार्य निरीक्षणों के अलावा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विशेष निरीक्षण भी कर रहा है, जहां भी उसे प्रदूषण के खिलाफ उपयुक्त निर्दिष्ट माध्यम से शिकायतें मिलती हैं, और निरीक्षण के संचालन के लिए न्यायालय या प्राधिकरण के निर्देश प्राप्त होते हैं।

(vi) फरीदाबाद में वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले सहित हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(vii) फरीदाबाद जिले सहित हरियाणा राज्य में वायु उत्सर्जन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, जिन भी ईंट भट्टों ने जिग –जैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तित नहीं किया है उन्हें चलाने की अनुमति नहीं है।

(viii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरीदाबाद जिले सहित पूरे हरियाणा राज्य में बहने वाली नदियों और नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।

(ix) राज्य सरकार ने निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए और खुले खेतों में कृषि अपशिष्टों और अवशेषों और अन्य कचरे को जलाने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

(x) राज्य सरकार लोगों को संवेदीकरण के लिए मल्टीमीडिया के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता पैदा कर रही है और लोगों की भागीदारी बढ़ रही है।

(xi) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फरीदाबाद जिले सहित पूरे हरियाणा राज्य में ईंधन के रूप में भट्ठी के तेल (फरनेस ऑयल) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा

दिया है। इसी तरह चूने–भट्टों और सीमेंट संयंत्रों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए पैट कोक के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(xii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरूग्राम और फरीदाबाद जिले की वायु प्रदूषण से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान के लिए गुरूग्राम में 24x7 नियन्त्रण क़क्ष की स्थापना की है।

(xiii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फरीदाबाद जिले सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाले जिलों में अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता निगरानी शुरू की है।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि एम.सी. मेहता वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है । मैंने पर्टिकुलर रोड का क्वैश्चन लगाया है कि 60 फीट एयरफोर्स रोड की हॉटस्पॉट के रूप में पहचान की गई थी। शायद माननीय मंत्री जी ने जवाब देने से पहले इस प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा है और पूरे फरीदाबाद के बारे में इस क्वैश्चन में चर्चा की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने एयरफॉर्स रोड पर प्रदूषण कम करने के लिए एक भी कदम उठाया है? माननीय मंत्री जी के पास प्रदूषण कम करने के लिए कोई सुझाव नहीं है तो मैं बता सकता हूं।

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, जिस रोड की बात माननीय सदस्य ने कही है उस पर हमने 40 सफाई कर्मचारी लगाये, उस पर हमने पांच रिक्शा लगाये, एक बुल मशीन लगाई, एक जे.सी.बी. लगाई, पांच कूड़ा उठाने वाले व्हीकल लगाये और 10 मोटर वाहन युक्त हैल्पर लगाये हैं।

श्री नीरज शर्मा : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी को उस रोड की आज की फोटो दिखाना चाहता हूं। इसी रोड के सम्बन्ध में मेरा कल प्रश्न भी था। मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि इस रोड पर कूड़े का ढ़ेर लगा हुआ है। मैंने वहां पर पार्क की प्रपोजल दी। अगर वहां पर पार्क भी नहीं बनाया जा सकता तो वहां पर पेड़ ही लगा दिये जायें। यह सड़क केवल मात्र मेरी विधान सभा की नहीं है बल्कि यह सड़क फरीदाबाद की तीन विधान सभाओं को टच करती है। जो मैं यहां पर कागज दिखा रहा हूं यह भी मेरा कागज नहीं है बल्कि यह कागज केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कागज है। मंत्री जी को इस विषय की गम्भीरता को समझना चाहिए। मैं

वायु प्रदूषण की बात कर रहा हूं कि वहां पर एयर के अंदर प्रदूषण का लैवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिससे वहां के निवासियों में कैंसर की बीमारी भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर वहां पर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो जायेगी। मैं मंत्री जी से अंतिम बार एक बात कह रहा हूं कि ये मेरे कुछ सुझाव है और सरकार मुझे आश्वासन दे कि मेरे सुझावों को माना जायेगा। इस सडक पर हवाई अड्डा है और देश की सुरक्षा और देश के वीर सैनिकों से बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं होती है। इस सड़क पर ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं यह मांग करता हूं कि जो हमारे 60 फीट रोड पर डिस्पोजल है इसकी क्षमता बढ़ाई जाये। आधे समय यह खराब रहता है। अगर इसकी क्षमता को बढ़ाया जायेगा तो वहां पर सीवरेज सिस्टम ब्लॉक नहीं होगा। दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि इसी रोड पर श्मशान घाट है वहां पर बिजली से जो क्रिमेशन होता है उसकी मशीनें बंद पड़ी हैं उनको चालू करवाया जाये। जो भी लोग लकड़ी के स्थान पर बिजली से क्रिमेशन करना शुरू करेंगे उससे भी वहां पर प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा सब्जी मण्डी के पास जमीन खाली पड़ी है उस जमीन पर भी पार्क बनाया जा सकता है या फिर वहां पर पेड़ लगाये जा सकते हैं। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नवादा भाखड़ी एरिया में एल्युमिनियम की भट्ठियां, रबड़ की फैक्ट्रियां और गैस के चूल्हे की ऐसी–ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रदूषण निकलता है। उस प्रदूषण से कैंसर होता है। सरकार या तो उन सभी फैक्ट्रियों को बंद करवाये, उन्हें कहीं और शिफ्ट करवाये या फिर वे सभी प्रदूषण रोकने के यंत्र लगायें। सबसे अहम मुद्दा यह है कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिला हमारे यहां 100 मीटर में न सीवरेज है और न ही उसकी सफाई होती है। गुरूग्राम नगर निगम में पीने का पानी और सीवरेज की सुविधा मिलती है। ये दो चीजें इस 100 मीटर के एरिया में डाली जायें जिससे इस सड़क से प्रदूषण कम हो। पांचवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 11313 सी.एम. अनाउंसमैंट थी जिसमें 8 करोड़ रुपया वहां पर ग्रीन बैल्ट डिवैल्प करके इस प्रदूषण को कम करने के लिए दिये गये थे। उसकी भी इस सदन में झूठी रिपोर्ट मिली कि यह जांच जारी है और मेरे को जांच दे रखी है। छठी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस एयर पोर्ट रोड को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाये। मैं सैक्रेटरी, अर्बन डिवैल्पमैंट से भी मिल लिया। हरियाणा सरकार ने

प्रपोजल भी दिया है। मेरी यह रिकवैस्ट है कि इसको फाईनल भी किया जाये। सबसे बड़ी बात जो अंत्योदय की बात होती है अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचाने की बात होती है। अधिकारियों द्वारा चण्डीगढ़ में एयर कंडीशंड रूम्ज़ में बैठकर योजनायें बनाने से गरीब लोगों को सुख नहीं मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का केस है। चीफ सैक्रेटरी हर बार वीडियो कांफ्रैंसिंग से मीटिंग लेते हैं। इस सदन में मुझे विश्वास दिलाया जाये कि इस सड़क पर मौके पर तीन महीने में एक बार चीफ सैक्रेटरी लैवल के ऑफिसर की मीटिंग होगी तो वहां से प्रदूषण अपने आप खत्म हो जायेगा। इस प्रदूषण की वजह से हमारे यहां हर 10वां आदमी कैंसर से मर रहा है।

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन और सभी हितधारकों के परामर्श से एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। नगर निगम फरीदाबाद के द्वारा नियमित रूप से कूड़ा–कर्कट और ठोस अपशिष्ट की सफाई की जा रही है। इसके अलावा जी. आर.ए.पी. के तहत जारी किये गये निर्देशों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया गया है। ऑन लाइन निगरानी के लिए फरीदाबाद जिले की 101 ईकाईयों को लगा दिया गया है जिनका ऑन लाइन डाटा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। वायु गुणवत्ता की निगरानी हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा स्थापित पांच नियंत्रण प्रवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) के माध्यम से की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। इस प्रकार के बहुत से कार्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं जिनका जिक्र मैंने अपने लिखित रिप्लाई में किया है। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने सभी सुझावों को लिखित रूप में मुझे भिजवा दें। हम उनको भी इम्पलीमैंट करने का प्रयास करेंगे। जहां तक वहां पर पेड़ लगवाने की बात है हम जल्दी से जल्दी वहां पर पेड़ लगवाने का काम शुरू करवायेंगे।

श्री नीरज शर्मा : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि मैंने अपने एक रोड का प्रश्न पूछा है और मंत्री जी पूरे जिले का जवाब दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि क्या हर तीन महीने में चीफ

सैक्रेटरी लैवल का ऑफिसर वहां मौके पर जायेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हो जायेगी तो इससे वहां की जनता को सुख मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नीरज शर्मा जी, आपकी समस्या का निराकरण होना चाहिए फिर भले ही वहां पर कोई भी ऑफिसर जाये।

श्री कंवर पाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उच्च अधिकारी वहां पर जाकर स्थिति का पूर्ण रूप से जायजा लेगा और अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसका तुरंत निराकरण किया जायेगा।

श्री नीरज शर्मा : स्पीकर सर, मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

———————

To Open a Government College

***933. Shri Dura Ram:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government college in Fatehabad City; if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री दूड़ा रामः अध्यक्ष महोदय, जिला मुख्यालय पर हमारा कोई कॉलेज नहीं है। हम जगह देने के लिए तैयार हैं। कृपा करके वहां फतेहाबाद शहर में एक कॉलेज बनवाया जाये।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद में एम.एम. कॉलेज चल रहा है।

श्री दूड़ा रामः अध्यक्ष महोदय, जिला मुख्यालय होने के कारण वहां पर एक सरकारी कॉलेज तो जरूर होना चाहिए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि फतेहाबाद में एक सरकारी कॉलेज अवश्य खोला जाए।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना ठीक है। वहां पर स्टूडैंट्स की संख्या भी 3349 है जो कि पर्याप्त है। अगर माननीय सदस्य जगह दिलवा देंगे तो वहां पर सरकारी कॉलेज खोलने पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री दूड़ा रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

Illegal Mining in Yamuna

***922. Shri Bishan Lal Saini:** Will the Mines and Geology Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the mining contractors are mining illegaly in Yamuna river in Radaur Assembly Constituency outside the area reserved by the Government for mining work; if so, the action taken by the Government in the matter; and

(b) whether it is also a fact that the studs constructed by the Government on the river banks to prevents soil erosion have also been damaged by the mining contractors; if so, the details thereof togetherwith the action taken by the Government in the matter?

खान एवं भू–विज्ञान मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा): (क) नहीं, श्रीमान् जी, अतः प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी, अतः प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

श्री बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि खनन से सरकार के खजाने में अच्छा पैसा आता है। मेरी खनन रोकने की कोई मंशा नहीं है। खनन होनी चाहिए तथा सरकार को राजस्व भी मिलना चाहिए। जब किसी भी फर्म को खनन का ठेका दिया जाता है तो उसके कुछ न कुछ नियम और शर्तें भी होती होंगी कि कितने एरिया में और कितनी गहराई तक खनन की जा सकेगी। इस बारे में मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि सरकार यह जांच करे कि क्या अलॉटिड एरिया में ही खनन हो रही है या उससे बाहर भी हो रही है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि खनन कितनी गहराई तक हो रही है, जहां तक सरकार ने अलाउड किया है वहीं तक खनन हो रही है या उससे अधिक हो रही है? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि पिछली सरकार द्वारा यमुना नदी में बाढ़ की रोकथाम के लिए जो टक्करें लगाई गई थी ताकि भूमि का कटाव न हो और जमीन यमुना नदी में न जाये, क्या खनन ठेकेदारों द्वारा उसका पालन किया जा रहा है या नहीं। इस बात की जांच करवाई जाये कि क्या इन खनन ठेकेदारों द्वारा उन टक्करों को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है या नहीं।

श्री मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, रादौर विधान सभा क्षेत्र में 7 माइंज हैं और 7 में से एक माइन वर्ष 2019 में इस क्षेत्र से चल रही थी। उस फर्म पर 4 करोड़ 80 लाख रुपये की पैनल्टी लगाई है और उसकी पैनल्टी का पैसा सरकार के पास आ

रहा है। 4 माइनिंग ऑक्शन में हैं और 5 माइनिंग के पास इनवायरमैंटल क्लियरेंस नहीं है। माननीय सदस्य अगर किसी पार्टीकुलर क्षेत्र के बारे में बतायेंगे तो हम टीम भेज कर उसकी जांच करवा लेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी इस महान सदन के सामने रखना चाहता हूं। यमुनानगर से हमें माइनिंग से कितना राजस्व प्राप्त होता है मैं उसकी जानकारी देना चाहूंगा। वर्ष 2014–15 में यमुनानगर से 2.52 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 2015–16 में 2.98 करोड़ रुपये तथा 2016–17 में 26.70 करोड़ रुपये की राशि रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हुई है। अगर वर्ष 2017–18 की बात की जाये तो 126.46 करोड़ रुपये तथा 2018–19 में 125.11 करोड़ रुपये माइनिंग सैक्टर से प्राप्त हुए। वर्ष 2019–20 में 141.15 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2020–21 के लिए 205.09 करोड़ रुपये का राजस्व हमें प्राप्त हुआ है और अभी यह महीना बाकी है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में अब तक के सारे रिकॉर्ड को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2015 में टोटल हरियाणा का रेवैन्यू 87 करोड़ 39 लाख रुपये माईनिंग से आया। वर्ष 2012–13 में टोटल हरियाणा का रेवैन्यू 75 करोड़ 02 लाख रुपये आया था। वर्ष 2013–14 में टोटल हरियाणा का रेवैन्यू 81 करोड़ 52 लाख रुपये आया था। वर्ष 2015–16 में टोटल हरियाणा का रेवैन्यू 265 करोड़ 42 लाख रुपये आया था। वर्ष 2016–17 व 2017–18 में टोटल हरियाणा का रेवैन्यू 712 करोड़ 87 लाख रुपये आया था। वर्ष 2019–20 में टोटल हरियाणा का रेवैन्यू 702 करोड़ रुपये आया था और वर्ष 2020–21 में आज तक टोटल हरियाणा का रेवैन्यू 925 करोड़ रुपये आया है। ये सब इसलिए हुआ है कि हमने माईनिंग की चोरियों को बन्द किया है। हमने बहुत सी जगहों पर जहां पर अवैध माईनिंग होती थी उसको बंद किया है। सारे विधायक यहां बैठे हैं वे अगर पूरे हरियाणा में कहीं भी इस तरह की कोई अवैध माईनिंग होती है तो वे मुझे बताएं। हम उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे और हम अपनी कमेटी की टीम साथ लेकर जाएंगे।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए।

श्री अध्यक्षः सैनी साहब, मंत्री जी ने इंश्योर कर दिया है कि अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है तो इन्हें बता दें।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा की एक छोटी सी बात रह रही है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि इतना–इतना पैसा खजाने में आया है। उससे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वह पैसा तो खजाने में आया है लेकिन जिस

प्रकार से वहां यमुना नदी बह रही है उसका इन माईनिंग के लोगों ने बुरा हाल कर दिया है।

श्री अध्यक्ष :सैनी साहब, आप उसके लिए लिख कर दे दीजिए। मंत्री जी ने कहा है कि हम इंक्वायरी करवाकर उस पर एक्शन लेंगे।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि हम बार–बार प्रशासन को, लोकल प्रशासन को, इरिगेशन विभाग को शिकायत करते हैं। वे लोग तो ऐसे हैं कि नदी का जो नैचुरल प्रवाह है अर्थात जो पानी बहता है उसके आगे गड्डे करके उस पानी की डायरैक्शन ही चेंज कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष :सैनी साहब, आप उसके लिए लिख कर दे दीजिए। मंत्री जी ने कहा है कि उसकी जांच करवाएंगे और उस पर एक्शन लेंगे।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, लिख कर भी दे देंगे। वे दो–चार दिन के लिए बन्द होते हैं और दोबारा फिर वही हाल शुरू हो जाते हैं।

———————————

तारांकित प्रश्न संख्या–1066

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अमर जीत ढ़ांडा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

———————————

To Construct the Building of Veterinary Hospital

***937. Shri Shamsher Singh Gogi:** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state that whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Veterinary Hospital in Assandh; if so, the time by which it is likely to be constructed?

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): हाँ श्रीमान् जी। राजकीय पशु अस्पताल, असंध, जिला करनाल के भवन निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है और यह पशु अस्पताल 31 मार्च, 2022 तक निर्मित होने की संभावना है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, असंध बहुत बड़ा एरिया है और वहां उस पशु अस्पताल में एस.डी.ओ. की भी पोस्ट है और डॉक्टर की भी पोस्ट है लेकिन वहां न तो एस.डी.ओ. है और न डॉक्टर है। वहां कुछ नहीं है। उसकी बिल्डिंग को

खराब हुए भी कितने दिन हो गये हैं और मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि उस बिल्डिंग का काम 22 मार्च तक पूरा हो जाएगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह काम शुरू कब होगा। जब वह काम शुरू होगा तभी तो पूरा होगा। आप शुरू होने की डेट बताइये कि वह काम शुरू कब होगा।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य को उस बिल्डिंग का काम 22 मार्च 2022 तक पूरा होने का एक साल का समय दिया है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं एक साल के बाद फिर आऊंगा। मैंने जाना कहीं नहीं है।

श्री जय प्रकाश दलाल : गोगी जी, आप चिन्ता मत करो। आपका हॉस्पीटल बन जाएगा। मैंने आपको 22 मार्च 2022 कम्पलीशन की डेट दे दी है तो फिर आप शुरू की चिन्ता क्यों कर रहे हो।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, हमने ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं कि शुरू होने से पहले सीधा कम्पलीशन हो जाए।

श्री जय प्रकाश दलाल : गोगी जी, हम काम को कम्पलीशन की डेट देकर करवाते हैं क्योंकि हम तेज गति से काम करवाते हैं। आपकी सरकार के समय काम शुरू होते थे लेकिन वे कभी पूरे ही नहीं होते थे। हम आपको काम खत्म होने की डेट दे रहे हैं। आप शुरू करने की चिन्ता मत कीजिए।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट है कि वहां उस हॉस्पीटल में डॉक्टर भी भेज दीजिए क्योंकि वह बहुत बड़ा एरिया है। हम भी सरकार के रेवैन्यू में कुछ न कुछ हिस्सा देते हैं। अगर असंध से कांग्रेस जीत गई है तो क्या बुराई हो गई। इसके साथ ही करनाल में एक क्लीनिकल लैब बन रही है। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है कि करनाल के अन्दर ऑलरेडी पहले से ही एक क्लीनिकल लैब है। अगर आप उसको असंध में बना दें क्योंकि असंध में जगह भी है। अगर आप वह लैब असंध में बनाते हैं तो उससे कैथल, जीन्द का जो दूर–दूर का एरिया है उनको करनाल जाने की बजाए नजदीक से ही सुविधा प्राप्त होगी इसलिए उस लैब को करनाल की बजाए असंध में बनाया जाए।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, एक बार इनका वह हॉस्पीटल बन जाए उसके बाद इनकी जो दूसरी डिमांड है उस पर विचार करेंगे। गोगी जी, आप उस लैब को करनाल से क्यों शिफ्ट करवाना चाहते हैं। हम आपके असंध के लिए अलग से प्रावधान कर देंगे।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, करनाल के उच्चाना में ऑलरेडी पहले से ही एक लैब है इसलिए वहां दो लैब बनाने की बजाए एक असंध में बना दी जाए।

———————————

To Start Construction Work of Building of YMCA

***987. Smt. Seema Trikha:** Will the Technical Education Minister be pleased to state the time by which the construction work of the building of YMCA University is likely to be started?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी, 2021 में नगर निगम, फरीदाबाद से भूमि का कब्जा लिया है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन कियाहै, जो प्रतीक्षित है। उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद, निर्माण कार्य शुरू करने बारे कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

श्रीमती सीमा त्रिखा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि वाई.एम.सी.ए. जो यूनिवर्सिटी है, इसका बहुत सा काम पूर्ण हो चुका है केवल एक फोरेस्ट डिपार्टमैंट की एन.ओ.सी. की आवश्यकता है। उसके आने से काम में और ज्यादा प्रगति आ जायेगी। सदन में पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित है और हमारे फोरेस्ट मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि फोरेस्ट डिपार्टमैंट की तरफ से जल्द से जल्द एन.ओ.सी. दिलाने का काम करें जिससे इस यूनिवर्सिटी के काम को नई गति मिलेगी और इसकी वजह से आने वाले समय में गुडगांव, फरीदाबाद तथा पलवल के बहुत बड़े एरिया को लाभ होगा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो फोरेस्ट मिनिस्टर साहब एन.ओ.सी. जल्द से जल्द देने का आश्वासन दे चुके हैं। इससे आगे यह बताना चाहूंगा यह यूनिवर्सिटी आलरेडी चल रही है और हम इसका नया कैंम्पस बनाने जा रहे है। यह यूनिवर्सिटी वर्ष 2009 में स्थापित हुई थी। इसमें 36 प्रोग्राम चलते हैं। इसमें 1821 बच्चों की एनुअल इंटेक होती है और इस वक्त जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी

संख्या 1952 है तथा जो टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या 5143 है और नम्बर ऑफ टीचर्ज की संख्या 183 है।अध्यक्ष महोदय, बहन जी एडीशनल कैम्पस बनाने की बात कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि यह यूनिवर्सिटी अभी नहीं चल रही है। इसको लेकर सरकार सजग है और सरकार ने बजट से संबंधित भी सारी तैयारी कर रखी है। धन्यवाद।

———————

To Construct a New Bus Stand

***871. Shri Ishwar Singh:** Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Bus-Stand of Cheeka is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Bus-Stand in Cheeka togetherwith the time by which the said Bus-Stand is likely to be constructed?

परिवहन मंत्री (पण्डित मूल चन्द शर्मा):

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) वर्तमान में चीका में नए बस स्टैण्ड के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हालांकि यहां पर जो बस स्टैंड है उसकी स्थिति ठीक है। यह बस स्टैंड कैथल मार्ग पर पड़ता है जोकि कैथल से 30 किलोमीटर तथा पटियाला से 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य समस्या यह है कि जैसाकि विधायक जी ने भी बताया है कि यह बस स्टैंड मुख्य रोड से डेढ किलोमीटर अंदर की तरफ है जिसके कारण बसिज इस बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती और बाहर से ही सवारी लेकर चली जाती है। इसके साथ ही माननीय सदस्य ने यहां की एक सरकारी जमीन पर नया बस स्टैंड बनाने का भी प्रपोजल दिया है। इस जमीन पर गुरूद्वारा, मजार व अन्य कईं प्रकार के कब्जे हैं परन्तु बावजूद इसके इन चीजों की परवाह न करते हुए हमने इस प्रयोजन हेतु 20 लाख 88 हजार रुपये स्वीकृत किए हुए हैं और जल्द ही इस जगह को खाली करवाकर यहां पर नया बस स्टैंड बना देंगे।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन का मैंने प्रपोजल दिया है यह पांच एकड़ सरकारी जमीन है। सरकार को कोई अलग से जमीन तो एक्वॉयर करनी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में बैठे हुए है। मैं उनके सामने माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बस स्टैंड का निर्माण जल्द से जल्द किया जाये।

श्री अध्यक्षः ईश्वर जी, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस जमीन पर इंक्रोचमैंट हो रखी है, आखिर इंक्रोचमैंट की गई जमीन को खाली तो कराना ही पड़ेगा?

श्री ईश्वर सिहः अध्यक्ष महोदय, सरकारी जमीन पर अनअथोरोइज्ड तरीके से खोखे रखकर या अनअथोराइज्ड तरीके से कोई कमरा बनाकर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी ने जमीन की रजिस्ट्री करवाकर मलकियन अपने नाम करवा ली है? अगर आज डी.सी को इस जमीन को खाली करने के लिए कहा जायेगा तो कल यह जमीन खाली हो सकती है? अतः अध्यक्ष महोदय, इस सरकारी जमीन को जल्द से जल्द खाली करवाकर चीका में नए बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाये।

श्री मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की अति संवेदशीलता को देखते हुए मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि चीका में जल्द से जल्द नया बस स्टैंड बना दिया जायेगा।

To Open a Women College

***758. Shri Aftab Amhed:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister to open a women college in village Kurthla in the memory of Martyr Lieutenant Kiran Shekhawat daughter of the said village in Nuh, Mewat District; and

(b) if so, the details of the progress made by the Government during the last five years in above said matter?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) राज्य सरकार ने राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेरी के नाम को बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेरी (नूंह) कर दिया है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि पहले से ही राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेरी (नूंह) बना हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 6 वर्ष पूर्व यह घोषणा हुई थी कि शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत की याद में गांव कुरथला में महिला महाविद्यालय खोला जायेगा। राज्य सरकार ने राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेरी का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेरी (नूंह) कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की घोषणा शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत की स्मृति में नये महाविद्यालय खोलने की हुई थी न कि महाविद्यालय के नाम बदलने की हुई थी। कृपया करके माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में इस संबंध में जवाब दें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि राजकीय महिला महाविद्यालय सालाहेरी (नूंह) गांव कुरथला से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा गवर्नमैंट एडिड Yasin Meo Degree College नूंह में चल रहा है, जिसमें छात्राओं की संख्या केवल 1108 है और इसकी दूरी गांव कुरथला से 15 किलोमीटर है। अध्यक्ष महोदय, राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेरी (नूंह) में छात्राओं की संख्या केवल 467 है, इस प्रकार से छात्राओं की संख्याओं को देखते हुए सरकार समझती है कि दूसरा नया महाविद्यालय खोलना ठीक नहीं है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आज भी राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेरी (नूंह) में लैक्चरार्ज के पद रिक्त पड़े हुए हैं और नगीना कॉलेज में भी लैक्चरार्ज के पद रिक्त पड़े हुए हैं। जब कॉलेजिज में लैक्चरार्ज के पद रिक्त पड़े होंगे तो हमारी बेटियाँ कैसे उन कॉलेजिज में एडमिशन ले सकती हैं, इसी कारण से उपरोक्त कॉलेजिज में छात्राओं की संख्या कम है। सरकार को चाहिए कि रिक्त पड़े लैक्चरार्ज के पदों को तुरंत भरे ताकि वहां बेटियों की कॉलेजिज में संख्या बढ़े।

माननीय मंत्री जी ने एक कॉलेज की दूरी तो 9 किलोमीटर और दूसरे कॉलेज की दूरी 15 किलोमीटर बताई है लेकिन 6 किलोमीटर का तो मेरा शहर भी नहीं है।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता पर सरकार गौर करेगी लेकिन नया कॉलेज खोलना ठीक नहीं है। धन्यवाद।

———————————

To Remove the 66kV Line

***926. Shri Deepak Mangla:** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the 66KV line is passing over the roof of the houses of the new extension area in Palwal City;

(b) whether it is also a fact that many people have been caught into accidents due to said line in above mentioned area; and

(c) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the abovesaid line together- with the time by which it is likely to be removed?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): (क) हां, श्रीमान।

(ख) पलवल शहर की नई एक्सटेंशन कालोनी में 24.04.2015 को बिजली का करंट लगने की केवल एक दुर्घटना हुई है।

(ग) नहीं, श्रीमान।

श्री दीपक मंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पलवल शहर में छतों के ऊपर से नए एक्सटेंशन की 66 के.वी.ए. लाइन गुजर रही है। वहां पर बहुत से लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। बरसात के दिनों में तो दुर्घटना की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान वहां पर 8–10 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से तीन व्यक्तियों की तो मौत भी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि पलवल के धर्म कॉलोनी और दुईराम कॉलोनी के एरिया से भी इसी तरह की एक हाईटैंशन तार गुजरती थी। उस तार को अंडरग्राउंड करवा दिया गया था जिससे लोगों को काफी राहत मिली गई थी। इस बात को तो मैं भी मानता हूं वहां पर उस हाईटैंशन तार को बदला नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर सैकड़ो की संख्या में मकान बने हुए हैं और वह एरिया घनी आबादी वाला एरिया है। वहां पर

18–20 हजार लोग रहते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि वहां के लिए दोबारा सर्वे करवाया जाए और उस हाईटैंशन लाइन को अंडरग्राउंड कर दिया जाए । इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और वहां पर आये दिन होने वाले एक्सीडैंट्स से भी लोगों को राहत मिलेगी । उन एक्सीडैंट्स में कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है । अतः उस हाईटैंशन लाइन के अंडरग्राउंड होने से वहां के निवासियों की जान भी बच जाएगी ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वह लाइन वर्ष 1992 में सैट अप की गई थी जोकि बहुत पुरानी हो चुकी है । उस समय विभाग के पास लाइन डालने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था । इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आदर्श कॉलोनी बाद में बनी है । वह एक अनअथॉराइज्ड कॉलोनी थी और जिस समय वहां पर लाइन डाली गई उस समय वहां पर कोई आबादी नहीं थी । इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर कोरोना काल में कई दुर्घटनाएं हुई हैं तो इसके बारे में तो मुझे पता नहीं क्योंकि कोरोना काल में अनेक तरह की दुर्घटनाएं हुई थी । पावर के करंट से हुई दुर्घटना के विषय में मैं बता सकता हूं कि वहां पर महाबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ बिजली का करंट लगने से दुर्घटना हुई थी । उस व्यक्ति को 24.04.2015 को ऑनरेबल हाई कोर्ट से 3 लाख रुपये का मुआवजा मिला था । विभाग ने उसको वह मुआवजा दे दिया था । इसके अलावा वहां से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में भी वहीं से पावर की सप्लाई दी जा रही है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर उनका इस तरह का कोई प्रपोजल है तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों से कहूंगा कि वे उस सवा किलोमीटर के एक टुकड़े में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड बिछाने की कोशिश करें ।

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ।

———————————

To Upgrade College as University

***1018. Shri Indu Raj :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister in Baroda Constituency to upgrade Choudhary Dhajja Ram Janta College Butana as University; if so, the action taken by the

Government for upgradation of said college togetherwith the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): नहीं, श्रीमान जी; इस अंश का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इंदू राज : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के बरोदा में हाल ही में उप–चुनाव हुआ था जिसमें इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी । उप–चुनाव से पूर्व वहां पर बी.जे.पी. के जितने भी बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय या माननीय मंत्रीगण गये वहां पर सभी ने उस कॉलेज को युनिवर्सिटी में अपग्रेड करने की घोषणा की थी । अगर सरकार उस कॉलेज को युनिवर्सिटी बनाती है तो मेरे हल्के के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा । इससे जनता में यह भी मैसेज जाएगा कि यह सरकार जो कहती है वह करती भी है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उस कॉलेज को युनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाए ।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, उस कॉलेज को युनिवर्सिटी में अपग्रेड करने के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमैंट की थी तो उन्होंने उस कॉलेज की मैनेजमैंट को सी.एम. ऑफिस में आकर सम्पर्क करने के लिए कहा था । अभी तक उस कॉलेज की मैनेजमैंट ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्पर्क करके इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है । इसके अलावा सोनीपत जिले में तीन सरकारी और पांच प्राइवेट युनिवर्सिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं । अतः उस जिले में युनिवर्सिटीज की संख्या पहले ही बहुत है । इसके साथ–साथ हम उस कॉलेज को युनिवर्सिटी में अपग्रेड करने की फिजिबिलिटी भी चैक करवा रहे हैं और हम वहां पर युनिवर्सिटी का रिजनल सैंटर बनाने पर भी विचार कर रहे हैं । अतः वहां पर जैसी भी आवश्यकता होगी वैसा ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

श्री इंदू राज : अध्यक्ष महोदय, उप–चुनाव से पूर्व वहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस कॉलेज को युनिवर्सिटी में अपग्रेड करने की घोषणा की थी और उस समय भी वहां पर वे सारी युनिवर्सिटीज बनी हुई थी । अतः मेरा कहना है कि सरकार स्वयं द्वारा की हुई घोषणाओं को जुमला न बनाएं और मेरा इस सरकार से विश्वास डिगाने का काम न करें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर एक सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं। यह सवाल माननीय सदस्य श्री इन्दू राज जी ने पूछा है, इसलिए उन्हीं को इस पर सप्लीमैंट्री पूछने दें। माननीय सदस्य श्री इन्दू राज जी नये चुनकर आए हैं, इसलिए आप उन्हें ही पूछने दें।

श्री इन्दू राजः अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल बहस हो रही थी कि गलत कार्य सरकार करती है और उनका इल्जाम हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो घोषणा की जाएं उनको पूरा भी किया जाए।

श्री अध्यक्षः इन्दू राज जी, आप अपना सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सप्लीमैंट्री का रिप्लाई दे रहा हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर एक सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, पहले माननीय सदस्य के सवाल का रिप्लाई देने दें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में बिल्कुल इन्कार नहीं किया है और यह सत्य है कि उस समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी उस एरिया में गये थे तो उस समय वहां के लोगों ने यह डिमांड की थी। उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा था कि अगर मैनेजमेंट मिलेगी और उसके बारे में प्रस्ताव दिया जाएगा तो हम उस पर विचार करेंगे, परन्तु आज तक उनसे मैनेजमेंट नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि किसी भी वर्क्स की फिजिबिलिटी चैक करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। जो इन्वैस्टमेंट होता है उसमें सरकार का ही खर्चा लगता है, इसलिए सरकार खर्च करने से पहले यह देखती है कि उसका उपयोग वहां पर कितना है ? सरकार यह चैक करवाती है कि उस कार्य का कितना उपयोग है ? अगर उस जगह पर उस चीज की आवश्यकता है तो हम उस कार्य को 100 प्रतिशत पूरा करवाते हैं। हम उस बात से इन्कार नहीं कर रहे हैं। वहां पर चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो या प्राईवेट यूनिवर्सिटी बनवाने की बात हो। अगर वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने की फिजिबिलिटी कम होगी तो हम वहां पर यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सैंटर ही बनवा देंगे ताकि बच्चों को असुविधा न हो।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है कि वहां के लोगों की तरफ से इस बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

इसके लिए सरकार के पास पहले ही प्रस्ताव आ चुका है। क्या सरकार के पास दोबारा से इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा तो वहां पर यूनिवर्सिटी बनवा दी जाएगी? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उस एरिया के आसपास पहले से ही 8 यूनिवर्सिटीज हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब इसके लिए घोषणा की गयी थी तो क्या उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं देखा कि उस एरिया में पहले से ही 8 यूनिवर्सिटीज हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनफिजिबल बात कह दी ? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं अभी भी इसके लिए इन्कार नहीं कर रहा हूं। किसी भी चीज को बनाने से पहले उसके लिए फिजिबिलिटी चैक करवायी जाती है। माननीय सदस्य भी सरकार में रहे हैं और इनको भी पता है कि किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली जाती है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उनकी घोषणाओं को चैक करवा लें। किसी भी चीज को बनवाने से पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली जाती है। माननीय सदस्य की पार्टी की सरकार ने बहुत लम्बे समय तक शासन किया है। माननीय सदस्य अपनी पार्टी की घोषणाओं का रिकार्ड चैक करवा लें।

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते समय इस बात पर विचार नहीं किया ?

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इनकी सरकार के समय की 100 ऐसी घोषणाएं निकलवाकर दिखा सकता हूं जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया।

———————————

To Extend the Road

***1039. Shri Vinod Bhayana:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the road of Hansi City from eastern bye-pass upto western bye-pass in Hansi City; if so, the time by which it is likely to be extended?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): No Sir.

श्री विनोद भ्याना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैंने जिस सड़क का जिक्र किया है वह सिर्फ 5 किलोमीटर की ही सड़क है और वह शहर के बीचों –बीच है। इसमें आलरेडी 2.50 किलोमीटर तक फोरलेन बना हुआ है बाकी 2.50 किलोमीटर का टुकड़ा ही शेष बचा हुआ है। इसके लिए मेरी डिमांड है कि इसको भी फोरलेन कर दिया जाए। इस सड़क पर हर रोज एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। इस सड़क के साथ–साथ 3 गांव लगते हैं और उन गांवों के लोग या तो मजदूरी करते हैं या छोटे किसान हैं। वे रोजाना अपनी सब्जी लेकर या मजदूरी करने के लिए साईकिल या मोटर साईकिल से शहर में आते हैं। वहां पर हर रोज एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप– मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस 2.50 किलोमीटर के टुकड़े को फोरलेन कर दिया जाए। ऐसा करने से वहां के लोगों के लिए बेहतरीन काम हो जाएगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एन.एच.ए.आई. ने हांसी में विशाल बाईपास बनवा दिया है। इसके कारण शहर में ट्रैफिक डैनसिटी बहुत बड़ी मात्रा में डिक्रीज हुई है। माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर केवल 2.50 किलोमीटर रोड का ही पैच है। इसके लिए मैं एक चीफ इंजीनियर लेवल की कमेटी कांस्टीच्यूट कर दूंगा। अगर डिपार्टमैंट के पास राईट ऑफ वे और लैंड अवेलेबल होगी तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से इस प्रस्ताव पर विचार कर लेंगे।

———————

Details of Installed L.E.D Street Lights

***1076. Shri Narender Gupta:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) number of LED lights for which tenders have been called by Municipal Corporation, Faridabad since 2018;

(b) rate of LED street lights alongwith name of contractors to whom said tenders have been released;

(c) wardwise LED street lights installed by the abovesaid contractors in Faridabad-89 Assembly Constituency;

(d) wardwise number of LED street lights installed at present in Faridabad Assembly Constituency; and

(e) whether it is a fact that the LED street lights working at present are less than the LED street lights installed by contractors; if so, the action taken by the Government on persons responsible?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, विवरणसदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा 2018 के बाद से विभिन्न वाट की 59,649 एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट, 198 हाई मास्ट एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट और 15 सोलर लाइट्स की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ख) नगर निगम फरीदाबाद द्वारा जिन ठेकेदारों को निविदाएं आवंटित की गई हैं, उनके नाम के साथ एल.ई.डी.स्ट्रीट लाइटों का मूल्य निम्नानुसार हैं:–

क्रम संख्या	ठेकेदार/एजेंसी का नाम	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट की संख्या	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट कीवाट क्षमता	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट की दर(प्रति यूनिट)	आवंटन की तिथि
1	मैसर्स शांति इलेक्ट्रिकल्स कंपनी	100	25 W.	Rs. 2500/-	09.01.2018
		100	60 W	Rs. 4800/-	
2	मैसर्स शांति इलेक्ट्रिकल्स कंपनी	128	90 W	Rs. 11,800/-	09.01.2018
3	मैसर्स शान इंटरनेशनल	8 हाई मास्ट12 एल.ई.डी.के साथ	100 W	Rs. 3,34,520/-	15.01.2018
4	मैसर्स प्रकाश वीर सिंह ठेकेदार	111	90 W	Rs. 11490/-	21.03.2018
5	मैसर्स ऑबिट टेकसाल प्रा. लिमिटेड	194	25 W	Rs. 1900/-	23.03.2018
6	मैसर्स ऑबिट टेकसाल प्रा. लिमिटेड	191	25 W	Rs. 1950/-	28.03.2018
7	मैसर्स अंजनी	200	25W	Rs. 1970/-	04.01.2018

	कंस्ट्रक्शंस कं।				
8	मैसर्स अंजनी कंस्ट्रक्शंस कं।	176	25W	Rs. 1900/-	04.01.2018
9	मैसर्स अंजनी कंस्ट्रक्शंस कं	143	25W	Rs. 1876/-	04.01.2018
10	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	21 हाई मास्ट 6 एल.ई.डी.के साथ	200 W	Rs. 3,50,000/-	12.04.2018
11	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	19हाई मास्ट 6 एल.ई.डी.के साथ	200 W	Rs. 3,50,000/-	12.04.2018
12	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	21 हाई मास्ट6 एल.ई.डी. के साथ	200 W	Rs. 3,50,000/-	12.04.2018
13	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	705	200 W	Rs. 2500/-	12.04.2018
14	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	6 of 12.5 mtr हाई मास्ट12 एल. ई.डी.के साथ	200 W	Rs. 3,87,000/-	12.04.2018
15	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	8 हाई मास्ट12 एल.ई.डी.के साथ	100 W	Rs. 3,87,000/-	12.04.2018
16	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	893	90 W	Rs. 12,500/-	12.04.2018
17	मैसर्स इंपीरियल इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड सर्विसेज	166	60 W	Rs. 4800/-	29.05.2018
		80	25 W	Rs.2900/-	
18	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	15	90 W	Rs. 12500/-	26.06.2018
		15 सोलर लाइट	18 W	Rs. 5800/-	
19	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	150	100 W	Rs. 12500/-	02.07.2018
20	मैसर्स ऑबिट टेकसाल प्रा. लिमिटेड	437	25 W	Rs. 1940/-	30.09.2018
21	मेसर्स सुपर एंटरप्राइजेज	51371	24 W	Rs. 1650/-	17.10.2018
			60 W	Rs. 3540/-	
			90 W	Rs. 6700/-	
22	मेसर्स एडवांस टेक्नोलॉजी	543	90 W	Rs. 7900/-	22.01.2019
23	मैसर्स शांति इलेक्ट्रिकल्स कंपनी	136	90 W	Rs. 9500/-	23.01.2019
24	मैसर्स प्रकाश वीर सिंह ठेकेदार	50 हाई मास्ट9 एल.ई.डी.केसाथ	150 W	Rs. 3,75,000/-	28.01.2019
25	मेसर्स एडवांस टेक्नोलॉजी	700	24W	Rs. 2600/-	07.02.2019
26	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	10	120 W	Rs. 15000/-	07.02.2019
27	मेसर्स सुपर एंटरप्राइजेज	1100	60 W	Rs. 3900/-	08.03.2019
28	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	30 हाई मास्ट12 एल.ई.डी.के साथ	120 W	Rs. 3,62,000/-	08.03.2019
29	मेसर्स सुपर एंटरप्राइजेज	500	90 W	Rs. 6000/-	08.03.2019
		1000	60 W	Rs. 3900/-	
		500	25 W	Rs. 1650/-	
30	मेसर्स अक्षय इंडिया एंटरप्राइजेज	14 हाई मास्ट12 एल.ई.डी.के साथ	120 W	Rs. 3,60,000/-	13.01.2020
31	मैसर्स इंपीरियल इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड सर्विसेज	1 हाई मास्ट9 एल. ई.डी.के साथ	150 W	Rs. 3,85,000/-	13.05.2020
32	मैसर्स प्रकाश वीर सिंह ठेकेदार	20 हाई मास्ट12 एल.ई.डी.के साथ	100 W	Rs. 3,49,000/-	काम अभी शुरु नहीं हुआहै।

(ग) फरीदाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा लगाई गई एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटों का वार्ड–वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं

वार्ड नं.	ठेकेदारकानाम	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटों की संख्या
29	मैसर्स इंपीरियल इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड सर्विसेज	246
30	मैसर्स शांति इलेक्ट्रिकल्स कंपनी	200
31	मैसर्स अंजनी कंस्ट्रक्शंस कं।	200
32	मैसर्स ऑबिट टेकसाल प्रा. लिमिटेड	437
	मैसर्स अंजनी कंस्ट्रक्शंस कं।	176
33	मैसर्स अंजनी कंस्ट्रक्शंस कं।	143
	मैसर्स ऑबिट टेकसाल प्रा. लिमिटेड	191
	मैसर्स शांति इलेक्ट्रिकल्स कंपनी	128
	मैसर्स इंपीरियल इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड सर्विसेज	1हाई मास्ट 9 एल.ई.डी.के साथ
34	मैसर्स ऑबिट टेकसाल प्रा. लिमिटेड	160

(घ) फरीदाबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में स्थापित एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटों का वार्ड वार विवरण निम्नानुसार हैं:

वार्डनं.	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटों की संख्या
13	1127
28	1212
29	1333
30	1819
31	2206
32	2290
33	2493
34	1347

(ड) हां श्रीमान जी। मुख्य अभियन्ता, नगर निगम फरीदाबाद की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। फिलहाल जांच जारी है।

श्री नरेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न (ख) में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है सुपर इंटर प्राइजिज द्वारा 51371 एल.ई.डी. लाइट्स खरीदी गई। प्रश्न (ग) के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है। मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें से एक लाइट भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं लगाई गई है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद के लिए 51371 लाइट्स खरीदी गई थी परन्तु इनमें से एक भी लाइट फरीदाबाद में नहीं लगाई गई है, इसके क्या कारण हैं? प्रश्न (ड़) में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मुख्य अभियंता नगर निगम फरीदबाद की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। मेरा इस संबंध में यही कहना है कि यह जो जांच चल रही है, वह कब तक पूरी हो जायेगी? फरीदाबाद नगर निगम के बारे में पूरे न्यूज पेपर्ज के माध्यम से बहुत ज्यादा इधर–उधर की खबरें आती रहती हैं कि नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारी ढंग से काम नहीं

करते हैं और अपनी मर्जी से फरीदाबाद नगर निगम को चला रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मुझे पहले 51371 एल.ई.डी. लाइट्स के बारे में बता दें कि ये लाइट्स मेरे क्षेत्र में क्यों नहीं लगाई गई और स्टॉक में अभी तक कितनी लाइट्स पैंडिंग पड़ी हुई है?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है कि लगभग 51000 एल.ई.डी. लाइट्स लगाई गई किन्तु हमारे माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में एक भी एल.ई.डी. लाइट नहीं लगाई गई, यह बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय सदस्य ने इस पूरे मामले के बारे में जो जानकारी दी है मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस मामले में चीफ इंजीनियर द्वारा जांच की जा रही है। माननीय सदस्य ने जो प्वॉयंट आउट किये हैं। हमने उन प्वॉयंट्स के बारे में इसकी पैरावाइज पूरी डिटेल बता दी है। मैं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच रिकमण्ड करता हूं कि इसकी उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाये और मुझे इसकी रिपोर्ट तुरन्त प्रभाव से भेजी जाये।

श्री नरेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूं और मुझे विश्वास भी है क्योंकि जो माननीय मंत्री जी कहते हैं वो करते जरूर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे अपने पी.ए. की ड्यूटी जांच की रिपोर्ट लेने के लिए लगायेंगे तो उच्च अधिकारियों से जांच की रिपोर्ट समय पर ली जा सकेगी।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मुख्य अभियंता से इस मामले की जांच की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप इस नगर निगम की एक बार फॉरेंसिक ऑडिट करवा दें। जो सरकार का पैसा चण्डीगढ़ से जा रहा है, वह पैसा लगा है या नहीं, इस बारे में पता चल जायेगा? अभी एक नया सर्वे हुआ है, जिसमें 450 लाख कीमत की प्रॉपर्टीज फरीदाबाद की चिन्हित की गई हैं और 55000 एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट का मामला भी है। सरकार कहती है कि हर 10 घर के बाद एक एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट लगाई गई है परन्तु हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है और इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि सरकार के पास फॉरेंसिक ऑडिट करवाने लिए पैसा नहीं है तो हमारे फरीदाबाद में चार्टेड अकाउंटेंट का पूरा दफ्तर है और उनकी एसोसिएशन भी है। वहां पर बच्चों को चार्टेड अकाउंटेंट का

काम सिखाया जाता है। मुझे लगता है कि शायद वे बच्चे जनता के हित में यह काम बिना पैसे के भी कर दें इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि नगर निगम फरीदाबाद का एक बार फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का काम किया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगम से काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मैंने इन दोनों नगर निगमों का ऑडिट कराने के लिए ए.जी. हरियाणा को लिखा है और ए.जी. हरियाणा ऑडिट करने के लिए तैयार भी हो गया है। मैंने उनको कहा है कि पिछले 5 सालों का पाई–पाई का ऑडिट किया जाये ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

———————

Construction of Roads

***829. Shri Lila Ram**: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads under the Haryana State Agriculture Marketing Board in Kaithal Constituency:-

(i) village Ujhana to village Kultaran;

(ii) village Dhundrehri to Diwal (road of school);

(iii) village Manas to Farsh Majra; (via fields passage)

(iv) village Jaswanti to village Dohar;

(v) village Guhna to village Sanghan;

(vi) village Gadi to village Manas;

(vii) village Padla to village Baba Ladana via village Budha Khera;

(viii) village Shergarh to footpath of water course via Deod Kheri up to Sugar Mill Karnal Road;

(ix) village Deohra to footpath of Canal upto village Kultaran;

(b) if so, the time by which these roads are likely to be constructed?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री **जय प्रकाश दलाल**): ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

ब्यौरा

क्र0 संख्या	कच्चे रास्ते का विवरण	लम्बाई (कि.मी. में)	आर.डी. वार राजस्व रास्ते की चौडाई	टिप्पणी
1	गांव उझाना से गांव कुलतारन	3.10	0 से 1260 = 6 करम आर.डी. 1260 से 3100 तक = 5 करम	इस सड़क का निर्माण कार्य अगले वित्तिय वर्ष 2021–22 में शुरू किया जाएगा ।
2	गांव धुंदरेहरि से दिवाल (विद्यालय की सड़क)	1.70	0 से 1350 = 5 करम आर.डी. 1350 से 1700 तक = 6 करम	इस सड़क का निर्माण कार्य अगले वित्तिय वर्ष 2021–22 में शुरू किया जाएगा ।
3	गांव मानस से फर्श माजरा (वाया खेतों के रास्ते)	3.76	0 से 605 = 3 करम आर.डी. 650 से 3760 तक = 5 करम	आर.डी. 0 से 605 मी0 में रास्ते की कम चौडाई उपलब्ध होने के कारण प्रस्तावित सड़क बोर्ड की सड़क निर्माण नीति के अन्तर्गत नहीं आती ।
4	गांव जसवन्ती से गांव दोहर	3.30	0 से 2180 = 6 करम आर.डी. 2180 से 2305 तक = 5 करम आर.डी. 2305 से 3300 = 4 करम	इस सड़क के निर्माण के लिए 146.67 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 24.02. 2021 को दे दी गई थी तथा कार्य 31.03.2022 तक पूरा होने की सम्भावना है ।
5	गांव गुहना से गांव सांगवान	5.50	0 से 1930 = 6 करम आर.डी. 1930 से 5500 तक = 5 करम	इस सड़क का निर्माण कार्य अगले वित्तिय वर्ष 2021–22 में शुरू किया जाएगा ।
6	गांव गढी से गांव मानस	1.45	0 से 1450 = 5 करम	इस सड़क का निर्माण कार्य अगले वित्तिय वर्ष 2021–22 में शुरू किया जाएगा ।
7	गांव पाडला से गांव बाबा लादाना वाया गांव बुढा खेड़ा			गांव पाडला से बाबा लदाना वाया बुढा खेडा के लिए कोई कच्चा रास्ता उपलब्ध नहीं है ।
8	गांव शेरगढ़ से पानी के नाले की पगडंडी वाया दाऊ खेड़ी से शुगर मिल करनाल सड़क तक	3.72	0 से 2720 – कोई रास्ता उपलब्ध नहीं आर.डी. 2720 से 3720 तक = 3 करम	रास्ता उपलब्ध न होने/कम चौड़ा होने के कारण प्रस्तावित सड़क बोर्ड की सड़क निर्माण नीति के अन्तर्गत नहीं आती
9	गांव दयौरा से नहर की पगडंडी गांव कुलतारण तक	4.70	0 से 2415 – कोई रास्ता उपलब्ध नहीं आर.डी. 2415 से 4700 तक = 3 करम	रास्ता उपलब्ध न होने/कम चौड़ा होने के कारण प्रस्तावित सड़क बोर्ड की सड़क निर्माण नीति के अन्तर्गत नहीं आती

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनसे पूछना भी चाहूंगा कि जो उन्होंने अपनी रिप्लाई में कई सड़कों के बारे में ब्यौरा दिया है, जो अगले वित्त वर्ष में बनाई जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस ब्यौरा में एक दो सड़कों के बारे में गलत लिखा गया है जैसे गांव दयौरा से जसवंती और एक गांव मानस से अटेला तक की सड़क ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अलावा मैं यह भी बातना चाहूंगा कि गांव कुलतारन से उझाना और गांव मानस से अटेला में 33 फुट की रोड है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस विधान सभा में वर्ष 2000 में चुनकर आया था

तब मैंने इस सदन में यही बात उठाई थी। मेरी सरकार से अपील है कि जो कार्य 18–20 साल से पैंडिग पड़े हुए हैं, उनको पूरा करवाने का काम किया जाये।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 9 सड़कों के बारे में ब्यौरा मांगा था। इसमें से एक सड़क की फिजीबिलिटी रिपोर्ट आनी बाकी है और बाकी सड़कों की फिजीबिलिटी रिपोर्ट चैक कर ली गई हैं। इन 9 सड़कों में से 4 सड़कों की फिजीबिलिटी रिपोर्ट आ गई है और 3 सड़कों के 3 करम के रास्ते हैं और एक सड़क का कच्चा रास्ता है। जो सड़कें फिजीबल की श्रेणी में आ जायेगी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जांच करवाने के बाद अगले आने वाले वक्त में इन सड़कों को बनाने का काम पूरा करवा दिया जायेगा।

———————————

The Present Status of Construction Work of Hisar Airport

***903. Dr. Kamal Gupta**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the present status of the Second phase construction work of Hisar Airport together with the time by which it is likely to be completed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Yes, Sir. The second phase of construction work of Hisar Airport has been started on 05.02.2021 and is likely to be completed by end of 2022 (i.e. FY 2022-23).

स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि हिसार एयरपोर्ट का जो कार्य फेज–2 का है वह ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और उस पर कार्य दिनांक 05.02.2021 से शुरू हो चुका है। उसमें फेज–2 के अंदर रन–वे एक्सपैंशन की बात है। इसमें हिसार एयरपोर्ट पर 10 हजार फीट का रन–वे ऑलरेडी अण्डर कंस्ट्रशन है और वर्ष 2022 के अंदर वह पूरी तरह से कम्पलीट हो जायेगा। इसके साथ ही साथ हमारा यह भी प्रयास है कि स्मॉल स्केल एम.आर.ओ. सहित बहुत से प्रोजैक्ट्स हम हिसार के अंदर अगले दो वित्त वर्ष के दौरान ला पायें। मैंने हमारे एयरो डिफैंस से सम्बंधित जितने भी इंस्टीच्युशंज हैं उन सभी की आज शाम को 05.00 बजे एक मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर हम उनको भी मोटीवेट करेंगे कि वे हरियाणा के अंदर आकर इनवैस्टमैंट करें। अध्यक्ष जी, हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारा हिसार का इकलौता एयरपोर्ट है उसको हम इंटरनेशनल लैवल पर लेकर जायें।

डॉ. कमल गुप्ता : स्पीकर सर, इसके लिए मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, इस मामले में मेरे दो सुझाव और हैं। एक तो जो ये फ्लाईंग क्लब एसोसिएशन है उसको भी शुरू करने की कृपा की जाये और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर एक हैली सर्विस शुरू की जाये। वहां पर नजदीक ही अग्रोहा धाम है। वहां पर अगर कोई हैलीकॉप्टर आ जा सके तो इससे लोगों का मनोरंजन भी हो जायेगा और यह कांसैप्ट टूरिज्म को भी हैल्प करेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से यह कहना चाहूंगा कि मेरे हिसार में फ्लाईंग क्लब एसोसिएशन और हैलीकॉप्टर सर्विस की भी शुरूआत की जायेगी तो मैं उप–मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभारी रहूंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, जहां तक हिसार में हैली सर्विस की शुरूआत करने की बात है हम इस सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं क्योंकि हैलीपोर्ट की फिजिबिलिटी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि आज भी उड़ान स्कीम के अंदर हिसार से देहरादून, हिसार से धर्मशाला और हिसार से चण्डीगढ़ के लिए फ्लाइट सर्विस निरंतर चल रही है। इसके साथ ही साथ जो हमारा सिविल एविएशन क्लब था उसको करनाल में रि–एलोकेट कर दिया गया था क्योंकि हिसार में हैंगर वगैरह की कंस्ट्रशन चल रही थी। स्पाईजैट से हमारा एम.ओ.यू. हो चुका है कि 100 पॉयलैट्स की ट्रैनिंग का फ्लाईंग क्लब हिसार में स्पाईजैट बनायेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन भी देता हूं कि अगर किसी कारणवश स्पाईजैट के फ्लाईंग क्लब की स्थापना में कोई डिले होगा तो जो हमारा हरियाणा का फ्लाईंग क्लब है उसको जरूर रि–एलोकेट करके वापिस करनाल से हिसार में ले जाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

———————

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Open a Store of Power Department

***791. Shri Lakshman Napa:** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a store of power department in Ratia; if so, the time by which it is likely to be opened?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): श्रीमान जी नहीं, इस भाग का प्रश्न हीं नहीं उठता।

———————

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Construct the Sub-Division and Tehsil Office

263. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be please to state-

(a) whether it is a fact that there is no Tehsil and Sub-division office in N.I.T. Faridabad of its own; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Sub-division and Tehsil office in Faridabad N.I.T. Assembly, Constituency togetherwith the time be which the said are likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) हां श्रीमान जी, इस समय तहसी कार्यालय व उप–मण्डल (ना.) बडखल, जिला फरीदाबाद का कोई भवन नहीं है और ये सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद के भवन में बिना किराए के कार्यरत हैं।

(ख) उप–मण्डल व तहसील कार्यालय हेतु एन.आई.टी. फरीदाबाद में भूमि चिन्हित की जा रही है और तदोपरान्त निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

.....

To Widen the Bridge

244. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the bridge of canal situated on road between villages Lohari Tibba and Mohana in Gohana Assembly Constituency?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Remove the 11 K.V Electricity Line

282. Shri Mewa Singh : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the 11 K.V. electricity line passing over the HDFC Bank, Market and many houses on the Babain to shahabad road of Ladwa Assembly constituency; if so, the time by which it is likely to be removed?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन) द्वारा खतरनाक लाइनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण वर्ष 2018 में पूरा किया गया था तथा लाडवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की बबैन से शाहबाद सड़क पर एच.डी.एफ.सी. बैंक, बाजार तथा बहुत से घरों के ऊपर से गुजर रही 11 के.वी. बिलजी लाइन को खतरनाक लाइन के रूप में नहीं पहचाना गया था।

11 के.वी. बबैन ग्रामीण घेरलू आपूर्ति (आर.डी.एम.) फीडर की बिजली लाइन बबैन से शाहबाद रोड़ तक घरों/दुकानों के ऊपर से गुजर रही है जोकि लाल डोरा के बाहर आते हैं। उक्त फीडर लगभग 25 वर्ष पहले बनाया गया था तथा बिजली लाइन 6 घरों के ऊपर से गुजर रही है जो बाद में बनाए गए थे। उपरोक्त लाइन को हटाने के लिए कोई आवेदन पत्र उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन) को प्राप्त नहीं हुआ है।

हालांकि, उक्त लाइन को हटाने की अनुमानित लागत 6.75 लाख रुपये है। यू.एच.बी.वी.एन द्वारा अपनाई गई हरियाणा सराकर की अधिसूचना के अनुसार, यह कार्य लाभार्थियों द्वारा अनुमानित लागत जमा करवाने के बार किया जाएगा तथा 30 दिनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।

.....

To Construct Road

239. Shri Ram Kumar Gautam : Will the Deputy Chief Minister be pleased be state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct road from villages Gulkani, Milakpur, Rakhi, Gurana, Luhari Ragho, Shala Dheri, Chanot and Tharwa in Hisar?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हॉ, श्रीमान जी। सड़क वाया गांव गुल्कनी, मिलकपुर, राखी, गुराना, लुहारी राघो, शाला धेरी और ठरवा सिवाय गांव चनोट बनाने का प्रस्ताव है।

————————

To Open Central Co-operative Bank

294. Shri Deepak Mangla : Will the Cooperation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Central Cooperative Bank on District level in Palwal; if so, the details thereof?

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : नहीं, श्री मान जी।

.....

To Provide House to the Poor Families

373. Shri Balraj Kundu: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the extent of target achieved by the Government under the Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin in State; and

(b) the number of families deprived of getting the benefits of abovesaid scheme togetherwith the steps taken or likely to be taken by the Government in this regard?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमानजी,

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के लिए 21,502 घरों का लक्ष्य आंवटित किया गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध 20,505 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 410 घर निर्माणाधीन हैं।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की हिदायतों अनुसार केवल 1249 वंचित परिवार पात्र हैं जिन्हें उनके मकानों के निर्माण के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवास + पोर्टल के अनुसार 1,44,276 परिवार सहायता के लिए पृथम दृष्टया पात्र हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा समय पर हरियाणा राज्य को वर्ष 2021–2022 के लिए अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन किया जा सकता है।

————————

To Set-up Division and Sub-division of DHBVNL

358. Shri Sita Ram Yadav: Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up Division and Sub-Division of DHBVNL in Ateli and Bachhod respectively; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized togetherwith the details thereof?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान जी, दक्षिण बिजली वितरण निगम के लिए स्वीकृत पुनर्गठन शर्तों के आधार पर, अटेली में एक मंडल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं बाछोद में एक उपमंडल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

.....

To Repair Road

319. Shri Amit Sihag: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the road from Dabwali to Rania is in dilapidated condition: and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the above said road togetherwith the time by which it is likely to be repaired?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) तथा (ख) सरकार ने पत्र क्रमांक 09/62/2020– 3 बी.एण्ड.आर. (डब्लयू) दिनांक 03.03.2021 को रुपये 3381.85 लाख की सड़क को 7.00 से 10.00 मीटर चौड़ा करने व इसके मजबूतीकरण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। कार्य की निविदाएं प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। यद्यपि, इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

————————

To open a new Nursing College

329. Shri Ram Niwas: Will the Medical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Nursing College in Narwana Assembly Constituency?

चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान मंत्री (श्री अनिल विज): नहीं, श्रीमान जी।

To Acquire Land Under the Master Plan

377. Shri Narender Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of total land acquired by the Government under the Greater Faridabad Master Plan, 2021; and

(b) whether the Government has taken over the possession of above said acquired land; if not, the reason thereof?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) ग्रेटर फरीदाबाद मास्टर प्लाल, 2021 के तहत सरकार द्वारा कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी।

(ख) सरकार ने मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार किसी भी भूमि के कब्जे को नहीं लिया है ।

.....

Discretionary Grants for Development Works

264. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the grant of 5 Crore Rupees has been released to every Legislator by the Chief Minister of Haryana as discretionary grant for the development works out of which Rs.1,10,24,000 had been released by me for the development works for rural area in my constituency and out of which Rs.77,34,000/- has been sanctioned by the Government but the files are lying pending since 10.7.2020 in the concerned office; and

(b) if so, the reasons thereof ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी, विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद एनआईटी के संबंध में सीएम घोषणा संख्या 25284 के तहत प्राप्त 1,00,24,000 रूपए के 8 कार्यों के अनुमानों की विभाग द्वारा जांच की गई और केवल 77,34,000 रूपए के 5 अनुमानों को ठीक पाया गया और सरकार को प्रस्तुत किया गया। इन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

———————

To Repair Chaupal

245. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair General Chaupal in Village Garhi Hakikat of Gohana Assembly Constituency?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): जी हाँ, श्रीमान जी। सीएम अनाउंसमेंट कोड नंबर 25284 के तहत प्राप्त गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़ी हकीकत में जनरल चौपाल को पूर्ण करने के लिए 2,88,000 रुपये का अनुमान सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

To Remove the 11 K.V. Erectricity Line

303. Shri Mewa Singh : Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the 11 K.v. electricity line passing over the houses near corony Gurudwara adjacent to Ward-8, Ladwa lndri road in Ladwa Assembly constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be removed?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्री मान (क) एवं (ख) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) द्वारा खतरनाक लाइनों की पहचान के लिए सर्वेक्षण वर्ष 2018 में पूरा किया गया था तथा लाडवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार्ड–8, लाडवा–इन्द्री रोड़ के समीप गुरूद्वारा कालोनी के पास घरों के ऊपर से गुजर रही बरोंदी कृषि बिजली (ए.पी.) फीडर की 11 के.वी. बिजली लाइन को खतरनाक लाइन के रूप में नहीं पहचाना गया था।

उक्त फीडर लगभग 20 वर्ष पहले बनाया गया था तथा बिजली लाइन कालोनी के 10 घरों के ऊपर से गुजर रही है जो बाद में बनाए गए थे। उपरोक्त लाइन को हटाने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) को कोई आवेदन नहीं हुआ है।

हालांकि, उक्त लाइन को हटाने की अनुमानित लागत 6.92 लाख रुपये है। यू.एच.बी.वी.एन. द्वारा अपनाई गई हरियाणा सरकार की अधिसूचना के

अनुसार, यह कार्य लाभार्थियों द्वारा अनुमानित लागत जमा करवाने के बाद किया जाएगा तथा 30 दिनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।

.....

To Constitute New Primary Agriculture Committee

295. Shri Deepak Mangla: Will the Co-operation Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the members of the Villages Rajupura Khadar, Dostpur and Bholra of Khadar area of Palwal have to go about 30-35 KM away to visit their Primary Agriculture Committee as Yamuna River falls between Gurwari Primary Agriculture Committee and the said Villages; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of Government to constitute new Primary Agriculture Committee by the name of Rajupura?

सहकारिता मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल):

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) हाँ श्रीमान जी।

.....

To increase the Capacity of PWD Rest House

320. Shri Amit Sihag : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of the PWD Rest House in Dabwali by constructing more rooms?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं, श्रीमान जी। डबवाली के पुराने लोक निर्माण विभाग गृह की 17.17 लाख रुपये की लागत से विशेष मरम्मत/नवीनीकरण का आकलन सरकार के विचाराधीन है।

————————

Collection of Labour Cess

330. Shri Ram Niwas: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the amount of labour Cess collected by the Labour Construction Welfare Board during the Year 2019-20 and 2020-21 in State; and

(b) the details of expenditure incurred on various components for welfare of various classes of labour out of the above collected funds during the Year 2019-20 and 2020-21?

उप– मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) श्रीमान् जी, हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा एकत्रित श्रम उपकर का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष 2019–20 (करोड़ में)	वर्ष 2020–21 (28 फरवरी 2021 तक) (करोड़ में)
रुपये 285.15	रुपये 307.62

(ख) श्रीमान् जी, वर्ष 2019–20 के दौरान श्रम (निर्माण श्रमिक) के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न घटकों पर किए गए व्यय **312.21 करोड़ रुपये** और वर्श 2020–21 (28 फरवरी 2021 तक) के लिए **353.75 करोड़** रुपये खर्च किए गए। व्यय का योजनावार विवरण **तालिका 'अ'** के अनुसार है।

विवरण

तालिका –'अ'

हरियाणा बोर्ड द्वारा 2019–20 व 2020–21 में निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत व्यय की गई राशि का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	2019–20	2020–21 (28 फरवरी 2021 तक)'
	कल्याणकारी खर्चे		
1	मातृत्व लाभ	6.82	4.65
2	पित्तृव लाभ	4.87	4.05
3	शिक्षा छात्रवृत्ति	67.80	67.19
4	कन्यादान	47.43	32.32
5	साईकिल	16.63	11.60

6	चिकित्सा सहायता	0.02	0.00
7	सिलाई मशीन	0.06	0.00
8	पेंशन	0.09	0.04
9	दाह संस्कार सहायता	2.70	2.34
10	मृत्यु	37.01	31.44
11	अपंगता सहायता/पेंशन	0.02	0.02
12	औजार	44.29	31.29
13	मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना	16.37	11.75
14	बच्चो की शादी पर वित्तिय सहायता	35.90	33.38
15	अपंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु पर वित्तिय सहायता	0.23	0.03
16	शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की वित्तिय सहायता बाल/बाल अपंगता पेंशन	0.15	0.15
17	मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	0.40	0.20
18	घातक बीमारी के लिए वित्तीय सहायता	0.05	0.00
19	मुफ्त भ्रमण सुविधा	0.0010	0.0000
20	अंशदान की वापिसी	0.0003	0.00
21	कोविड–19 के दोरान वित्तीय सहायता	31.40	123.28
	कुल–क	312.21	353.75

'वित्तिय वर्ष 2020–21 के लिए दर्शाई गई राशि अनधिकृत है और बैलेंस शीट को अंतिम रुप देने के अधीन है।

.....

To Regularize Aarohi School Teachers

265. Shri Neeraj Sharma: Will the Education Minister be Please to state-

(a) whether it is a fact that the teachers have been appointed by the Government in the Aarohi Model Schools opened in the year-2011 on

the contract basis subject to regularization after 5 year as mentioned in the terms and conditions of contractual agreement; and

(b) if so, the reasons for which abovesaid teachers are not been regularized so far togetherwith the time by which these are likely to be regularized?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) हां, श्रीमान जी।
(ख) मामला प्रक्रिया में है।

.....

Level of Water Courses

246. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that level of water courses in fields of village Hullaheri in Gohana Assembly Constituency is not right; if so, the time by which these are likely to be levelled correctly?

माननीय मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): नहीं, श्रीमान जी।

————————————

To Construct Hospital

266. Shri Neeraj Sharma: Will the Ayush Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that approximately 8 acre land of village Kheri Gujran in Faridabad N.I.T. Assembly Constituency has been given to Ayush Department for constructing the Hospital of National Institute of Unani Medicine for non communicable diseases; and

(b) if so, the time by which said hospital is likely to be constructed?

स्वास्थ्य एंव आयुष मंत्री (श्री अनिल विज):
(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) यह एक केन्द्रीय परियोजना है। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धसरकारी पत्र दिनांक 11.02.2021 के द्वारा इस बारे निम्न अनुसार स्थिति सूचित की गई है:–

"आबंटित भूमि क्षेत्र मे यूनानी उपचार सुविधांए स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी भी

नए संस्थान की स्थापना के लिए व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0)/कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक है, इसलिए, उक्त शोध संस्थान का निर्माण कार्य अभी तक शुरु नही हो सका और यह भी बताया गया है कि संबधित एजेसियों से आवश्यक वैधानिक मंजूरी/अनुमोदना प्राप्त होते ही इन सुविधाओं को यथाशीघ्र स्थापित किया जाएगा।"

To Desilt the Minor

247. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that water is not reaching up to the tail of Saragthal Minor; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the abovesaid minor togetherwith the details thereof?

माननीय मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): नहीं, श्रीमान् जी, इसलिए प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता ।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्थगन

11.00 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं एक सूचना यह देना चाहूंगा कि आज सदन की पहली बैठक में एक कॉलिंग अटैंशन मोशन लगा हुआ था लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहीं एक जरूरी बैठक में जाना पड़ गया है इसलिए उस कालिंग अटैंशन मोशन को आज सदन की दूसरी बैठक में टेक–अप किया जायेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैंने आपको हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त हरियाणा के युवाओं की दयनीय स्थिति के बारे में कालिंग अटैंशन नोटिस दिया था। आपने अभी तक मुझे उसके फेट के बारे में नहीं बताया है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि क्या आप आज उसे भी लगा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका यह कालिंग अटैंशन मोशन नामंजूर हो चुका है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मेरे इस कालिंग अटैंशन मोशन को तो आपको स्वीकार करना ही चाहिए था क्योंकि यह तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, माननीय सदस्यों के किसी भी कालिंग अटैंशन मोशन को मंजूर किये जाने या फिर नामंजूर किये जाने का फैसला सरकार के स्तर पर लिया जाता है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैंने भारी बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण बेरी हल्के के समस्त गांवों में फसलों को हुए नुक्सान के बारे में कालिंग अटैंशन नोटिस दिया था, उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैंने आपका वह कालिंग अटैंशन मोशन सरकार के पास 48 घंटे के अंदर–अंदर कमैंट्स देने के लिए भेज दिया है।

———————————

प्रदर्शनकारियों के सम्बन्ध में मामला उठाना

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, कल जब मैंने अपने निवास स्थान पर प्रदर्शन के बारे में यहां पर अपनी बात रखी थी तो उस समय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह कहा था कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में शामिल नहीं था। जब यह 302 का मामला कहा गया था उस समय की मैं फोटोज लेकर आया हूं। इस फोटो में इनकी पार्टी के सारे पदाधिकारी बैठे दिखाई दे रहे हैं जोकि उस प्रदर्शन के समय वहां पर उपस्थित थे। जब धारा 302 की लाईफ थ्रैटनिंग की धमकियां दी गई और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया ये सारी की सारी फोटोज उसी समय की हैं। मैं इन फोटोज को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। इसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के पदों को मैंशन करती हुई फोटोज मैंने हाईलाइट की हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सारे फोटोज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के हैं। इनके साथ ही इनके पदों के नाम भी लिखे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सदन को मिसलीड करती है जबकि ये फोटोज अपनी कहानी खुद व खुद बयां कर रहे हैं। इस प्रकार से ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं तथा इनकी भूमिका दोहरी हो जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः असीम जी, आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि दीप सिद्धू के बारे में भी बताएं कि दीप सिद्धू कौन है, वह भारतीय जनता पार्टी का ऐजेन्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, कल हुड्डा साहब ने सदन में कहा था कि हमारा एक भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नहीं था। मैं जो फोटो लेकर आया हूं

उसमें इनके पदाधिकारियों के फोटो के साथ नाम भी लिखे हुए हैं जो मेरे घर के बाहर धरने पर मौजूद थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, इस फोटो में जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वे सभी किसान हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैंने कई कालिंग अटैन्शन नोटिस दिये थे कृपया उनका फेट बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, कल सदन की कार्यवाही के दौरान हुड्डा साहब ने कहा था कि मेरे घर के बाहर धरना देने वाले लोगों में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। क्या इस प्रकार से वे कार्यकर्ता जान से मारने की धमकी दे सकते हैं? उनको उकसाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः असीम जी, यह जो घटना हुई है इस पर कानून अपना काम करेगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिसने भी गलत हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कल भी पूरा हाउस सुन रहा था और मैंने जो बात कल कही थी वही बात मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा कोई विधायक इस घटना में शामिल नहीं है। हमारे किसी विधायक ने किसानों को नहीं उकसाया है। (शोर एवं व्यवधान)

.....

वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम करण (शाहबाद) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी शाहबाद विधान सभा क्षेत्र का कोई आदमी कोई व्हीकल लेता है तो उसको उस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन व पासिंग के लिए कुरूक्षेत्र रजिस्ट्रेशन अथोरिटी में जाना पड़ता है जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र शाहबाद में भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथोरिटी बना दी जाए जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों के व्हीकल का रजिस्ट्रेशन शाहबाद में ही हो जाए क्योंकि कोई भी आदमी अगर ट्रक, कार व मोटर साईकिल लेता है तो उसको पास करवाने के लिए कुरूक्षेत्र रजिस्ट्रेशन अथोरिटी में जाना पड़ता है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना

पड़ता है। मेरी दूसरी मांग यह है कि शाहबाद में मंजी साहब गुरूद्वारा से काली माता मंदिर, रामनगर तक एक छोटी पुलिया व सड़क बनाई जाए। मेरी तीसरी मांग यह है कि बस स्टैंड के सामने अण्डर पास बनाया जाए क्योंकि वहां पब्लिक को रोड पार करने में बहुत दिक्कत आती है। इसके साथ मैं तालाबों की बात करूंगा कि हरियाणा के अन्दर जितने भी तालाब हैं उनकी खुदाई करके उनकी चार दीवारी होनी चाहिए। उसके साथ ही वहां से एक पाईप लाइन दबाई जाए ताकि किसी किसान को पानी की जरूरत पड़े तो वह किसान उन पाईपों के माध्यम से पानी को अपने खेत में ले जा सके और जो पानी का ऑवरफलो है वह भी उन पाईपों के माध्यम से खेतों में चला जाएगा। उससे न रोड खराब होंगे और न ही गलियां खराब होंगी। इसी के साथ हमारे वहां लाडवा रोड को फॉर लेन किया जाए क्योंकि उसके पास एक शुगरमिल है और उस पर बहुत ट्रैफिक है इसलिए वह रोड फॉर लेन होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा जो अम्बाला से चण्डीगढ़ रोड है वह भी छः लेन होना चाहिए क्योंकि इस पर भी बहुत ट्रैफिक हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरी कुछ और भी मांगे हैं। अगर आपकी सहमति हो तो इनको भी प्रौसीडिंग का पार्ट बना लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अगर आपकी इसके अतिरिक्त कुछ और मांगे हैं तो उनको लिखित में दे दें, उनको प्रौसीडिंग का पार्ट बना लिया जाएगा।

*** श्री राम करण** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह मांग है कि मेरे शाहबाद मारकण्डा विधान सभा क्षेत्र की सभी गाड़ियों की पासिंग शाहबाद मारकण्डा तहसील में ही होनी सुनिश्चित की जाए। दूसरा जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हैं चाहे वे 100 बैठे हैं, चाहे 200 बैठे हैं और हर शहर में बैठे हैं। उनके लिए रिहायशी इलाके में 100–100 गज के प्लॉट दिये जाएं। उनको वे प्लॉट चाहे कमेटी से कटवाए जाएं या सरकार काट कर दे क्योंकि वे सरकारी जमीन में अपनी झुग्गी

———————————————————

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग का पार्ट बनाया गया।**

झोपड़यां बनाकर बैठे हुए हैं। उनमें से जिनके पास प्लॉट नहीं उनको प्लॉट दिये जाएं। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह भी मांग है कि मेरे हल्के में डेरों और ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शन जल्दी से जल्दी दिये जायें ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से एक मांग यह भी है कि मेरे हल्के के जिन–जिन सरपंचों को पिछले दो साल से

मानदेय नहीं मिला है उनको पैंडिंग मानदेय जल्दी से जल्दी दिया जाये। इसी के साथ स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि शाहबाद मारकण्डा में भाड़े पर माल की ढुलाई करने वाले ट्रकों की बहुत ज्यादा संख्या है लेकिन अभी उनकी पार्किंग के लिए शाहबाद में कोई प्रॉपर जगह की व्यवस्था नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि शाहबाद ट्रक यूनियन के लिए शाहबाद में जी.टी. रोड के आस–पास प्रॉपर जगह की अलॉटमैंट करवाई जाये। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में सरकार द्वारा एप्रूव की गई अधिकतर कालोनियों में अभी तक भी बिजली के कनैक्शन नहीं दिये गये हैं । मेरी सरकार से मांग है कि मेरे हल्के में सरकार द्वारा एप्रूड जितनी भी कालोनियां हैं उन सभी में जल्दी से जल्दी बिजली के कनैक्शन दिये जाने का काम किया जाये। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस मंच पर जनहित की एक बहुत बड़ी मांग माननीय उप–मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वे समय की मांग को देखते हुए चण्डीगढ़ से अम्बाला रोड, जो अभी फोर लेन का है, उसको सिक्स लेन बनाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। स्पीकर सर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इन सभी मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनके ऊपर जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्यवाही करवायेगी। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कुछ विधायक ऐसे हैं जो अभी तक राज्यपाल जी के अभिभाषण या बजट पर नहीं बोल पाए हैं तो मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि उन विधायकों को कम से कम बजट पर बोलने का अवसर अवश्य दिया जाए।

श्री धर्म सिंह छौक्कर (समालखा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ही वित्त मंत्री हैं और उन्होंने वर्ष 2021–22 का जो बजट रखा है वह किसान, व्यापारी, कर्मचारी और जनता के हित में नहीं है। यह ठीक है कि बजट पेश भी हुआ और बजट पास भी हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि बजट पर माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बजट के आंकड़े भी बताए गये और जमा–घटा भी की गई। मैं यह कहना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में बजट में जितना प्रावधान दिया गया है और जो पैसा जिस हैड में दिया गया है उस पैसे को अच्छे से इम्प्लीमैंट किया जाए। चाहे सरकारी परियोजनायें कांग्रेस की सरकार के समय की हों या इस सरकार की हो, जो विकास परियोजनायें अधूरी पड़ी हैं, उनको

प्रायरिटी के हिसाब से आगे बढ़ाने का काम किया जाये और आगे दौड़–पीछे छोड वाली प्रवृत्ति पर काम नहीं करना चाहिए। हमारे चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय हमारे यहां हथवाला–बिलासपुर व कुरड़ी–नांगला पुल की नींव रखी गई थी लेकिन इसको आज आठ साल का समय बीत चुका है, अत निवेदन है कि इस काम को जल्द पूरा करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्रोजैक्ट्स हैं, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे हैल्थ, व्यापार या फिर कृषि के ही क्यों न हो, इन सभी क्षेत्रों के अधूरे कामों को पूर्ण करने का काम किया जाये। जहां तक हैल्थ एजुकेशन की बात है, हुड्डा साहब के कार्यकाल में 10 यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया गया लेकिन अब केवल मात्र घोषणायें ही की जाती हैं। हमारे बरोदा में मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी लेकिन आज वह घोषणा, केवल मात्र घोषणा ही बनकर रह गई है क्योंकि यहां से कांग्रेस का विधायक जो बन गया है। मेरा निवेदन है कि इस तरह का भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा एक–हरियाणवी एक जहां तक यूनिवर्सिटीज की बात है या फिर कालेजिज की बात है, यह सरकार नए कालेजिज खोलने का काम तो करती है लेकिन यहां पर सुविधायें देने का काम नहीं करती है। आज कालेजिज में लैक्चैरर नहीं हैं और कोई दूसरा इंफ्रॉस्ट्रक्चर या दूसरी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक एडिड कालेजिज की बात है गवर्नमैंट की तरफ से इनको 95 परसेंट तक गवर्नमैंट एड दी जाती है, के मद्देनज़र मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि हमारे यहां एडिड कालेजिज के साथ–साथ, गवर्नमैंट कालेज भी बनाया जाये और उनका अच्छा रखरखाव किया जाये। जहां तक हैल्थ की बात है, जब माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय समालखा में 100 बैड का हस्पताल बनाया गया था और जैसाकि सदन के एक सदस्य श्री नरेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो कहते हैं, करके दिखाते हैं, के ध्यानार्थ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस 100 बैड के हस्पताल में डाक्टर्ज डेप्यूट किए जायें तथा इस हस्पताल को एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन तथा अन्य प्रकार के सभी इंफ्रॉस्ट्रक्चर के साथ सुसज्जित किया जाये। आज यहां पर केवल मात्र डिलीवरी केसिज होते हैं और वह भी केवल मात्र डिलीवरी हट में ही होते हैं। यह हस्पताल चंडीगढ–दिल्ली हाईवे पर पड़ता है और यदि यहां पर ट्रामा सैंटर भी बना दिया जाये तो विपरित परिस्थितियों में यह हस्पताल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बहुत काम आ सकता है।

वर्तमान में यहां पर केवल मात्र तीन डॉक्टर्ज ही उपलब्ध हैं। अतः सर्वप्रथम डाक्टर्ज की संख्या को बढ़ाने का काम जल्द से जल्द किया जाये। जहां तक शुगर मिल की बात है। चौधरी भूपेंन्द्र सिंह हुड्डा ने आठ साल पहले पानीपत शुगर मिल की नींव रखी थी लेकिन आज तक यह अधूरी पड़ी है। इस शुगर मिल का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाये। हमारे किसानों की इतनी बुरी दुर्दशा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश या पंजाब में गन्ना लेकर जाना पड़ता है। पिछले सैशन में भी मैंने इस बारे में आवाज उठाई थी। हमारे यहां एक गांव है इकबालपुर जहां के किसानों के गन्ने का 36 करोड़ रूपया पिछले तीन साल से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में लंबित पड़ा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को इस 36 करोड़ की राशि को रिलीज करने संबंधी एक पत्र लिखा जाये। जहां तक विकास परियोजनाओं की बात है के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हमारा समालखा पिछले 50 साल से आयरन फाउंड्री के क्षेत्र में न 1 है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर वित्त मंत्री कहा है कि इस बार टैक्स फ्री बजट पेश किया है। समालखा में आयरन फाउंड्री पूरे एशिया में नं01 पर है। चारा काटने वाली मशीन पर पहले कोई भी टैक्स नहीं लगता था लेकिन इस सरकार ने इस मशीन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगा दिया। वर्ष 2017 में इसी सरकार में 12 प्रतिशत जी.एस.टी. और लगा दिया और मशीन के पार्ट्स के ऊपर 18 प्रतिशत टैक्स लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि इस बार टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है। (घंटी) सरकार ने डार्क जोन में ट्यूबवैल कनैक्शंज खोल दिये हैं, यह अच्छी बात है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हरियाणा और यू.पी. यमुना नदी पर जमीन विवाद को लेकर रहती है। इस संबंध में हमारी सरकार के समय दिक्षित अवार्ड हुआ था और दिक्षित अवार्ड के तहत अभी तक पिल्लर स्थापित नहीं किये गये। अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि हरियाणा और यू.पी. के किसानों का यमुना नदी पर जो जमीन विवाद रहता है, उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाये। धन्यवाद।

श्री बिशम्बर सिंह (बवानी खेड़ा) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका बहुत–बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

'कुछ तो फूल खिलाये हमने, कुछ और खिलाने बाकी हैं,

मुश्किल है इस बात में अब तक, कांटे कई पुराने हैं।'

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021–22 के लिये बहुत ही सुंदर, सुनहरा और प्रगतिशील बजट पेश किया है, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बार ऐसा बजट बनाया है जिसके माध्यम से किसान, मजदूर, कमेरा, मेहनतकश व दलित समाज को उभरने का पूरा–पूरा मौका मिलेगा। इस बार हरियाणा का 1 लाख 55 हजार 645 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है जोकि पिछली बार से 13 प्रतिशत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इससे अच्छा बजट हरियाणा के हित में नहीं हो सकता है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार ने बुढ़ापा सम्मान पैंशन 2500 रुपये प्रति महीना कर दी है जो देश में सबसे अधिक है। प्रदेश में 4000 आंगनवाड़ी केन्द्र प्ले–वे स्कूल्ज अपग्रेड होंगे। बजट में कृषि कल्याण के लिये 2998 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंचाई की व्यवस्था के लिये 5081 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास के लिये 868 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खेल को बढ़ावा देने के लिये 7731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रोजगार के लिये 884 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के लिये 71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परिवहन विभाग के लिए 2,865 करोड़ रुपये, जन–स्वास्थ्य विभाग के लिए 3,402 करोड़ रुपये, शिक्षा विभाग के लिए 18,410 करोड़ रुपये, बिजली विभाग के लिए 7,089 करोड़ रुपये, नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 183 करोड़ रुपये, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए 2,985 करोड़ रुपये, सैनिक एवं अर्द्ध–सैनिक बल के लिए 143 करोड़ रुपये, पुलिस विभाग के लिए 5,779 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक गरीब वाल्मिकी परिवार में पैदा हुआ और गांव में ही पढ़ा–लिखा हूं । मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा हुआ है । समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा के फलस्वरूप ही मैं इस सदन में दूसरी बार विधायक बनकर पहुंच पाया हूँ । अध्यक्ष महोदय, मनुष्य जिन हालातों से गुजरा हुआ होता है वह उन हालातों को कभी भूल नहीं सकता । यह मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि भेड़–बकरी की गिनती करने वाला गरीब परिवार का लड़का आज इस सदन का

सदस्य बनकर आकंड़ों की गिनती कर रहा है और फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट पढ़ता हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में वे बहन–बेटियां आती हैं जिनको पानी के लिए टोकनी–बाल्टी लेकर कई–कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था । मेरे जहन में वे गरीब बच्चे आते हैं जिनके मां–बाप के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते थे और वे जैसे–तैसे करके अपने बच्चों की फीस देते थे । मेरे जहन में वे गरीब भाई आ जाते हैं जिनके मकान गलियों से तीन–तीन चार–चार फुट नीचे तक चले गए हैं और मैं गांव की उन गलियों के बारे में विचार करने लगता हूँ जहां पर चलना भी मुश्किल हो जाया करता था । अध्यक्ष महोदय, मैंने सामाजिक पीड़ा को झेला है, इसलिए मैं एक अच्छे बजट की अहमियत भी समझता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो दूरदृष्टि, सही दिशा और संकल्प के साथ यह बजट बनाया है इससे हर वर्ग का विकास होगा । पहले केवल एक किलोग्राम चावल और तीन किलोग्राम गेहूं देकर गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और बड़ी–बड़ी बातें कही जाती थी । मैं कहना चाहता हूँ कि एक महीने में कोई आदमी केवल एक किलोग्राम चावल और तीन किलोग्राम गेहूं खाकर जिन्दा रहकर तो दिखाए । अध्यक्ष महोदय, ऐसा करके केवल मात्र गरीबी और निर्धनता का उपहास करने का ही काम किया जाता था । अगर गरीबों का कल्याण करना विपक्ष के लोगों के बस में नहीं है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे छह महीने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास आकर ट्रेनिंग ले लें । उनको पता चल जायेगा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किस प्रकार किया जाता है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब तक दिशा और दृष्टि ठीक नहीं होगी तब तक संकल्प के साथ काम नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के समय में जो बजट पास हुआ करते थे क्या उनमें कभी आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, धार्मिक विषमता या प्रशासनिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया गया ? अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रयास पहले कभी नहीं किया गया । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में ईमानदारी व योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया गया है । पिछली सरकारों के समय में एक–एक परिवार के सात–आठ सदस्यों को नौकरी मिल जाती थी और कुछ परिवार ऐसे भी होते थे जिनमें एक सदस्य को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद और नमन करता हूँ कि उन्होंने ईमानदारी से काम

करते हुए पढ़े–लिखे योग्य युवाओं को सरकारी सेवाओं में आने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, अब हरियाणा प्रदेश में नौकरी के लिए कोई अपनी जमीन नहीं बेचता है और न ही कोई अपना कुछ गिरवी रखता है। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे योग्य युवाओं को नौकरियों मिली हैं जिनकी मां सुबह चार बजे उठती थी ताकि उनके बच्चों को बड़े होकर काम धंधा मिल सके। आज उन माताओं के सपने साकार करने का काम इस मनोहर सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक खेल नीति की बात है। यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा खेल मंत्री जी की बेहतरीन खेल नीति का ही नतीजा है कि जहां पहले खेल के मैदान में हमारे युवा खेलने तक के लिए नहीं जाते थे, आज उन्हीं खेल के मैदानों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। आज हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी देश–विदेश और प्रदेश में निरन्तर विकास के नए आयाम छूते जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा खेल मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज प्रदेश में कहीं पर बिजली की लटकती हुई तारें दिखाई नहीं देंगी। यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की दूर दृष्टि का ही कमाल है। अध्यक्ष महोदय, आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5080 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है और वर्ष 2021–22 में प्रदेश के जितने भी गांव बचे हुए हैं, वहां पर भी 24 घंटे बिजली देने के प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि वे हमारे कोमल–हृदय वाले मुख्यमंत्री जी को कमजोर न समझें। वे दूसरे बड़बोले लोंगों की तरह लंबी–लंबी फेंकने में विश्वास नहीं रखते बल्कि चुपचाप हरियाणा प्रदेश की भलाई करने में लगे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि–

परिदों को मिलेंगी मंजिल एक दिन,
ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं,
वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर,
जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जयवीर जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य को अपनी बात रखनें दें।

श्री बिशम्बर सिंहः अध्यक्ष महोदय, भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत –बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पंडित नेकीराम शर्मा जी मुलतः कलिंगा गांव से संबंध रखते थे। खरक और कलिंगा गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो बड़े गांव हैं। उस जमाने में पंडित नेकीराम शर्मा जी ने छूआछूत को मिटाने का बीड़ा उठाया था और उसकी शुरूआत कंलिंगा गांव से की थी। वे उस वक्त हरिजनों के बच्चों को अपनी गोदी में उठा लेते थे। इस महान् स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम जी के नाम से भिवानी में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त सरकार ने तिगड़ाना गांव के पुरातात्विक स्थल को अपने संरक्षण में लेने की पहल की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि यह मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय में बनना मंजूर हुआ था, इसलिए इसके लिए माननीय सदस्य को कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी की सरकार के समय पर इसका कुछ भी कार्य नहीं हुआ था। इस मेडिकल कॉलेज के बनाने का प्रोसैस हमारी सरकार के समय पर मैंने ही शुरू करवाया है। इनकी पार्टी की सरकार के समय पर तो माननीय सदस्या का मुंह बन्द रखने के लिए ही यह घोषणा की गयी थी। उस समय फाइलों पर इसको बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। मैंने ही इसको बनाने के लिए सारा प्रोसैस शुरू करवाया था।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की सरकार के समय में वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गयी थी।

श्री अध्यक्षः बिशम्बर जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री बिशम्बर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। तिगड़ाना में एक पुरातात्विक स्थल सरकार ने अपने संरक्षण में लिया है। वहां पर डॉ0 नरेन्द्र सिंह परमार द्वारा खुदाई करके 5,000 वर्ष पुरानी नगरीय सभ्यता की

खोज की गयी है। डॉ0 नरेन्द्र सिंह परमार ने वहां पर रहने वाले लोगों के रहन–सहन, खान–पान, आभूषणों और पालतू पशुओं के बारे प्रकाश डाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर एक म्यूजियम बनवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मेरे हल्के की कुछ मांगें भी रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः बिशम्बर जी, अगर इसके अतिरिक्त आप कोई और बात कहना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखित में दे दें।

श्री बिशम्बर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में ही अपने हल्के की मांगों के बारे में बता दूंगा। वैसे भी मैं बहुत कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिशम्बर जी, आप लिखित में अपनी स्पीच दे दीजिए उसको कार्यवाही का हिस्सा बना लिया जायेगा।

श्री बिशम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे बवानी खेड़ा क्षेत्र में सुन्दर नहर का पानी प्रत्येक महीने कम से कम एक सप्ताह जरूर दिया जाये। खरक कलां में कॉलेज का निर्माण करवाया जाये। यह गांव भिवानी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिरसा घोघड़ा माइनर का निर्माण करवाया जाये क्योंकि इसकी सी.एम. अनाउंमैंट हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : बिशम्बर जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

श्री बिशम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। केवल एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं। (विघ्न)

श्री बिशम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कभी–कभी तो बोलता हूं। मैं माननीय सदस्या किरण जी को कहना चाहूंगा कि जब अगली बार इनके बोलने की बारी आयेगी तो मैं अपना समय भी माननीय सदस्या को दे दूंगा। गांव खरक कलां में पी.एच.सी. बनाई गई है उसको सी.एच.सी. बनाया जाये। गांव खरक कलां को सब–तहसील का दर्जा दिया जाये। गांव कलिंगा में लगभग 2 हजार एकड़ भूमि पर खेती हर साल पानी के कारण बर्बाद हो जाती है इसलिए यहां पर ड्रेन की व्यवस्था करवाई जाये। बवानी खेड़ा शहर में खेल इनडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाया

जाये। बवानी खेड़ा में आई.टी.आई. का निर्माण करवाया जाये और खरक कलां में फोर लेन हाइवे है उस पर फ्लाई ओवर बनाया जाये क्योंकि इस रोड पर कई गांवों के लिंक रोड मिलते हैं जैसे मालपास, कलिंगा चांग, सकरोड, बोंद यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर बाइपास की जगह नहीं है इसलिए फ्लाई ओवर का निर्माण करवाया जाना उचित है।

श्री अध्यक्ष : बिशम्बर जी, अब प्लीज आप वाईंड–अप करें।

श्री बिशम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग का पार्ट बनाना चाहता हूं और वाईंड–अप करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप लिखकर दे दीजिए उसे प्रौसीडिंग का पार्ट बना दिया जायेगा।

***श्री बिशम्बर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त यह कहना चाहूंगा कि बवानी खेड़ा से तोशाम रोड फाटक पर फ्लाई ओवर बनाया जाये। बवानी खेड़ा में फाटक 65–सी पर अंडर पास बनाया जाये। गावं तिगड़ाना में हड़प्पा स्थल बनाया जाये। खरक से कलिंगा रोड का नाम शहीद राजबीर सिंह के नाम पर रखा जाये। कलिंगा में पी.एच.सी. बनवाई जाये।

श्री इन्दु राज (बरौदा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री होने के नाते बजट को पढ़ा। मैंने भी ध्यानपूर्वक इस बजट को सुना और पढ़ा भी। मैं इस बजट से असंतुष्ट हूं क्योंकि मैं हरियाणा विधान सभा में बजट सत्र के माध्यम से बहुत सी बातें कई दिनों से सुन रहा हूं। चाहे वह सरकार के माननीय मंत्री हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों और चाहे माननीय उप–मुख्यमंत्री हों। इनकी तरफ से किसानों के नाम पर केवल और केवल छाती पीटने का काम किया जा रहा है लेकिन इस बजट के अंदर किसान के लिए कुछ नहीं किया गया है।

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

दिल्ली बॉर्डर पर पिछले लगभग 4 महीनों से किसान धरने पर बैठा हुआ है और वहां पर 300 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। जो किसान शहीद हो गये हैं इस बजट में उनके परिवारों के लिए सरकार ने कुछ भी देने का काम नहीं किया है। मैं सबसे पहले हमारे नेता प्रति पक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने प्रदेश के किसानों के प्रति अपनी संवदेना व्यक्त की

और शहीद हुए किसानों के परिवार वालों को दो–दो लाख रुपये देने की घोषणा की और घोषणा ही नहीं बल्कि उनके घर जाकर हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों और माननीय दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी द्वारा उनको दो–दो लाख रुपये देने का काम भी किया। हमारी कांग्रेस पार्टी ने किसानों का दर्द समझा इसलिए समझा क्योंकि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी किसान के बेटे भी हैं और खुद एक किसान हैं । **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो किसान शहीद हुए हैं, उन परिवारों को 50–50 लाख रुपये और उनके परिवार में एक–एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम भी करे। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के से चार किसान शहीद हो गये हैं उनमें श्री अजय मोर, बरोदा, श्री कुलवीर देशवाल, गंगाना, श्री दिलबाग सांगवान, कोहला और राजेश कुमार, मंदीना से थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अजय मोर के बारे में इस सदन में बताना चाहूंगा। श्री अजय मोर की 32 साल की उम्र थी और उसकी तीन बेटियां हैं। दो बेटी 6 साल की हैं क्योंकि ये दोनों बेटियां जुड़वा पैदा हुई थी और एक बेटी एक साल की है लेकिन उसकी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वह भविष्य में अपने परिवार की देखभाल कर सके। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उसकी पत्नी को कोई भी सरकारी नौकरी देने का काम करे ताकि वह अपने परिवार और तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में माननीय दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का जिक्र करना चाहूंगा। इन तीन काले कानूनों के बारे में संसद के किसी भी सांसद ने आवाज नहीं उठाई, चाहे वह हरियाणा का सांसद हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सांसद हो और चाहे वह दिल्ली का सांसद क्यों न हो? माननीय दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने संसद सत्र के दौरान किसानों की आवाज उठाने का काम किया और इन तीनों काले कानूनों में क्या–क्या खामियां हैं, उनके बारे में भी बताया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चाहे संसद सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से तीनों काले कानूनों के बारे में सवाल पूछा हो या फिर लोकसभा में माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा हो, उन्होंने इनके एक–एक सवाल का जवाब देने का भी काम किया। डिप्टी स्पीकर सर, मैं अपने माननीय चौधरी दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि वे इस किसान आंदोलन के दौरान लगातार किसानों के बीच में जाते रहते हैं। चाहे वह जगह कहीं के भी टोल गेट हों, चाहे सिंघू बॉर्डर हो या फिर चाहे टीकरी बार्डर ही क्यों न हो। सरकार के विधायकों, मंत्रियों

और मुख्यमंत्री के स्तर पर इस प्रकार के ब्यान हमें निरंतर सुनने को मिल रहे हैं कि उनको प्रदेश की जनता द्वारा गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। कोई यह भी कह रहा है कि सरकार के बहुत से विधायकों को उनके हल्के में भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। मैं पूरी सरकार से यही रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि सरकार भी माननीय सांसद श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी की तरह किसानों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुने और जल्दी से जल्दी उनका समाधान निकालने का प्रयास करे। मैं भी अपनी पार्टी के माननीय सांसद श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी की तरह किसानों के धरनों के स्थल पर जाता हूं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं वहां पर विधायक की हैसियत से नहीं जाता बल्कि मैं वहां पर एक किसान का बेटा बनकर जाता हूं। मैं एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा कि जब माननीय सांसद श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी जब–जब भी किसानों के बीच में गये हैं तो हर बार सभी किसान भाईयों ने उनका फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया है। किसान भाईयों ने उनका स्वागत इसलिए किया क्योंकि वह किसान का बेटा है और किसान के दुख तकलीफों को समझता है। इतना ही नहीं उन्होंने संसद में भी किसानों की आवाज को उठाने का काम किया है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री इंदू राज नरवाल जी को यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसको ये और इनकी पार्टी के लोग ही तो करवा रहे हैं। (विघ्न) जिस समय इस हाउस के एक माननीय सदस्य का अपमान किया जा रहा था और उनको धमकी दी जा रही थी उस समय इनकी पार्टी के प्रवक्ता श्री देवेन्द्र बजाज, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री तरूण चुघ, इनकी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री देवेन्द्र पुनिया, कोषाध्यक्ष श्री रोहित जैन, एक्स एम.सी. श्री अरविन्द्र पुनिया और एक दूसरे एक्स एम.सी. श्री देवेन्द्र देवपा, ये सारे के सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। क्या श्री इंदू राज नरवाल जी यही कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसके कर्ताधर्ता ये और इनकी पार्टी के सभी लोग ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री इंदू राज नरवाल जी मेरे सभी सवालों का जवाब दें। अभी श्री विशम्बर बाल्मिकी जी ने यह कहा कि इंदू नरवाल जी की पार्टी ने हरियाणा में से विषमता को दूर करने के बारे में कभी विचार नहीं किया। मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में से विषमता दूर करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती बल्कि इसके उल्टा इन्होंने

सदा–सदा ही हरियाणा प्रदेश में नये–नये तरीकों से विषमता पैदा करने का ही प्रयास किया है। इस प्रकार की दोगली सोच और दोगले आचरण के साथ ये हरियाणा प्रदेश से विषमता को दूर कर ही नहीं सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में श्री भूपेन्द्र हुड्डा जी सबसे सीनियर व्यक्ति हैं। मेरे विचार में नेता प्रतिपक्ष से सीनियर व्यक्ति यहां पर कोई भी नहीं है। मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारा संविधान किसी का बॉयकाट करने की इजाजत देता है? अगर यह सब गैर–कानूनी है तो फिर हुड्डा साहब चुप क्यों बैठे हैं? उपाध्यक्ष जी, हुड्डा जी को ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए बल्कि इनको तो समाज का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए और अगर प्रदेश में कोई वर्ग गलत रास्ते पर चलता है तो उसको रोकने का काम करेंगे लेकिन हुड्डा साहब तो उपद्रव करने वालों और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को डॉयरैक्ट और इनडॉयरैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस विषय पर सदन में कल बात हुई थी आज फिर उसके बारे में चर्चा की है। हमने यह बात पहले भी कही है, कल भी कही थी और आज फिर से कह रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी जिस किस्म से बात करते हैं वह हम सभी की समझ से परे है। प्रदेश में चाहे कोई किसी को भी जान से मारने की धमकी दे वह पूरी तरह से गलत बात है और प्रदेश में किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का काम किया है तो सरकार को उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। अगर किसी ने हिंसक प्रदर्शन किया है तो वह कानून व्यवस्था का सवाल है। हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी ही चाहिए। यह कार्यवाही करना सरकार का काम है न कि असैम्बली का काम है।

श्री कंवर पाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा हुड्डा साहब को यह कहना है कि उनका कहना सिर्फ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का कहना नहीं है बल्कि हुड्डा साहब इनकी पार्टी के हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज हैं। डिप्टी स्पीकर सर, जो फोटोग्राफ्स श्री असीम गोयल ने आज सदन के पटल पर रखे थे उनमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उन फोटोग्राफ्स में सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, संसदीय कार्य मंत्री का बात करने का यह कोई सही तरीका नहीं है। इनको इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए।

क्या इस प्रकार से सदन की कार्यवाही चल सकती है? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सरकार अपनी विफलताओं को दूसरों पर डालने की कोशिश कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा कि समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी इस हाउस की है। चाहे कोई सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में बैठा हो। कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, इतनी संवेदनहीनता मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखी। किसान आंदोलन में 300 आदमी अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, वे अपनी शहादत दे चुके हैं लेकिन सरकार के मुंह से उनके प्रति संवेदना का एक शब्द भी नहीं निकला है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके परिवार में गुजारे के लायक भी कुछ नहीं है लेकिन सरकार ने उनके प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि किसानों के हित के लिए अपनी जान दी है तो सरकार किसानों के प्रति सहानुभूति के दो शब्द तो बोल ही सकती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले ज्यादातर बुजुर्ग थे। लेकिन हुड्डा साहब ने वहां पर जा कर उनको कभी नहीं समझाया कि ताऊ या चाचा जी आप घर जाओ। ये तो इंतजार कर रहे थे कि कब उनके साथ दुर्घटना घटे और वोट बटोरने का मौका मिले। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात रिकॉर्ड पर लेकर आना चाहती हूं कि प्रजातंत्र में बायकॉट करना लोगों की विल का मैनिफैस्टेशन है against the political dispensation. सरकार प्रजातंत्र का गला घोट कर बिल्कुल मारना चाहती है। अगर लोग राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट होंगे तो वे बायकॉट ही करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र का गला घोटने का काम तो इनकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये संवाद को खत्म करके प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जिन किसानों के घर के चिराग बुझ गये उनके प्रति थोड़ी बहुत तो संवेदना सरकार की तरफ से प्रकट की जानी चाहिए थी लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार इतनी संवेदनहीन नहीं होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य पहली बार चुन कर विधान सभा में पहुंचा है और सरकार की तरफ से बार–बार उसको डिस्ट्रब किया जा रहा है। यह इनकी मेडन स्पीच है और इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कादियान जी, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। हर बात पर रूलिंग नहीं हुआ करती है। अब आप बैठ जाइये। इंदुराज जी आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री इंदु राजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज किसान केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के विरोध में बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनको मच्छर, मक्खियों से बचाव और टॉयलेट की बहुत बड़ी दिक्कत है उसको दूर किया जाये। उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है इसलिए सरकार उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन हरियाणा के बोर्डर पर बैठे किसानों ने शाहदत दी है, उन सभी गरीब किसानों के परिवारों में एक–एक नौकरी देने का काम करे और उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए। मैं श्री श्रीकृष्ण हुड्डा जी को याद करना चाहूंगा और मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने का काम भी करूंगा। इसके साथ ही मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा क्योंकि मेरा जो पहला सवाल लगा है उसके लिए उप–मुख्यमंत्री जी ने मेरा धन्यवाद व स्वागत भी किया है लेकिन इनकी करनी और कथनी में भी फर्क है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि श्री श्रीकृष्ण हुड्डा जी के समय में विधायक ग्राम विकास योजना के तहत जो साढ़े छः करोड़ रुपये की ग्रांट की घोषणा की गई थी उनकी उस डिमांड के करीब साढ़े छः करोड़ रुपये के ऐस्टीमेट्स बनकर आ चुके हैं। वे आज धरती पर नहीं स्वर्ग में हैं। सरकार उनके समय में की गई घोषणाओं को सुनने का काम जरूर करे। उनके नाम से जो ग्रांट

व ऐस्टीमेट्स आए हैं उनको भी सरकार देने का काम करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि हल्का बरौदा का अभी–अभी चुनाव हुआ था। उस समय सभी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री ने बरौदा हल्के में जाने का काम किया था। उन्होंने वहां छाती ठोक कर गली–गली में घूमकर बड़े–बड़े वायदे किये थे। मैं उन वायदों को याद दिलाना चाहूंगा और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप मेरे बरौदा हल्के में जो घोषणाएं व वायदे करके आए हुए हैं उनको पूरा करने का काम करें। जैसे वहां आई.एम.टी. बनाने की बात भी रखी गई थी कि सरकार बरौदा हल्के में आई. एम.टी. बनाने का काम करेगी, दो–दो गर्ल्ज कॉलेज बनाने की बात की गई थी जिनका मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रैंस के जरिये उद्घाटन भी किया है। हमारे वहां राईस मिल लगाने की बात भी की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे इन वायदों को पूरा करें। सरकार अगर अपने इन वायदों को पूरा करेगी तो यह हरियाणा प्रदेश की जनता आप पर विश्वास करेगी, नहीं तो ऐसे ही होगा जैसे अब हो रहा है कि कोई आपको गांव में घूसने नहीं देगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं पूरे हरियाणा और हल्का बरौदा की जनता की तरफ से कहना चाहूंगा और मेरे पास अखबार की ये सभी कटिंग्ज हैं कि जब–जब सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री व उप–मुख्यमंत्री मेरे बरौदा हल्के में गये और वहां जो–जो वायदे करके आए थे वे उनको पूरा करने का काम करें। मैं दोबारा से फिर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जब मैंने शपथ ली उससे दो दिन पहले मीडिया में भी ब्यान आया था कि अगर इंदुराज जी मेरे पास आएंगे तो मैं उनके काम करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इंदुराज मुख्यमंत्री जी के पास ही नहीं मंत्री के पास भी जाएगा और उप–मुख्यमंत्री के पास भी जाएगा और संतरी के पास भी जाएगा लेकिन सरकार ने बरौदा हल्के में जो भी वायदे किये थे उनको पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। जयहिन्द।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की मेड इन स्पीच थी इसलिए मैंने इनको बीच में टोका नहीं। उन्होंने एक सांसद के बारे में बात रखी है। माननीय सदस्य की उस बात को एडिट किया जाए अब वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे, अब वे राज्यसभा में आ चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पुंडरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर जो किसानों की भलाई व सिंचाई के लिए प्रावधान किए हैं, मैं सर्वप्रथम उन पर बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जल जीवन की वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है और वर्तमान में जल संरक्षण की महता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जल है तो जीवन है। उपाध्यक्ष महोदय, बिना जल के न मनुष्य का काम चल सकता है और न ही किसी पशु या पक्षी का काम चल सकता है। कहने का मतलब यह है कि जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, किसान के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सक्षम योजना के माध्यम से जो हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इससे निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र का बेहतरीन ढंग से विकास होगा और यह क्षेत्र और अधिक सुदृढ़ होता चला जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2021–22 के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के चार जिले महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद की प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए बजट के माध्यम से पानी का प्रावधान व किसान का भला करने के जिस अनूठे कार्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री की भूमिका का बेहतरीन ढंग से निवर्हन करते हुए, अपने बजट में स्थान दिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साधुवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बजट के माध्यम से तालाबों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष योजना बनाई है। चाहे सीवरेज पाइप लाइन बिछाने की बात हो, चाहे जल को तालाब में डालने की बात हो, चाहे ड्रेन्ज को पक्का करने की बात हो, चाहे तालाब की खुदाई करने की बात हो, चाहे बांध का निर्माण करने की बात हो या फिर चाहे तालाब के किनारों पर घास ट्रैक बिछाने की बात ही क्यों न हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन सब प्रावधानों के साथ–साथ सूक्षम सिंचाई, मछली पालन तथा तालाब के पानी की गुणवत्ता में सुधार जैसे अनूठे कार्यों को भी बजट में विशेष स्थान देने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब प्रावधानों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाबार्ड के तहत जो माइक्रो सिंचाई कोष योजना बनाई है।

इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जोकि वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाले हुए हैं, को एक सुझाव देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो माइक्रो सिंचाई कोष योजना पूरे हरियाणा प्रदेश में लागू की गई है तो विशेषतौर से जो काडा डिपार्टमैंट है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, काडा डिपार्टमैंट ने सूक्ष्म योजना के तहत स्प्रिंकलर्स सिंचाई की योजना बनाई है। कैथल, करनाल, पानीपत, कुरूक्षेत्र आदि जिलों में नाबार्ड स्कीम के तहत हमारे जो खाले होते हैं, उनके नीचे पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाये क्योंकि यह योजना हमारे क्षेत्रों में कामयाब नहीं होती है। हमारे क्षेत्रों में धान की फसल बहुत ज्यादा होती है और इसके लिये हमारे किसान भाइयों को खुले पानी की आवश्यकता पड़ती है। धान की पैदावार ज्यादा होगी तभी हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। सरकार ने पानी के संरक्षण, पुनः उपयोग, रिचार्ज और रिसाइक्लिंग पर बल देने का काम किया है। आज प्रदेश में 300–350 फीट तक भूमिगत जल चला गया है। आज भूमिगत जल तेजी से घट रहा है, उसको रोकने में हम कामयाब हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यमुना नदी में मानसून अवधि के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता बढ़ाने और सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने समानान्तर दिल्ली शाखा, संवर्धन नहर, जवाहर लाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा के पुनरोद्धार की परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई हैं। इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात भी सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार रिसाव और अन्य नुकसानों को नियंत्रित करके तथा नहरों की वहन क्षमता को बढ़ाकर राज्य में पुराने जीर्ण–शीर्ण सिंचाई नहरी तंत्र का पुनरोद्धार करने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 110 चैनलों का पुनरोद्वार कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सरकार रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, चरखीदादरी, और भिवानी में उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार पर विशेष बल देकर दक्षिणी हरियाणा के प्रत्येक टेल तक पानी पहुँचाने के लिये प्रतिबद्ध है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी इस महान सदन से यह भी कहना चाहता हूँ कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया है, इसके लिये भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर पर बहन किरण चौधरी जी राजनीति न करके बल्कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सरकार के साथ मिलकर पानी को लाने का काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष

12:00 बजे

महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.वाई.एल. नहर के संबंध में हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एस.वाई.एल. नहर के ऊपर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा हुआ है कि सरकार विपक्ष को भी एस.वाई.एल. नहर के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी के पास लेकर जाये ताकि हमें हमारे हक का पानी मिल सके। कांग्रेस पार्टी के सदस्य तो कब के इस इंतजार में बैठें हुए हैं कि कब सरकार दिल्ली लेकर जाये लेकिन सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर राजनीति तो सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है जो इस मुद्दे के ऊपर झूठे उपवास रखते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को करैक्ट करना चाहती हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर बहुत ही अच्छी बात कही है कि कांग्रेस पार्टी सदन के साथ है। कांग्रेस पार्टी पहले तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। कांग्रेस पार्टी को अपने चुनावी घोषणा पत्र पर तो विश्वास होना चाहिए क्योंकि पंजाब राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही कहा है कि एस.वाई.एल. नहर का निर्माण नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पहले अपनी ही पार्टी में चर्चा कर ले कि वो एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिये तैयार है या नहीं। हमारी सरकार पूरी तरह से एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिये तैयार है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

श्री किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में जब माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय विधान सभा के सदस्य नहीं थे तो उस समय एस. वाई.एल. नहर के विषय पर एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी । उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने मिलकर यह तय किया था कि हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलेंगे और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनसे इस बारे में आग्रह करेंगे । हम इस विषय पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इसके लिए पिछले 6 साल से इंतजार ही कर रहे हैं । इस बात का माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को पता नहीं है ।

श्री राम कुमार गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो कैप्टन अमरिन्द्र सिंह ने विधान सभा में एक रेजोल्यूशन

पास करवाया था कि वे हरियाणा को एक बून्द पानी भी नहीं देंगे । इसके बाद उस खुदी खुदाई नहर को पंजाब में कई जगहों पर आट दिया गया था और कई जगहों पर नहर के लिए दी हुई जमीन किसानों को वापिस दे दी गई थी । हरियाणा और पंजाब में अभी ताजा–ताजा भाईचारा बना है । पंजाब को बड़ा भाई और हरियाणा को छोटा भाई कहा जा रहा है । ऐसे में मेरा कहना है कि हरियाणा के किसान को पंजाब के किसान से कहना चाहिए कि भाई, तुम सबसे पहले एस. वाई.एल. नहर को खुदवाओ बाकी बात तो बाद में करेंगे । इसके अलावा जहां तक संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कहा गया कि सरकार के मंत्रियों और माननीय सदस्यों को इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के वर्करों द्वारा जनसभा करने से रोका जा रहा है तो इस पर मेरा कहना है कि लॉ एण्ड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम सरकार का है । यह काम विपक्ष का नहीं है । विपक्ष तो रोड़ा अटकाएगा और जितना ज्यादा बिघन कर सकता है उतना करेगा लेकिन सरकार में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह जनता का स्वयं पर विश्वास बहाल कर सके ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में अपने आपको शामिल नहीं करना चाहता था लेकिन इस समय हाउस को एस.वाई.एल. नहर के विषय पर गुमराह किया जा रहा है । यह बात सही है कि पंजाब ने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसके खिलाफ हम देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिले थे । उस समय मैं सांसद हुआ करता था । देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास से वह केस महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास गया । उसके बाद वह केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डैफर हुआ । हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए । अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करवाना है । इसके अतिरिक्त एस. वाई.एल. नहर केन्द्र सरकार ने खोदनी है और केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा–जजपा की सरकार है । केन्द्र सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में स्वयं मैं, हरियाणा प्रदेश से भाजपा के बड़े नेता और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ए.जी. भी शामिल हुए थे । उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ए.जी. ने कहा था कि इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वह पहले ही फाइनैलिटी अटेन कर चुका है और उस पर किसी की रोक नहीं है । अतः स्पष्ट है कि जिस दिन प्रदेश सरकार चाहेगी एस.वाई.एल. नहर पुनः खुद जाएगी । ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम

राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए कहा था । महामहिम राष्ट्रपति महोदय से तो हम मिलकर आये थे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हमें मिलवाने के लिए आज तक लेकर नहीं गए । मेरा कहना है कि हम प्रदेश की जनता के हित में कोई भी कदम उठाने और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस कार्य में हमसे दो कदम आगे तो जरूर चलना चाहिए ।

श्री रणजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एस.वाई.एल. नहर के विषय में कुछ बात बताना चाहता हूं । इस बात का हुड्डा साहब को भी पता है कि जिस दिन श्री राजीव गांधी जी और लौंगोवाल जी ने समझौता किया उस दिन भजन लाल जी उस कमरे के बाहर बैठे हुए थे । जब राजीव गांधी जी और लौंगोवाल जी के बीच समझौता हो गया तो उसके बाद हरियाणा में आन्दोलन छिड़ गया । तत्पश्चात् चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर बादल साहब बने थे । उस समय एस.वाई.एल. नहर बिल्कुल शुरू हो गई थी । एस.वाई.एल. नहर का बंटाधार तो तब हुआ जब भजन लाल जी हरियाणा प्रदेश के दोबारा चीफ मिनिस्टर बने । उसके बाद से वह नहर बंद ही है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जब राजीव गांधी जी और लौंगोवाल जी के बीच समझौता हो गया था तो उसके बाद एस.वाई.एल. नहर की खुदाई की गई थी । बाद में पंजाब गवर्नमैंट ने समझौते को एब्रोगेट (निरस्त) कर दिया था । इसके अलावा जिस समय श्री प्रकाश सिंह बादल ने एस.वाई.एल. नहर के पंजाब में पड़ने वाले पॉर्शन को मशीनों के द्वारा समतल करवा दिया था उस समय पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और उस समय भाजपा भी अकाली दल की सहयोगी पार्टी थी ।

श्री रणधीर सिंह गोलन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में सिरसा ब्रांच की रिमॉडलिंग के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जोकि कुरूक्षेत्र, कैथल और नरवाना से होती हुई सिरसा तक जाती है । इसके लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये से रि–मॉडलिंग करने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाबड़ी ब्रांच और मोड़ा माईनर की रि–मॉडलिंग के लिए बजट में प्रावधान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः रणधीर जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री रणधीर सिंह गोलनः उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे पुंडरी हल्के में एक महान् तीर्थ है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह एक महर्षि हुए हैं। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इरिगेशन विभाग के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रस्ताव बजट में रखा है। हमारे एरिया में फतेहपुर गांव में फतेहपुर माईनर तक, पाई गांव से किसान ड्रेन तक, ढींग गांव और जिडोलागंद गांव में भी फ्लड की समस्या के समाधान के लिए पम्पिंग सैट लगाने के अलावा 5 किलोमीटर तक पाइप लाइन बिछाने का प्रावधान भी इस बजट में रखा है।

श्री उपाध्यक्षः गोलन जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। आपकी बात पूरी हो चुकी है।

श्री रणधीर सिंह गोलनः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की कुछ डिमांड रखना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्षः गोलन जी, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप उसके बारे में लिखित में दें दे।

श्री रणधीर सिंह गोलनः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पुंडरी एक तहसील है और ढांड गांव उप तहसील है। मेरा हल्का एक बड़ा कस्बा है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उसको सब डिविजन बनाया जाए। मेरा सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन है कि वे भी मेरी बात का समर्थन करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज बन रहा है और उसमें भी इसी सत्र से क्लासिज स्टार्ट करवायी जाएं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर इसी सत्र से क्लॉसिज शुरू करवायी जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं। मेरे हल्के के पाई गांव में लड़कियों का कॉलेज बनवाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर भी इसी सत्र से क्लॉजिस शुरू करवायी जाएं। मैंने पहले भी इस बारे में मांग की थी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली (टोहाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज सरकार ने प्रदेश के लिए नया बजट पेश किया है। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए

सरकार ने यह बजट पेश किया है। कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो वह प्रदेश और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए एक अच्छा बजट पेश करने का कार्य करती है। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले सभी माननीय सदस्यों ने हर वर्ग के बारे में चर्चा की है। आज मुख्य मुद्दा किसान और किसानी का है, किसानों की आय दोगुनी करने का है। मैं इस बजट में इन बातों के बारे में पढ़ रहा था। सरकार ने बागवानी के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हमें फसल चक्र के तहत नैचूरल रिसोर्सिज को अपनाना पड़ेगा। मैं स्वयं भी किसान रहा हूं और मेरा परिवार भी किसान रहा है। यहां पर बैठे हुए बहुत से माननीय सदस्यों का पालन–पोषण भी किसानी से हुआ है और वे आज भी किसानी से जुड़े हुए हैं। एक किसान को अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए मिनिमम इन्कम की जरूरत होती है। जब लेटैस्ट टैक्नॉलोजी आयी तो किसानों ने अपने खेतों में ऊपज को बढ़ाने के लिए पैस्टीसाईड्स का यूज किया क्योंकि उनको इन्कम की जरूरत थी। लेकिन आने वाले समय में उसके क्या साईड इफैक्ट होंगे, हम इस बात को नहीं समझ पाए ? आज पूरे प्रदेश या मेरे हल्के की बात करूं तो वह नहरों की नगरी है। हम नहरों के कारण ज्यादा उत्पादन करते हैं। पहले हमारे वहां पर एक फसल चक्र होता था जिसके तहत हर प्रकार की फसलों की बुआई करते थे। जिसमें नरमा कपास की भी खेत के 1/3 हिस्से में बुआई करते थे। धान, चना, सरसों के अलावा दूसरी फसलों की बुआई भी करते थे। लेकिन अब हम धीरे–धीरे केवल 2 फसलों तक ही सीमित रह गये हैं। जिनको हम पक्की फसल का नाम देते हैं और उसमें हम गेहूं और धान तक ही सीमित रह गये हैं। चूंकि आज किसानों की आय दोगुनी हो सकती है क्योंकि मैंने खुद किसानी की है, इसलिए इसमें मेरी नॉलेज है कि हम किसानों की आय कैसे दोगुनी कर सकते हैं? इसके लिए किसानों को वही फसल चक्र एडॉप्ट करना होगा। हमारा देश अपने खेतों में यूरिया का यूज करके आने वाले बच्चों के लिए अनाज के रूप में जहर का उत्पादन कर रहा है, इसलिए हमें किसानों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में किसान मेले लगाने का काम करना चाहिए। जैसे पहले किसान पुरानी पद्धति से खेती करते थे। उसी तरह से हमें उस पद्धति को दोबारा लागू करके किसानों की आय बढ़ाने पर पुनर्विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यही मेरा मानना है। इसके साथ किसानों को पशुपालन और मछली पालन के लिए भी जागरूक करने

का काम किया जाये। आपको भी इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि आज किसानों की जमीनें कई भागों में विभाजित हो चुकी हैं। अगर हम अपने दादा, पड़दादा और पिता जी के समय को देखें तो हमें पता चलेगा कि पहले जो जमीनें थी, वे जमीनें उस समय के हिसाब से उस परिवार के पालन पोषण के लिए काफी होती थी लेकिन आज उसी जमीन के 15–15 हिस्से हो चुके हैं। कहीं पर उस जमीन के 10–10 हिस्से हो चुके हैं और कहीं–कहीं पर उस जमीन के 5–5 हिस्से हो चुके हैं। आज जो जमीन पर हैड है, उस बारे में हम सभी जानते हैं कि 80 परसैंट हमारी जो किसानी है वह 2 एकड़ से 5 एकड़ भूमि तक सिमटकर रह गई है। जिसके कारण वह अपने परिवार का अच्छी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता है। किसान अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है वह भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि किसानों की आय दुगुनी कैसे की जाये? हमें उन किसानों को यह बात समझानी पड़ेगी कि जो रूटीन में चलती आ रही फसल से हटकर बागवानी फसल की तरफ या इससे जुड़े हुए चाहे वह दूध का उत्पादन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे वह पशुपालन डेयरी का उत्पादन हो या किसानों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय हो, सरकार को उन किसानों को उनकी तरफ लेकर जाना होगा। हमारी सरकार को इसके लिए किसान मेले लगाने होंगे। जिससे किसान को जागरुक किया जाये कि आने वाले समय में इसकी खूबियां और कमियां क्या हैं, इस बारे में किसानों को अवेयर करने का काम किया जा सके। सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट पर हमारे बहुत से साथियों ने काफी लम्बी चौड़ी चर्चा भी की। सरकार का जो मुखिया होता है वही प्रदेश को चलाता है जिसके कारण उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। वह अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है और जनता ने जिस कुर्सी पर उसको बैठाया है, वह उस कुर्सी के साथ न्याय करना चाहता है। इस मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी एक अच्छा प्रयास किया है। मैं इस अच्छे बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं। मैं आज अपने टोहाना हल्के की कुछ बातें इस सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं। जो सरकार ने अच्छे काम किये हैं, मैं उनकी सराहना भी करूंगा और जो काम पैंडिंग पड़े हुए हैं, मैं उनके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। मेरे टोहाना हल्के के वासियों की तरफ से भी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरे विधायक बनने से पहले पूर्व की सरकारों के समय में टोहाना हल्के की जनता के लिए कई पॉलिसी आई

थी। उनमें से एक पॉलिसी यह भी थी कि पानी को कैसे बचाया जा सके? मेरा भी यही मानना है कि जल है तो जीवन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश में घर–घर तक पानी पहुंचाने का अभियान चलाया हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी प्रदेश में यह अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत प्रदेश में काफी प्रगति के साथ काम किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश में बिजली को घर–घर तक पहुंचाने का अभियान चलाया हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी प्रदेश में यह अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत काफी तेजी के साथ काम भी किया गया है। मेरे क्षेत्र में ''म्हारा गांव, जगमग गांव'' योजना के तहत हमारी कुछ ढाणियों को छोड़कर लगभग 90 परसैंट तक बिजली घर–घर तक पहुंचाई जा चुकी है। मेरे हल्के के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 16 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बिजली पहुंचाई जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री से कहना चाहूंगा कि जो बिजली की चोरी हो रही है। उसके बारे में जनता को अधिकारी और जनप्रतिनिधि अवेयर करे कि निगम उनको मिनीमम रेट पर बिजली देती है इसलिए वे बिजली की चोरी न करे। जब बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी के छापे डाले जाते हैं तो उनमें बहुत सी जगहों पर जबरन वसूली भी विभाग द्वारा की जाती है, जो कि सही नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि सरकार प्रदेश की जनता से रिकवरी न करे बल्कि उनको बिजली चोरी रोकने के लिए अवेयर किया जाये। इसमें मेरा यह भी कहना है कि सरकार का लॉस न हो विभाग द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए जो छापेमारी की जाती है जिसको ताडंव बोलते हैं, जिससे प्रदेश के लोगों को परेशान किया जाता है। मेरा इस संबंध में यही कहना है कि इस ताडंव को रोकने का काम करें। जहां तक पानी बचाने की बात है। मेरा इसमें यही कहना है कि जल है तो जीवन है। हमारे यहां खेतों में बहुत सी ढाणियां बनी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकार ने गांवों में हर घर नल और शुद्ध जल का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ मैं एक शब्द शुद्ध जल जोड़ना चाहूंगा कि सरकार जल तो प्रदेश के सभी लोगों को देना चाहती है। अगर सरकार लोगों को जल प्रोपर तरीके से देना चाहती है तो उनके घरों में साफ पानी पहुंचाने का काम किया जाये। मेरे हल्के में नहरों की नगरी है इसलिए यहां के लोगों को इसका बैनिफिट भी मिलना चाहिए क्योंकि जो धरती का पानी है वह पानी कहीं न कहीं

खराब हो चुका है। जिसके कारण मेरे हल्के के लोगों के घरों में कैंसर और हैपीटाइटिस–सी और बी जैसी घातक बीमारियां घुस चुकी हैं। मेरे हल्के के गांवों में एक भी घर ऐसा नहीं है, जिसमें कोई न कोई सदस्य इन बीमारियों से ग्रस्त न हुआ हो। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे पूरे हल्के के लोगों को शुद्ध जल की सुविधा नहरों से जोड़कर देने का काम करें। सरकार ने फैसला किया है कि जिन महिलाओं की उम्र 60 साल है और जिन पुरूषों की उम्र 65 साल है उनको रोडवेज की बसों में किराये में छूट दी जायेगी। मेरा यह कहना है कि जब सरकार महिला और पुरूष दोनों को बराबरी का दर्जा देती है तो पुरूषों की उम्र भी 60 साल की जाये ताकि इनको भी रोडवेज की बसों में किराये में छूट मिल सके। डिप्टी स्पीकर सर, हमारे प्रदेश में अवैध कालोनियों का मुद्दा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं यह मानता हूं कि प्रदेश में अवैध कालोनियां का फलना–फूलना प्रशासन की मिलीभगत के बिना किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए विकास की बहुत सी परियोजनायें लेकर आई है। जहां तक प्रदेश में पनप चुकी अवैध कालोनियों का सम्बन्ध है वे भी सरकार को मिनीमम डिवैल्पमैंट चार्जिज देकर अपनी डिवैल्पमैंट कर सकती हैं और रेगुलर हो सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने हल्के से सम्बंधित बहुत सी समस्याओं के बारे में लिखित रूप में लेकर आया हूं। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं उनको यहां पर पढ़ना चाहूंगा और अगर आप यहां पर उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको भी हाउस की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : देवेन्द्र बबली जी, जो भी आपके पास लिखित में है उसको आप सदन के पटल पर रख दें। उनको हाउस की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बना दिया जायेगा।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : ठीक है डिप्टी स्पीकर साहब। सर, हमारी गठबन्धन सरकार ने इस बार एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है इसके लिए मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और अपनी पूरी सरकार को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। जय हिन्द।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। सर, कल से बजट पर डिस्कसन के दौरान बजट के बारे में, बजट के पक्ष में और बजट के विपक्ष में हमारे काफी साथियों ने यहां पर काफी कुछ कहा है। मैं इस विषय को

थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में पैसा अलॉट करने से अर्थात् धनराशि अलॉट करने मात्र से ही सारे का सारा काम पूरा नहीं हो जाता। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए विकास का एक माहौल चाहिए होता है। विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो मैं समझता हूं कि प्रदेश में जब तक शांति और सद्भावना नहीं होती तब तक प्रदेश के विकास का कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। प्रदेश में जो वर्तमान समय में हालात हैं ये हालात प्रदेश के विकास के लिए बहुत घातक और पीड़ादायक हैं। हमारा जो किसान आंदोलन है इसकी वजह से हमारा हरियाणा प्रदेश दिल्ली के तीन तरफ स्थित है और बहादुरगढ़ से बल्लभगढ़ तक की सारी की सारी इण्डस्ट्रीज बंद पड़ी हैं क्योंकि कच्चे माल को लाने में दिक्कत हो रही है और जो फिनिश गुड्ज़ हैं उनको भेजने में दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं इस समय एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि प्रदेश की सारी की सारी अर्थव्यवस्था एक तरह से रूक सी गई है। इसके लिए मैं जो समझता हूं क्योंकि किसान आंदोलन में किसान अपनी बात कह रहे हैं और हमारे देश में सत्याग्रह करने का सभी को हक उपलब्ध है लेकिन इसके साथ ही साथ आंदोलन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आंदोलन तो पंजाब के किसान भी कर रहे हैं, यू.पी. के किसान भी कर रहे हैं और अगर किसान यूनियन की बात को सच माने तो किसान आंदोलन तो सारे देश में ही हो रहा है लेकिन हरियाणा जैसे हालात और हरियाणा जैसी स्थिति और किसी भी राज्य में नहीं है। मैं यह समझता हूं कि स्पष्ट रूप से इसके दो कारण हैं। मैं किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इसलिए मेरी बात को अन्यथा न लिया जाये लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में कुछेक व्यक्ति ऐसे हैं अर्थात् हमारे प्रदेश की पॉपूलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें प्रदेश के हर वर्ग और हर सम्प्रदाय के लोग शामिल हैं जो तोड़–फोड़ और अशांति फैलाने में विश्वास रखते हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, इस प्रकार के उपद्रवी तत्वों ने देश के झण्डे तक को नहीं बख्शा। डिप्टी स्पीकर सर, उन प्रदर्शनकारियों ने देश के तिरंगे तक का सम्मान नहीं किया। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, विपक्ष के साथियों को तो बैठे–बैठे शोर करने की आदत सी हो गई है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, मैं यहां पर एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाने के लिए अंग्रेजों के

खिलाफ कितना लम्बा संघर्ष किया यह हम सभी को अच्छी तरह से मालूम है। अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के झण्ड़े को हाथ तक नहीं लगाया लेकिन किसान आंदोलन की आड़ लेकर कुछ उपद्रवी तत्वों ने हिन्दुस्तान के झण्डे तक का भी सरेआम अपमान करने का दुस्साहस किया है।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जाति विशेष के बारे में गलत बयानी की है उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, माननीय सदस्य ने किसी जाति का नाम नहीं लिया है और न ही किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है। आप ऐसे ही खड़ी हो रही हैं, यहां हर सदस्य को बोलने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, वे कुछ लोग किसी भी जाति या सम्प्रदाय से हो सकते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ लोग तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के साथी सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

परिहवन मंत्री (श्री मूल चन्द शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, **(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, **(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, **(शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्षः विपक्ष के जो सदस्य बिना चेयर की अनुमति के बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड न किया जाये। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से अब श्रीमती गीता भुक्कल जी अपनी बात रखें।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमारे साथी डॉ. अभय सिंह ने बोलते हुए आग में घी डालने

का काम किया है। पहले ही हमारा प्रदेश जाति–पाती की मार झेल रहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य से किसानों को भी जाति–पाती में बांटने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, 36 बिरादरी किसानी करती है। हमारी जाति के लोग भी किसानी करते हैं, सभी जातियों के लोग किसानी करते हैं। किसान किसी विशेष जाति समुदाय के नहीं होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, डॉ. अभय सिंह जी ने किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि कुछ जाति विशेष के लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, आप जो कह रही हैं यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर सरकार ने बैरीकेडिंग की हुई है, जहां पर कीलें गाड रखी हैं और कांटेदार तार लगाए हुये हैं वहां पर किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस प्रकार से जहर घोलने का काम न किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अभय यादव जी ने यह कहा है कि मैंने किसी जाति–पाति का नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी मेरी एक बात सुन लें। (शोर एवं व्यवधान) अगर किसी भी सदस्य ने चाहे वह सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो ऐसा शब्द कहा है तो वह डिलिट कर दिया जाएगा। वह प्रौसीडिंग में नहीं आएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ———— (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मूल चन्द जी, प्लीज आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छौक्कर : उपाध्यक्ष महोदय, ——— (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : छौक्कर जी, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) बात क्लीयर हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, आप इन कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को चुप करवाईये । ये किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स : उपाध्यक्ष महोदय, ––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुलदीप जी, प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सोमबीर सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, ––––––(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सांगवान जी, प्लीज आप बैठिये। जब आपका नम्बर आएगा तब बोल लेना।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का तोड़ कर देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर वह शब्द कहा है तो उसको डिलिट करवा दिया है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठें।

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कांग्रेस के सदस्यों से एक अनुरोध है कि ये मेरी एक बात सुन लें। इसका फैसला यहीं हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्डिंग निकलवाकर देख लें। मैंने यह कहा है कि मैं किसी जाति वर्ग का नाम नहीं ले रहा उसमें हर जाति व हर वर्ग के लोग शामिल हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अशांति में विश्वास करते हैं। आप चाहे यह रिकॉर्ड निकलवाकर देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इससे ज्यादा क्लीयर और क्या होगा। (शोर एवं व्यवधान) हमने कह दिया है कि अगर कोई इस तरह की बात है तो उसको डिलिट कर दिया जाएगा। अब अगर कोई ऐसा शब्द था तो वह डिलिट हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरा बजट अभिभाषण खत्म हो जाए उसके बाद आप विधान सभा की रिकॉर्डिंग निकलवाकर देख लेना। अगर मैंने किसी जाति के बारे में कहा है तो उसमें वह क्लीयर हो जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभय जी, आप कॉन्टीन्यू कीजिए।(शोर एवं व्यवधान) आप इस बात को रिपीट न करें। आप कॉन्टीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत गलत बात कही है। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं आज ही विधान सभा छोड़कर चला जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को क्लीयर करवाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, हो गया क्लीयर।(शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब, अब बात क्लीयर हो गई है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठें।

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही यह फैसला हो जाएगा कि कौन असत्य बोल रहा है। आप रिकॉर्डिंग निकलवाकर देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सोमबीर सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने का समय दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सांगवान जी, प्लीज आप हाऊस को चल लेने दें। (शोर एवं व्यवधान) आपका जब नम्बर आएगा तब बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं वह इनको और भी बुरी लगेगी। मैं यह कह रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर हरियाणा की एक पार्टी का एक वार रूम पूरी रात काम नहीं करता तो आन्दोलन 26 जनवरी को ही खत्म हो गया था लेकिन इस प्रकार इस आंदोलन में राजनीति घुस गई और उस राजनीति की बात करते हुए जब इन लोगों की बात आती है तो ये लोग अपनी बात को सच करने के लिए जोर जोर से बोलने लग जाते हैं। ये लोग झूठे प्रचार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राकेश टिकैत का भाई भी आंदोलन खत्म करने की घोषणा करके यू.पी. चला गया था लेकिन इसके बाद राकेश टिकैत के आंसुओं से यह आंदोलन पुनर्जीवत हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः देखिए, माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, आप लोग उन्हें अपनी बात तो पूरी करने दो। आप लोगों को इनके बोलने से क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह कुछ लोग कृषि कानूनों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें देखकर मैं सदन के सामने एक छोटा सा

किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में सड़क के किनारे पेड़ कट रहे थे और उस गांव का एक अधेड़ सी उम्र का आदमी रोज उस जगह पर आता और सारा दिन चुपचाप पेड़ कटने की कार्रवाई को बैठा–बैठा देखता रहता और जब पेड़ कटने बंद हो जाते तो उठकर चला जाता था। तीन–चार दिन ऐसे ही हो गए तो एक दिन पेड़ काटने वालों में से एक ने उस आदमी से पूछा कि बाबा आप यहां पर रोज आते हो, सारा दिन पेड़ काटने की कार्रवाई देखते हो और शाम को चुपचाप चले जाते हो ऐसा क्यों है, तो वह अधेड़ उम्र का आदमी बताता है कि भाई जब आप पेड़ को काटते हों ना तो जब करड़–करड़ की आवाज करते हुए पेड़ नीचे गिरता है तो वह मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी चीज को देखने के लिए यहां पर रोज आता हूँ। (हंसी) भाव जिसको समझना था वे समझ गए होंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों की बात कर रहा था जोकि तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं बल्कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष की बात कभी नहीं कही। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कृषि कानूनों के नाम पर सारे स्टेट की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर रखने का काम किया जा रहा है। वास्तव में कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है। इन कृषि कानूनों के द्वारा एक तरह से लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद किसान के हित को सुरक्षित करते हुए उसको कानूनी कवच देने का काम किया गया है। यूं तो सभी अपने आपको किसान कहते हैं लेकिन मैंने तो किसानी जी है, मैंने किसानी की है और जब मैं आठवीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने बैलों का हल चलाना शुरू किया था। मैं मंडी में अनाज भी बेचकर आया हूँ। मैं मेले में पशु भी बेचकर आया हूँ। मुझे पता है कि किसानी क्या होती है। किसान के हालातों को मैंने अपनी आंखो से देखा है। मंडी में फसल बेचने के लिए जमींदार सुबह अपनी फसल लेकर जाता है। वहां पर उसकी फसल की ढेरी करवा ली जाती है और जब तक किसान की फसल की बोली नहीं लगती जब तक किसान अपनी फसल की ढेरी को झाड़ू से साफ सुथरी रखने का काम करता है और जब बोली आती है यह मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ नजारा है चार–पांच आदमी आक्शन रिकार्डर के साथ आते है और फसल को उछालते हुए एक आदमी बोली लगता है कि एक सौ एक रूपया दूसरा उससे थोड़ा ज्यादा कहेगा इसके बाद तीन चार बार बोली लगाकर काम खत्म हो जाता है। इसके बाद ऑक्सन रिकॉर्डर अंदर खाते पूछता है कि कौने से के क्या क्या रेट लिखू तो फिर सैंटिंग कर ली जाती है कि मेरे फलां रेट लिख दे, दूसरे के फलां रेट लिख दे। मंडी में किसान की फसल

का यही हाल होता है। इन सारी बातों को देखते हुए इन नए कानूनों को बड़ी प्रक्रिया अपनाते हुए किसान हित में बनाया गया है जिनके लिए कहा जाता है कि ये कानून लॉकडाउन में जल्दबाजी में बनाये गए कानून हैं जबकि असलियत यह है वर्ष 2002 से यह सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसके बाद से लगातार यह सारी प्रक्रिया चलती रही और वर्ष 2010 मे माननीय हुड्डा साहब के कार्यकाल में भी एक कमेटी ने इस बारे में रिपोर्ट दी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, जब कानूनों पर स्टे हुआ है तो फिर इन कृषि कानूनों पर अब इतनी चर्चा क्यों की जा रही है। जब हम इन कृषि कानूनों पर बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि इन कानूनों पर स्टे है अतः इन पर बात नहीं हुई है और सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा इन कानूनों के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है। इस तरह बेमतलब की बात नहीं करनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज अर्थव्यवस्था को बंदी बनाया गया है, मैं तो उसको स्पष्ट करने के लिए सारे कारण बता रहा हूँ लेकिन मेरी सच बातें इन लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, इनको बजट पर बोलना चाहिए बेकार की बात करके विषय को घुमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने समुदाय विशेष के बारे में गलत टिप्पणी की है। जनता इन्हें माफ नहीं करने वाली। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने सफेद * के साथ स्टेट को बांधकर रखने का काम किया हुआ और मैडम किरण जी की तो * बोलने की मजूबरी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, जो शब्द अभी बोला गया है इसको प्रोसिडिंग्ज से डिलीट करने का काम किया जाये?(शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्षः जिस * शब्द पर माननीय सदस्यों को आपत्ति है इसको प्रोसिडिंग्ज का हिस्सा न बनाये जाये।

डॉ. अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाभारत में गुरू द्रोणाचार्य की हत्या का छल रचा गया था क्योंकि वे इतने बड़े योद्धा थे कि अर्जुन जैसे बड़े–बड़े योद्धा भी उनको मार नहीं

सकते थे। गुरू द्रोणाचार्य के मारने की प्लानिंग श्री कृष्ण के पास थी और केवल उन्हीं को पता था कि गुरू द्रोणाचार्य को किस प्रकार से मारा जा सकता था। श्री कृष्ण ने बताया कि उनकी जान उनके बेटे अश्वत्थामा में बसी हुई है। जिस दिन उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार गुरू द्रोणाचार्य को मिल जायेगा उसी दिन उन्हें मारा जा सकता है लेकिन अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र है, इसलिए उनको भी मारना आसान काम नहीं था। गुरू द्रोणाचार्य को मारने की ड्यटी युधिष्ठिर की लगाई गई क्योंकि गुरू द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की बात पर विश्वास करते थे। युधिष्ठिर ने भारी मन से श्री कृष्ण के झांसे में आकर आधा श्लोक गुरू द्रोणाचार्य को कहा कि 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो' पता नहीं 'अश्वत्थामा' नामक हाथी या मनुष्य कौन मारा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष की भी वही स्थिति हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है डॉ. अभय सिंह यादव युधिष्ठिर बन गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी आफताब अहमद (नूंह): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बजट सरकार का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। विपक्ष के सदस्य बजट में सदन के पटल पर आंकलन, मूल्यांकन और कमियाँ निकाल कर सरकार को एक आइना दिखाने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर वित्त मंत्री जो वर्ष 2021–22 का बजट पेश किया है उसमें केवल और केवल आंकड़ों का हेर–फेर दर्शाने का काम किया गया है और जनता को गुमराह करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट प्रदेश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने इस बजट के तथ्यों को छिपाकर और आंकड़ों में हेराफेरी करके पेश किया है। बजट की तुलना प्रदेश के हित में होनी चाहिए लेकिन सरकार ने इसकी तुलना पिछले वर्ष के बजट

———————————————————————————————

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

से की है। पूंजीगत खर्च जो राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का आधार होता है, लेकिन सरकार ने इसमें इतना बजट नहीं दिखाया है, जिससे कि यह राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। हरियाणा एक ऐसपाइरिंग स्टेट (महत्वाकांक्षी) है । अगर मैं कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल ऐक्सपैंडीचर की बात करूं तो हम इस बजट में देखते हैं कि आज प्रदेश पर इस चालू वित्त वर्ष में कर्ज की देनदारी 1,99,823

करोड़ रुपये है । आगामी बजट में प्रदेश की कुल देनदारी का वर्णन नहीं किया गया है । इस तरह से सरकार द्वारा आंकड़ो को छुपाने का कार्य किया गया है । इस 1,99,823 करोड़ रुपये के कर्ज में अगर इस कर्ज के निपटान के लिए बजट में जो 28,161 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है उसको और जोड़ लिया जाए तो हमारे प्रदेश पर कर्ज की कुल देनदारी लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से हरियाणा एक डैट ट्रैप में नहीं फंस रहा है? इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में इस बजट को पेश किया है । इससे हमें उम्मीद थी कि यह दस्तावेज एक विश्वसनीयता का दस्तावेज होगा । अब इस दस्तावेज पर कैसे विश्वास किया जाए जब सिर्फ झूठी वाहवाही लेने के लिए और प्रदेश पर कर्जदारी असलियत से कम दिखाई गई हो और इस बजट के माध्यम से केवल नंबर की बाजीगरी को पेश किया गया हो । हरियाणा की वित्तीय स्थिति के लिए यह कोई सराहनीय कदम नहीं हो सकता बल्कि यह एक चिंतनीय विषय है और इसकी वजह से भविष्य में हरियाणा एक डैट ट्रैप में पड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा । बजट में दिए गए आंकड़ों के विषय में मैं कहूंगा कि सरकार को केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए इनके साथ खिलवाड़ और शरारत नहीं करनी चाहिए क्योंकि बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार का लेखा–जोखा प्रस्तुत करता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा चाहे कृषि की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में इस बजट में घटोतरी की गई है । इससे भी अधिक चिंता का विषय तो यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए आबंटित बजट का लगभग एक हजार करोड़ रुपये तो अनयूटिलाइज्ड रह जाता है। सरकार वाहवाही लूटने के लिए एक बार तो कृषि के क्षेत्र के लिए बजट में हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान कर देती है लेकिन बाद में उस पैसे को पूरा यूटिलाइज भी नहीं किया जाता । इसके अलावा सरकार किसान हितैषी होने का भी दम भरती है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है । उस नाते इस तरह की चीजें हरियाणा प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है । मैं सदन के नेता से कहना चाहता हूं कि राज तो बदलता रहता है लेकिन अगर कहीं हरियाणा प्रदेश की वित्तीय स्थिति डगमगा गई और प्रदेश डैट ट्रैप में फंस गया तो हरियाणावासियों को कर्ज पर ही आश्रित रहना होगा और प्रदेश अपने ही रिसॉर्सिज का उपयोग नहीं कर पाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जिला

एक एस्पिरेशनल (अभिलाषी) जिला है । इसके बावजूद हमें विकास की दरकार रहती है । साल–दर–साल यह उम्मीद बढ़ती जाती है। अभी ढेड़ साल तो मुझे ही विधायक बने हुए हो चुका है और इस समय भी हमने उम्मीद लगाई हुई है। नूँह जिले के एस्पिरेशनल जिला बनने के बाद हमें उम्मीद थी कि वहां पर विकास की जो डगर हमने शुरू की थी वह आगे बढ़ेगी लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज सरकार का हमारे जिले के प्रति नजरिया ही कुछ और है । हमारे कार्यकाल में विकास की जो डगर हमारे जिले में चली थी अब उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को इस बात से अवगत करवाना चाहता हूं कि पिछली सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वास्थ्य से संबंधित थी और उस समय हमारे जिले में शहीद हसन खां के नाम पर हरियाणा का दूसरा मैडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। आज उनका 495वां शहादत दिवस है और मैं उनको इस बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देता हूं । उन्होंने उस समय बाबर के खिलाफ युद्ध में लड़कर हिन्दुस्तान की एकता और भाईचारे की परम्परा को जीवित रखा था । हमें उन पर फख्र है । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की जिस मांग के बारे में बताऊँगा उसके बारे में मैंने पिछले सत्र में भी कहा था । पिछली सरकार में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 550 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा में रोहतक के बाद दूसरा गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज हमारे जिले में खोला था लेकिन आज वह मैडिकल कॉलेज खुद ही बीमार है । उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब पड़ी हुई है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने उस समय वहां पर 550 करोड़ रुपये की लागत से एक मेडिकल कॉलेज बनवाया था और वह रोहतक के बाद हरियाणा प्रदेश का दूसरा ऐसा मेडिकल कॉलेज था। कोविड–19 के टाईम पर वहां नर्सिज ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की थी, परन्तु अब उनको सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है। कोविड–19 के दौरान कुछ और कारण थे, परन्तु सरकार ने विफलताओं से बचने के लिए हमारे ईलाके और हमारे समुदाय के लोगों पर विशेष तौर पर आरोप लगाये थे। वहां पर 125 नर्सिज पिछले 6 सालों से अपनी सेवाएं दे रही थी और उन्होंने कोविड–19 की बीमारी के समय भी अपनी जान पर खेलकर मरीजों की सेवा की थी। अब सरकार ने उनको नौकरी से निकाल कर बाहर कर दिया है। जिसके कारण वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। जब वे कोविड–19 के दौरान सेवाएं दे रही थी तो उनके

स्थान पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, परन्तु अब सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया है। क्या यह सरकार उनको रोजगार देगी ? क्या यह सरकार उस मेडिकल कॉलेज को सुचारू रूप से चलाएगी ? सरकार ने 3 मेडिकल कॉलेज के लिए एक–एक लाख रुपये की नोशनल अमाउंट दी है। क्या यह अमाउंट उन मेडिकल कॉलेजिज के लिए काफी है? जो मेडिकल कॉलेज वर्ष 2012 में शुरू हुआ था, उसको आज 9 साल का समय व्यतीत होने के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए था, लेकिन वह मेडिकल कॉलेज खुद ही बीमार हो गया है क्योंकि सरकार का नजरिया ठीक नहीं है। सरकार को इन बातों पर संज्ञान लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की सरकार ने वहां पर एक 100 सीट्स का डैंटल कॉलेज बनाना मंजूर किया था। इस सरकार ने सात साल में उसको 100 सीट्स से घटाकर 50 सीट का कर दिया ताकि उस इलाके के लोगों को 100 सीटें न मिल पाएं, इसलिए उनमें कटौती कर दी। इसके अतिरिक्त मैं दूसरे विषयों के बारे में भी बताना चाहूंगा। आज शिक्षा का क्या हाल है? हमारे 50 फीसदी से ज्यादा स्कूल्ज में पूरे टीचर्ज नहीं हैं। पिछले 6–7 सालों से मेवात कैडर बना था, परन्तु उसमें एक भी भर्ती नहीं हुई है। यह समस्या तो तब है जब मेवात डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है। प्रदेश सरकार सबका साथ–सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। अगर वहां पर शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जायेगा? (इस समय घंटी बजायी गयी।)

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, आपको बोलते हुए 10 मिनट का समय हो गया है। आप दो मिनट में कंक्लूड करें।

चौधरी आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए 8 मिनट का समय दिया है। आप इसके बारे में टाइम टेबल निकलवाकर देख लें। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को बोलने के लिए दिये गये टाइम के हिसाब से हमारे बोलने के टाइम में फर्क हो तो आप हमें रोक दें।

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, आपसे पहले 6 सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को बोलने का समय दिया गया था और 6 माननीय सदस्य ही विपक्ष के बोले हैं। अगर आप उनके बोलने का समय पूछना चाहेंगे तो उसके बारे में भी बता देंगे।

चौधरी आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए भी केवल 8 मिनट का समय दिया गया था, परंतु दूसरे माननीय सदस्य 20–25 मिनट तक भी बोले हैं।

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, आपको बोलते हुए 10 मिनट का समय हो चुका है।

चौधरी आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, हम साल में एक बार उम्मीद करते हैं कि हमें बजट सैशन में बोलने के लिए पूरा समय दिया जाएगा। हमारी पार्टी के 3 नये माननीय सदस्य इस बजट सत्र में नहीं बोले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे बजट पर बोलने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

चौधरी आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महेदय, इसके अतिरक्त मैं शिक्षा के बारे में भी कहना चाहूंगा। मुझे हमारे एरिया में सरकार से विश्वविद्यालय बनाने की उम्मीद नहीं है, परन्तु वहां पर स्कूल्ज और कॉलेजिज के लिए पूरे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। मेवात कैडर के तहत कोई भर्ती नहीं की गयी है। सालाहेड़ी गांव में कॉलेज है और सैंट्रल स्कूल बनाना मंजूर किया गया था, परंतु 8 साल के बाद भी उसको बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। संगेल गांव में एक सैनिक स्कूल बनाने की मांग की गई थी, लेकिन उसके लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अबकी बार इस बजट में मेवात कैनाल के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह वही मेवात कैनाल है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2019 में चुनावों से पहले किया था। इसका शिलान्यास वोटों की राजनीति के लिए किया गया था। इस परियोजना के तहत डेढ़ साल में 100 करोड़ रुपये मिले हैं, परन्तु यह परियोजना 633 करोड़ रुपये की है। सरकार द्वारा इस अमाउंट को 3 हिस्सों में बांटकर दिया जा रहा है। इस प्रकार इस कार्य को पूरा करने में दशकों का समय लग जाएगा। जिस समय इसका शिलान्यास किया गया है तो उस दिन बजट का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? सरकार को इसके लिए बजट का प्रावधान करने में डेढ़ साल का समय लग गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे एरिया के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। हमारे एरिया में जमीन का पानी ऐसा है जिससे किसानी नहीं हो सकती है। आज सभी जगहों के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे एरिया के किसान इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनको सिंचाई के लिए प्रर्याप्त पानी दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, आज जल्दी कंक्लूड करें।

चौधरी आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त 2 बातें और रखना चाहूंगा। मेरे एरिया में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाएं और पानी की गुणवत्ता

बढ़ायी जाए। इस संबंध में हमारे माननीय मंत्री जी ने एक मीटिंग भी की थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके लिए सरकार की तरफ से अधिक तवज्जो की जरूरत है। उस पानी को पशुओं के पीने योग्य तो करवा दें। वह पानी के कृषि योग्य न होने के कारण फसलों को नुक्सान हो रहा है। सरकार द्वारा बजट में सड़कें बनाने की बहुत बातें की गयी हैं, लेकिन इसमें हमारे एरिया के लिए कोई सड़क बनाने की बात नहीं की गयी है। हमारे एरिया में 248 (ए) नूंह से लेकर अलवर बॉर्डर तक रोड की एक मंजूर– शुदा परियोजना थी, परन्तु उसको सरकार द्वारा वर्ष 2017 में यह कहकर अबैंडन कर दिया गया कि मुम्बई कॉरीडोर बनाया जा रहा है, लेकिन आज वहां पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अगर सरकार इतनी असंवेदनहीन हो गई तो फिर आमजन के लिए जीना भी मुश्किल हो जायेगा। वर्तमान सरकार का काम होता है कि पूर्व की सरकारों के समय में जो मंजूर शुदा परियोजनाएं हैं उनको चालू करवाया जाये। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आफताब जी, आप लिखित में अपनी स्पीच दे दीजिए। उसको कार्यवाही का हिस्सा बना लिया जायेगा। (विघ्न)

चौधरी आफताब अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरे क्षेत्र में खनन के माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार राजस्व अर्जित करना चाहती है तो जिस एरिया में खनन प्रतिबंधित नहीं हैं या अरावली क्षेत्र में प्रतिबंधित नहीं हैं। जो क्षेत्र एन.जी.टी. और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हैं। वहां पर सरकार खनन का काम शुरू करवा सकती है ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : आफताब जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

चौधरी आफताब अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ''मिर्जा गालिब'' का एक शेर सुनाना चाहता हूं:–

''उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे

धूल चेहरे पर थी और आइना साफ करते रहे''।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि इस सदन में सिर्फ बजट पर चर्चा की जाये। इधर–उधर की बातें करने से सदन का समय खराब होता है जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बजट पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ? इस प्रकार की चर्चा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होती है। मेरा यही कहना है कि सिर्फ बजट पर ही चर्चा की जानी चाहिए।

श्री दूड़ा राम (फतेहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा आप जानते हो कि हम सभी इस कोराना महामारी के कारण एक मुश्किल समय से गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं। इस मुश्किल समय की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बजट पेश किया गया है। इस बजट के माध्यम से हर वर्ग का ध्यान रखने का काम किया है और यह बजट बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। इस बजट में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने पर विशेष बल दिया गया है। इस बजट के माध्यम से शिक्षा और कृषि पर विशेष बल दिया गया है क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के आगामी साल में हमारी बहन बेटियों के लिए जहां 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोलने की बात की है वह भी सराहनीय कदम है। वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ाये जायें, इसके लिए भी सरकार ने बेहतर प्रयास किया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और हमारी सरकार किसान के हित और किसान की आय को दोगुना करने के लिए कितना प्रयास कर रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 2998 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 489 करोड़ रुपये, पशुपालन और डेयरी के लिए 1225 करोड़ रुपये, मछली पालन के लिए 125 करोड़ रुपये और सहकारिता क्षेत्र के लिए 1274 करोड़ रुपये रखे गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये बजट में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस संकट के समय में बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। बजट में स्वास्थ्य और कृषि पर अधिक बल देकर आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने वाली श्रेणी में रखा गया है। यह सकरार का बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किये बजट में यदि

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे जिला मुख्यालय में 200 बैड का अस्पताल बनाने का रास्ता साफ हुआ है, जिसका लाभ हमारे क्षेत्र के वासियों को होगा। वहीं मेरी विधान सभा के साथ लगते हुए अग्रोहा मैडीकल कॉलेज में कैंसर विज्ञान केन्द्र स्थापित भी किया जायेगा, उसका लाभ भी पूरे फतेहाबाद जिले के नागरिकों को मिलेगा। डिप्टी स्पीकर सर, इसके अलावा मेरे फतेहाबाद जिले में संक्षिप्त सिंचाई व वर्षा जल संचय जैसी योजनाओं को सरकार ने शुरू किया है इनसे मेरे हल्के व मेरे जिले के सभी किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमारे भूना और रतिया से होते हुए एक एक्सप्रैस–वे निकाला जा रहा है जिससे इन दोनों कस्बों में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। डिप्टी स्पीकर सर, बजट में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पैंशन में 250/– रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए हमारी सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम ही होगी। उपाध्यक्ष जी, अब आपके माध्यम से अपने हल्के के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगें रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2019 में मेरे हल्के के गांव काजल हेड़ी में दुर्लभ कछुआ, ढ़ाणी माजरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर और गांव धांगड़ में काली हिरण के लिए सामुदायिक आर्थिक क्षेत्रों की घोषणा की गई थी। मैं इस सदन के माध्यम से यह अवगत करवाना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन होने के बाद दो साल का समय व्यतीत हो गया लेकिन अभी तक भी इन सामुदायिक आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए कोई भी ग्रांट जारी नहीं की गई है और न ही इन मामलों से सम्बंधित कमेटी में इनकी एप्रूवल हो पाई है। उपाध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह पुरजोर मांग है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा सामुदायिक आर्थिक क्षेत्रों का प्लॉन जल्दी से जल्दी तैयार किया जाये। उपाध्यक्ष जी, पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के खेतों को पानी देने वाले खाले थे उनकी मुरम्मत के लिए पूर्व में निर्धारित 20 वर्ष की समय सीमा को घटाकर 15 साल निर्धारित किया गया था। उस समय यह घोषणा तो हो चुकी थी लेकिन इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए नोटिफिकेशन अभी तक भी नहीं हो पाया है। उपाध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से यही प्रार्थना है कि खराब खालों की मुरम्मत के लिए पूर्व निर्धारित 20 साल की समय सीमा को घटाकर 15 साल की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी की जाये ताकि किसानों के खेतों में पानी देने

13:00 बजे

के लिए जिन खालों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और जिसके कारण किसानों को बड़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को खराब खालों के कारण से होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार को इनकी मुरम्मत की स्कीम जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए। इससे खासकर फतेहाबाद और डिप्टी स्पीकर सर आपके गृह जिला हिसार के किसानों को खराब खालों की वजह से बहुत भारी दिक्कतों को सहन करना पड़ रहा है। इस मामले में पहले एक निर्णय यह भी लिया गया था कि इन खराब खालों की मुरम्मत पर होने वाले खर्च का 25 परसैंट किसान भुगतान करे। इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से विशेष रूप से यही प्रार्थना है कि खालों की मुरम्मत पर होने वाले खर्च की 25 परसैंट राशि को भी किसानों से न भरवाया जाये बल्कि खराब खालों की मुरम्मत पर होने वाले तमाम खर्च को सरकार ही वहन करने का काम करे। माननीय उपाध्यक्ष जी, फतेहाबाद जिले में अधिकतर लोग खेतों में और ढ़ाणियों में रहते हैं। मेरी आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि जो लोग खेतों और ढ़ाणियों में रहते हैं उनको गांवों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाये। मैं मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे फतेहाबाद हल्के में कुछेक ढ़ाणियां ऐसी भी हैं जहां पर अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि मेरे हल्के फतेहाबाद में जहां–जहां पर लाइट की सुविधा नहीं है वहां पर सरकार अपने खर्च से जल्दी से जल्दी लाइट पहुंचाने का काम करे। डिप्टी स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि मेरे फतेहाबाद हल्के में ढ़ाणियों में जहां–जहां पर भी तीन कदम के रास्ते हैं उन सभी को सी.सी. ब्लॉक्स से पक्का किया जाये ताकि स्कूल, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, बच्चियों और लोगों को पक्का रास्ता न होने विशेषकर बरसात के मौसम से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। डिप्टी स्पीकर सर, मेरे हल्के की विशेष रूप से एक तो ढ़ाणियों में डोमैस्टिक फीडर से लाइट देने बारे और दूसरी तीन कदम के रास्तों को सी.सी. ब्लॉक्स लगाकर पक्का करने की दो ही मुख्य मांगें हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से बार–बार यही प्रार्थना है कि सरकार मेरे हल्के की इन दो मांगों को शीघ्रता से पूरा करे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री बलराज कुंडू (महम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट चर्चा पर मैं सभी साथियों के अपने–अपने वक्तव्य सुन रहा था। मुझे पता लगा है और मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है, एक वरिष्ठ सदस्य के लिए यहां हाउस में जो मर्यादा होनी चाहिए वह दिखाई नहीं दी। सदन में जो बहस होती है, संसदीय कार्य मंत्री के अलावा कोई मंत्री बीच में टोका–टाकी नहीं करता। यहां आज एक चीज देखने को मिली कि अगर कोई साथी अपनी बात रखता है तो उसको बीच में ही टोक दिया जाता है। उसकी बात सुनी ही नहीं जाती है। शोर–शाराबे में ही उसका समय बर्बाद कर दिया जाता है। मैं आप सभी सदस्यों को सदन के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने अपना तमाम तरह का आंकड़ा बजट के लिए सदन के पटल पर रखा है और आप सभी ने उसको सुना है। मैं तो अखबार में छपा एक बड़ा हैडिंग देख रहा था जिसमें लिखा हुआ है कि किसानों और कृषि के विकास का विजन। मैंने इस बजट में जितना ढूंढा उससे मुझे पता चला कि किस प्रकार से कृषि के बजट को पिछले वित्त वर्ष में 1 हजार करोड़ कम यूटीलाईज करने का काम इस सरकार ने किया है, यह कृषि के लिए क्या विजन है? इसी प्रकार से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास के बजट को भी कम करने का काम किया है। शिक्षा मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मैं अपने हल्के के सभी स्कूलों का पूरा ब्यौरा इनके पास भिजवा चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि 1 रुपये का बजट भी उन स्कूलों को अपग्रेड करने और उनकी दशा सुधारने के लिए किया है। इसके विपरीत शिक्षा के बजट को भी कम करने का काम किया है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट के बजट को भी कम किया गया है। पब्लिक हैल्थ के बारे में बात की जाये तो आज हर गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे हल्के के लोग पीने के पानी के नाम पर जहर पी रहे हैं। मैंने मांग की थी कि मेरे हल्के के हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये का बजट दिया जाये। इसी तरह से पूरे हरियाणा में पीने के पानी की किल्लत लोग झेल रहे हैं और सरकार की तरफ से इसका बजट पिछले बजट से भी कम किया गया है। आज सरकार पानी की बड़ी–बड़ी बात करती है और कहती है कि किसानों की आमदनी को डबल किया जायेगा लेकिन आज किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शन जारी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है कि ट्यूबवैल कनैक्शन कब मिलेंगे, किसको मिलेंगे तथा सिनियोरिटी का क्या सिस्टम है और किस प्राथमिकता के आधार पर कनैक्शन

जारी किये जा रहे हैं? अभी हमारे वरिष्ठ साथी डॉ. अभय सिंह जी तीन कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के बारे में अपनी बात कर रहे थे और संसदीय मंत्री जी ने भी किसानों द्वारा तीन कृषि कानूनों के बायकॉट की निन्दा की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों से कहना चाहता हूं और यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बॉर्डर पर किसानों के बीच लेकर चलूंगा और यह वादा करता हूं कि आपकी तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देखेगा। आप वहां पर जा कर किसानों को इन तीन कृषि कानूनों तथा इस बजट के बारे में समझा दें कि किसान का इससे क्या फायदा होने वाला है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको टिकरी बॉर्डर पर लेकर चलूंगा और स्टेज पर बोलने का मौका दूंगा और आप वहां पर धरना दे रहे किसानों को इन तीन कृषि कानूनों के बारे में बतायें कि इसमें किसान का फायदा किस प्रकार से होगा? आप उनको बतायें कि आपकी नीतियां किसान के लिए किस प्रकार से कल्याणकारी हैं? मैं इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी से यह वायदा करना चाहता हूं कि ये मेरे साथ वहां पर चलें। अगर इनकी तरफ कोई आंख उठा कर भी देख ले तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी इनको सही सलामत वहां से निकालूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों द्वारा तीन कृषि कानूनों के बायकॉट की बात की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन कानूनों का बायकॉट क्यों किया जा रहा है? आप लोगों को राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हैं? आप तो झूठी बात पर भी जनता को बहका देते हैं, अगर वास्तव में इन तीन कृषि कानूनों में कुछ अच्छा है और सच्चा है तो आप जनता के बीच चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं। डॉ. अभय सिंह जी जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं और वे बहुत पढ़े–लिखे और बुद्धिमान आदमी हैं। मेरे मन में इनके प्रति बहुत सम्मान है और ये एक समुदाय विशेष के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मुझे इस बात का दुख हुआ है। ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, अगर इनकी जगह कोई अनपढ़ आदमी इस प्रकार की टिप्पणी करता तो मुझे दुख नहीं होता लेकिन ये एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। मुझे इनकी बात का दुख हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ भी कहा है उसका रिकॉर्ड निकलवा लिया जाये मैंनें किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी डॉ. अभय सिंह को कहना चाहता हूं कि जिस समुदाय विशेष के लिए इन्होंने टिप्पणी की है वह वही समुदाय है जिसका ये जिक्र करना चाहते हैं। यह एक निंदनीय टिप्पणी है।

श्री उपाध्यक्ष : कुण्डू साहब, अब वह शब्द हमारी कार्यवाही का कोई हिस्सा नहीं है। आप बजट पर बोलिये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुण्डू : उपाध्यक्ष महोदय, अगर सदन में इस प्रकार का जाति–पाति का सवाल उठेगा तो वह प्रदेश के हित में बहुत गलत है।(शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, बात कार्यवाही की नहीं है। बात यह है कि सत्य क्या है? वह सच्चाई सामने आनी चाहिए। यह बात सफेद झूठ है अभय जी, ने यह बात कही ही नहीं है। बात सच्चाई की है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप कमेटी बना दीजिए। वह कमेटी रिकॉर्डिंग को सुनकर बता देगी कि क्या सच्चाई है। बात सच्चाई की है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने कह रहा हूं कि आप एक कमेटी बना लीजिए। मुझ पर जो ये आरोप लगा रहे हैं अगर मैंने ऐसे कहा हो तो मैं अभी आपको इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। माननीय सदस्य ने क्लीयर कर दिया है। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी?

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार इन्होंने यह कहा है कि हमारे प्रदेश में एक वर्ग ऐसा है जो जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको पढ़कर बता सकती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि उस आन्दोलन में हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल हैं। इसके साथ ही माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि एक समुदाय ऐसा है जो हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या में बहुत बड़ा हिस्सा है और वह तोड़–फोड़ और अशांति में विश्वास रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : किरण जी, आप इस वाक्य का क्या मतलब समझती हैं।(शोर एवं व्यवधान) अखबार की बात नहीं है यह तो विधान सभा की प्रोसिडिंग्ज का हिस्सा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये जानबूझकर बाहर जाने के बहाने तलाश रही

हैं। इनकी जब पोल खुलती है तब ये असत्य बोलती हैं। मैं कहता हूं कि ये * हैं। ये असत्य बोल रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, पढ़े–लिखे व्यक्ति के द्वारा ऐसा शब्द प्रयोग करना गलत है इसलिए * शब्द को कार्यवाही से निकलवाया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह शब्द तो डिलीट हो जाएगा लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं कही उसको बार–बार कहना भी गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री मूल चन्द शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम किसी के दबाव की बात नहीं सुनेंगे। हम विधान सभा में सच्चाई कहेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा में खुल्ला नाच हो रहा है। हम सच्चाई कह रहे हैं। आप सुनने की ताकत रखिये।(शोर एवं व्यवधान) यह कौन करवा रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं? ये हमें डराने का काम करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन असीम जी के बारे में भी इन्होंने ऐसे ही कहा था। उन्होंने जो बात कही थी वह यह कही थी कि जो वहां नारे लगा रहे हैं और जो उनका साथ दे रहे हैं उन्होंने वे शब्द इनके लिए प्रयोग किये थे लेकिन इन लोगों ने उसको किसान बना दिया और किसान बनाकर इन्होंने कह दिया और उसका शोर मचा दिया। जबकि उसमें किसान का कहीं नाम ही नहीं आया था। असीम जी ने किसान का कहीं जिक्र ही नहीं किया। आज फिर दोबारा इन्होनें अभय सिंह जी को कह दिया कि आपने जाति के बारे कुछ कहा है। जब अभय जी कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा हो तो रिजाईन करने को तैयार हूं। चाहे उस रिकॉर्डिंग को कांग्रेस वाले ही चैक कर लें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुण्डू जी, आप कॉन्टीन्यू करें और बजट पर बोलें।

———————————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हुड्डा साहब, उस सारी रिकॉर्डिंग को सुनकर ये कह दें कि मैंने गलत बोला है तो मैं अभी विधान सभा छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इन्हीं पर छोड़ता हूं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, ————(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, अब सारी बात हो गई हैं । प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) यह क्या बात हुई, आप बार–बार खड़े हो जाते हैं?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। इस सारे मामले का जो पूरा निष्कर्ष है और जिस पर डिस्कशन चल रहा है इसमें हर आदमी बड़ी जिम्मेवारी से, अपनी काबिलियत से लोगों का जनाधार लेकर आ रहा है। लोकतंत्र से ही हम सदन में बैठे हैं लेकिन अब हम पोलिटीकल लोगों के सामने क्राईस आ गया और वह क्राईसिस यह है कि ये कृषि कानून हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक लोगों के गले की फांस बन गये हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश को बांटना चाहते हैं, इन्होंने हजारों साल के ताने–बाने को तोड़ने की कोशिश की है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने समाज के लोगों को बांटने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है।(शोर एवं व्यवधान) ये लोग सामाजिक ताने बाने को खराब करने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लीला रामः उपाध्यक्ष महोदय, कादियान जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा पर काम करने वाली पार्टी है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कादियान जी, आप इस हाउस के बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं। कुंडू जी अपनी बात रख रहे हैं आप उन्हें अपनी बात रखने दें। प्लीज आप बैठिए। अब आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जायेगी। लीला राम जी आप भी प्लीज बैठिए। कूंडू जी, अब आप अपनी बात रखें।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, बजट में बड़ी–बड़ी बातें कही गई। कृषि के विकास की बात कही गई, किसान की आय दोगुनी करने के विजन को दिखाने का काम किया गया। मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन से विजन की बात की जा रही है। सरकार अगर विजन दिखाना चाहती थी तो वैट कम करने का काम करना चाहिए था, डीजल–पैट्रोल के दाम कम करके किसान को लाभ पहुंचाने का काम करना चाहिए था। सरकार ने तो सब्सिडी तक को खत्म करने का काम किया है तो फिर किस हिसाब से विजन की बात कही जा रही है। वास्तव में सरकार को कृषि के क्षेत्र में और ज्यादा सब्सिडी

देकर किसान को प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए था तब तो विजन की बात समझ में आती लेकिन सब्सिडी खत्म करके, किसान को खुशहाल करने का आखिरकार कौन सा विजन है? सरकार पिछले साल के कृषि बजट का तो पूरा प्रयोग तक नहीं कर पाई और बात विजन की करते हैं।एक तरफ तो आज प्रदेश का किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर बैठा हुआ है वहीं दूसरी और सत्ता पक्ष की तरफ से कृषि कानूनों के संबंध में बड़ी–बड़ी तारीफ करते हुए बातें कही जा रही हैं। मैं सदन के सभी सत्ता पक्ष के साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी कृषि कानूनों के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हो, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो, किसान को खुशहाल करने की बात करते हो तो क्यों न आप और हम बार्डर पर धरना दे रहे किसानों के पास जायें और उन्हें समझायें। हम आप लोगों को वहां स्टेज पर खड़ा करेंगे और आप किसानों को समझाते हुए किसानों को अपने पक्ष में लाने का काम कीजिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर किसान धरने पर क्यों बैठा है यह जानने की जरूरत है? हर रोज हमारे किसान भाई मर रहे हैं और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि हमारे संसदीय मंत्री जी ने कहा कि वो तो एज्ड हैं इसलिए मर रहे है। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बजुर्ग माता–पिता के मौत पर शोक व्यक्त नहीं किया जाता? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कुंडू जी, आप बजट पर बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कभी नहीं कही। मैंने तो इतना कहा था कि उनकी उम्र ज्यादा थी हर आदमी उम्र के साथ ही तो चलता है इसको इस तरह घुमाने का प्रयास न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ यह भी बजट का ही हिस्सा है।

श्री उपाध्यक्षः नहीं, इस तरह नहीं चलेगा? बजट पर चर्चा हो रही है तो कुंडू साहब आप अपने विषय को बजट पर ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, किसान को खुशहाल करने की बात की जाती है और आरोप लगाये जा रहे हैं कि किसानों को बरगलाकर राजनीति की जा रही है। मैं सदन के माध्यम से सभी मंत्रियों व अन्य सदस्य साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे साथ दिल्ली बार्डर पर धरना दे रहे किसानों के पास चलिए। आपको किसी प्रकार के सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको वहां पर स्टेज पर खड़ा करूंगा। आप लोग खुलकर बोलिए दो घंटे, चार घंटे या दस घंटे किसान को

समझाइये कि ये बिल उनके पक्ष के बिल हैं मैं तब मानूंगा कि आप लोग किसान हितैषी हैं। सदन में खड़ा होकर केवल मात्र अपने सरकार के आंकाओं को खुश करने के लिए जो बातें कहीं जा रही हैं, इनसे किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला है। परसों मुख्यमंत्री जी मेरे रोहतक शहर में आए थे तो पूरे रोहतक को छावनी बना दिया गया था। ऐसा क्यों है? एक तरफ राम राज की बात करते हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा घेरे लेकर चलते हैं। अरे राम–राज में पुलिस और सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं होती है। राम–राज में तो राजा खुले होकर अकेला चल सकता है? यह आप लोग कौन से राम राज की बात कर रहे हो कि जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया तक को इतने भारी दल बल के साथ लोगों के बीच जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के मंत्रियों और सदस्य साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट के माध्यम से पुलिस दल की संख्या बढ़ाने का काम किया जायेगा? निश्चित रूप से सरकार के मंत्रियों व विधायकों को इससे अच्छी सुरक्षा मिलेगी और उनको कोई खतरा नहीं होगा? उपाध्यक्ष महादय, इस प्रावधान के अतिरिक्त बजट में मुझे अन्य कोई विजन नज़र नहीं आया। सरकार द्वारा युवाओं को 75 परसेंट आरक्षण के साथ रोजगार देने की बात कही जाती है। आज प्रदेश बेरोजगारी के क्षेत्र में नम्बर–1 की पायदान पर पहुंच चुका है। आज प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार किस प्रकार से 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे सकेगी?

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत बयानबाजी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री प्रमोद विजः उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने ही वास्तव में रास्ते बंद करवाने का काम किया है। ये लोग किसानों को भड़काने का काम करते हैं। जबरदस्ती देश व प्रदेश को बंद करवाने का काम करते हैं और सदन में उंचा बोलकर गलत बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये लोग किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये लोग असत्य बोलने का करते हैं। इन लोगों ने तो व्यापारियों को बर्बाद करने तक का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं इनको खुद भी तो सड़क पर बैठकर देखना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री लीला रामः उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुण्डू: उपाध्यक्ष महोदय, भाई लीला राम जी जब किसानों के बीच में जायेंगे तो पता चल जायेगा कि कौन गलत बयानबाजी कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः लीला राम जी, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री प्रमोद विजः उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई भी व्यापारियों की बात सदन में नहीं उठाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः विज साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुण्डू: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लीला रामः उपाध्यक्ष महोदय, श्री बलराज कुण्डू सदन में हमारी पार्टी के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कुण्डू साहब, आप अपनी स्पीच एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री बलराज कुण्डू: उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहे हैं। मुझे यह नहीं पता कि सरकार कितने नये उद्योग लेकर आ रही है, जिसमें 75 प्रतिशत युवाओं को नौकरी मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले माननीय सदस्य श्री बिशम्बर सिंह सरकार का बड़ा गुणगान कर रहे थे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार के बारे में काफी लम्बी चौड़ी बातें कही और अपनी वाहवाही लूटी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हर क्षेत्र का निजीकरण करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदेश में जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेगी तो युवाओं को रोजगार कहा से मिलेगा, इस बात की चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए। सरकार बड़े–बड़े दावे तो करती है लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। जिस प्रकार से सरकार प्लानिंग के साथ चल रही है आने वाला समय इस प्रदेश को अंधकार की तरफ ले जायेगा। आज हमारे प्रदेश में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकृति का नियम भी है कि जब कोई चीज आसानी से नहीं मिलती तो उसको छीना जाता है। आज हमारे प्रदेश का युवा भटक रहा है। रोजगार के लिये हमारा युवा दर–दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है और उसे कहीं भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आज प्रदेश की हालत यह हो गई है कि लोगों ने तय

कर रखा है कि जब भी भाजपा और जजपा के सदस्य गांव में आयेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आप लोगों के किये हुए वायदे कहां गये? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कुण्डू साहब, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, कृपया करके बैठ जाइये।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला) (अ.ज.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू: उपाध्यक्ष महोदय, हमें सदन में बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। हमें भी सदन में बराबर बोलने का मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? (विघ्न)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि चेयर ने बोलने का समय पार्टी के सदस्यों की संख्या के मुताबिक तय किया हुआ है। जितने सदस्य सत्ता पक्ष के हैं उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें बोलने का मौका दिया गया है और विपक्ष के जितने सदस्य हैं, उनकी संख्या के हिसाब से उनको बोलने का समय दिया गया है। इसी प्रकार से निर्दलीय विधायकों को भी संख्या के हिसाब से बोलने का समय तय किया हुआ है। यदि सत्ता पक्ष के 10 सदस्यों को बोलने का मौका मिला है तो विपक्ष के सदस्यों को उससे कम बोलने का मौका मिलेगा क्योंकि उनकी संख्या सत्ता पक्ष के सदस्यों से कम है। माननीय सदस्य श्री बलराज कुण्डू चाहते हैं कि वे तो जितनी देर चाहेंगे उतनी देर तक बोलेंगे लेकिन उनकी यह सोच ठीक नहीं है । मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से हाउस चल सकता है ? अगर इस तरीके से हाउस चल सकता हो तो माननीय सदस्य बता दें । उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से हाउस नहीं चल सकता । सदन में सभी वक्ता चेयर के आदेशानुसार मिले हुए समय तक ही बोल सकते हैं लेकिन किसी भी माननीय सदस्य का इस तरह की बात करना ठीक नहीं है । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस का टाइम बढ़ा दीजिए । इसका केवल यही सोल्यूशन है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सदन की एक सिटिंग पहले बढ़ाई थी और एक सिटिंग बी.ए.सी. की सैकेण्ड मीटिंग में बढ़ाई है । इस तरह से बजट सत्र की दो सीटिंग्ज हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं । (शोर एवं व्यवधान) हमने विपक्ष की मांग पर सदन की दो सिटिंग्ज बढ़ा दी हैं लेकिन सदन की सिटिंग्ज बढ़ाने की एक

लिमिट भी होती है । (शोर एवं व्यवधान) अब मैं माननीय सदस्य श्री बलराज कुण्डू के कथन कि "मैं तो जितनी देर चाहूंगा उतनी देर तक बोलूंगा" पर कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री बलराज कुण्डू ने यह बात उस समय जोश–जोश में कह दी होगी । कई बार व्यक्ति जोश–जोश में इस तरह की बात कह देता है लेकिन यह कहना ठीक नहीं होता । (शोर एवं व्यवधान) अगर हर विधायक को चेयर द्वारा बोलने के लिए 6 मिनट दिये जाते हैं तो यह विधायक की टाइम मैनेजमैंट होनी चाहिए कि वह अपनी बात को 6 मिनट में ही पूर्ण कर ले । अगर कोई विधायक अपनी बात को 6 मिनट में पूरा नहीं कर पाता तो यह विधायक का कोई गुण नहीं है । यह तो विधायक का अवगुण है कि वह अपने निर्धारित समय में अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया । यह विधायक की काबिलियत होती है कि वह निर्धारित समय में ही अपनी बात को पूरा कर ले । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा आज की दूसरी सिटिंग में की जाएगी ।

.....

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना सं0 जी.एस.आर.5/कांस्ट/आर्ट.320/2021, दिनांकित 1 मार्च, 2021 ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019–2020 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019–2020 के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019–2020 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष

2019–2020 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 23वीं वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट ।

हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2019–2020 (01.04.2019 से 31.03.2020) के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व सैक्टर पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षण रिपोर्टें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2019–2020 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखे (भाग–1 तथा 2) ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2019–2020 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन आज दिनांक 16 मार्च, 2021 को दोपहर 2:30 (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

1:27 बजे

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार 16 मार्च, 2021, दोपहर 2:30 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित हुई ।)